भारत के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वार अदावत का रुख अख्तियार करता जा रहा है। ट्रंप ने अपने टैरिफ वार से विश्व के देशों की आंखें खोली हैं कि अमेरिका किसी भी देश का हितैषी नहीं है, उसे बस अपने से मतलब है। ट्रंप ने विश्व में अमेरिका के लोकतंत्र के रक्षक, ग्लोबल ऑर्डर के नियंता और महाशक्ति होने के तिलिस्म को भी तोड़ दिया है। अब अमेरिका एक साधारण राष्ट्र है, जो अपने बेशुमार कर्ज से उबरने के लिए संघर्षरत है। भारत पर ट्रंप के 50 फीसदी शुल्क ऐलान के बाद नई दिल्ली ने संयमित रहते हुए वाशिंगटन को दो टूक संदेश दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों व ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाता रहेगा। भारत के लिए अमेरिका ने शुल्कात्याचार से ऐसी संकटपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है कि वह नए वैश्विक ऑर्डर की तरफ सरक रहा है। पीएम मोदी एससीओ की बैठक में चीन जा सकते हैं, चीन ने इसका स्वागत किया है, वहां मोदी व चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग मिल सकते हैं। मोदी व पुतिन ने बात की है, वर्ष के अंत तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। ब्राजील ने मोदी व शी के साथ सहयोग बढ़ाकर टैरिफ वार का हल निकलने की बात की है। यानी ब्रिक्स ध्रुवीकृति हो रहा है। मौजूदा परिस्थिति में भारत के लिए अपनी ट्रेडकूटनीति को आगे बढ़ाने के मौके का विश्लेषण करता आजकल का यह अंक...

भारत के लिए ट्रेडकूटनीति का मौका

विश्लेषण
प्रभात कुमार रॉय
विदेश मामलों के जानकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के विरुद्ध टैरिफ बम प्रयोग करने की जो आक्रामक व्यापारिक रणनीति अख्तियार की है, बाकायदा इसके चलते हुए अमेरिका द्वारा एशिया में भारत सरीखे एक करीबी साझेदार को निश्चित तौर पर गंवाया जा सकता है। रूस-यूक्रेन जंग को समाप्त कराने का ट्रंप का दंभपूर्ण दावा एकदम खोखला साबित हुआ। अतः राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्धरत रूस की अर्थव्यवस्था पर प्रबल प्रहार करने के लिए भारत को भी अपना निशाना बना डाला। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के विरुद्ध ट्रंप द्वारा प्रारम्भ की गई टैरिफ वार में अमेरिका को भारत से भी कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि विश्व पटल पर ट्रंप की विदेश नीति एक बेहद गलत दिशा में प्रस्थान कर चुकी है।

सात अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के विरुद्ध अपने द्वारा ही घोषित किए गए आयात शुल्क को 25 प्रतिशत से दो गुना करके 50 प्रतिशत कर दिया। अधिक वक्त पुराना दौर नहीं था, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तक़रीर पर अमेरिका की संसद में जोरदार तालियां गूंज उठीं थी। एक ऐतिहासिक वक्त इस बात का गवाह रहा कि दो शक्तिशाली ध्रुवों के मध्य फिर से निरंतर विभाजित हो रही दुनिया में भारत वस्तुतः अमेरिका का एक भरोसेमंद पार्टनर बनता जा रहा था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत ही खुले दिल और गर्म जोशी से नरेंद्र मोदी का खैरमक़दम किया था। इस शानदार खैरमक़दम के पीछे जो बाइडेन के दो रणनीतिक मक़सद थे। पहला मक़सद था कि यूक्रेन पर रूस के हमले के मामले में भारत को स्पष्ट कूटनीतिक रुख अख्तियार करने के लिए रजामंद करना। दूसरा मकसद था कि भारत को एक ऐसे गठबंधन में बाकायदा शामिल करना जो कि चीन के निरंतर बढ़ते हुए वैश्विक प्रभाव का बखूबी सामना कर सके।

प्रबल रणनीतिक साझेदार भी रहा भारत

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी दफा राष्ट्रपति पद पर सत्तासीन होने से ठीक पहले तक, भारत यकीनन अमेरिका की दृष्टि में केवल उसका सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार ही नहीं था, वरन् एक प्रबल रणनीतिक साझेदार भी रहा। अमेरिका की नजरों में भारत एशिया में लोकतंत्र का सबसे प्रबल पैरोकार और ताकतवर स्तंभ भी रहा। राष्ट्रपति डब्ल्यू जार्ज बुश से लेकर जो बाइडेन तक अमेरिका के सभी राष्ट्रपतियों द्वारा भारत को रणनीतिक नजरिए से फ्री एंड ओपेन इंडो पैसेफिक के लिए अत्यंत आवश्यक सहयोगी करार दिया गया। अमेरिका और भारत द्वारा एकजुट होकर रक्षा, विज्ञान, तकनीक, नौसेनिक अभ्यास, और क्वाड फ्रंट में एक प्रबल सहयोगी के तौर पर शानदार काम अंजाम दिया। वर्ष 2024 में भारत और अमेरिका द्वारा दस वर्षीय रक्षा रोडमैप का सृजन किया गया और परस्पर व्यापार को 500 अरब डालर तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह संबंध को आगे ले जाने की पहल थी।

अमेरिका गंवा सकता है करीबी साझेदार

अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के विरुद्ध टैरिफ बम प्रयोग करने की जो आक्रामक व्यापारिक रणनीति अख्तियार की है, बाकायदा इसके चलते हुए अमेरिका द्वारा एशिया में भारत सरीखे एक करीबी साझेदार को निश्चित तौर पर गंवाया जा सकता है। दिल्ली स्थित आर्थिक मामलों के एक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव का तथ्यात्मक और तार्किक अनुमान है कि अमेरिका को भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले सामान 50 प्रतिशत तक गिर सकते हैं। इसी वर्ष 2025 के फरवरी महीने में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे, तो उस वक्त भी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों में अनेक अंतरराष्ट्रीय जानकार एक गहरी अंतरविरोधी रणनीतिक उलझन देख रहे थे। अमेरिका के जाने माने अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन का कथन है कि डोनाल्ड ट्रंप का बुनियादी चरित्र एक कुशल व्यापारी का रहा है, ना कि एक प्रखर दूरदर्शी राजनेता का। अतः राष्ट्रपति ट्रंप व्यापारिक संबंधों को कूटनीतिक हथियार को तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मिथ्या दंभ से परिपूर्ण एक घोषणा की थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन और रूस की जंग को खत्म करा देंगे, लेकिन ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ लिए हुए तकरीबन सात महीने व्यतीत हो चुके हैं और रूस-यूक्रेन जंग को समाप्त कराने का उनका दंभपूर्ण दावा एकदम खोखला साबित हुआ। अतः राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्धरत रूस की अर्थव्यवस्था पर प्रबल प्रहार करने के लिए रणनीतिक मित्र राष्ट्र भारत को भी अपना निशाना बना डाला।

दोनों देशों को होगा आर्थिक नुकसान

आर्थिक संकट की इस विकट घड़ी में भारत के लिए आखिरकार आगे का क्या रास्ता है? चीनी कूटनीति के जाने माने विशेषज्ञ हुआंग का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम हमले में भारत को तात्कालिक तौर पर जबरदस्त आर्थिक नुकसान उठाना ही होगा। भारत के विरुद्ध ट्रंप द्वारा प्रारम्भ की गई टैरिफ वार में अमेरिका को भारत से भी कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि विश्व पटल पर ट्रंप की विदेश नीति एक बेहद गलत दिशा में प्रस्थान कर चुकी है। डिप्लोमेट हुआंग को प्रतीत होता है कि अमेरिका की इस आक्रामक रणनीति से भारत और चीन कूटनीतिक तौर पर एकदम निकट आ सकते हैं। कूटनीतिक निकटता के इस प्रस्थान बिंदु से चीन और भारत एक साथ अमेरिका के व्यापारिक दबाव का जमकर मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाएंगे। हुआंग के मुताबिक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिरकत करना तकरीबन तय हो चुका है। चीन स्वागत को तैयार है।

भारत का ट्रंप को ताकतवर पैगाम

एससीओ के शिखर मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग का एक साथ खड़ा होना ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए ताकतवर पैगाम होगा कि चीन की तरह से भारत भी किसी अंतरराष्ट्रीय अमेरिकन धौंस और दबाव के आगे कदाचित नहीं झुकेगा। पीएम मोदी ने न झुकने का ऐलान भी किया है। ट्रंप ने चीन पर प्रारंभ में 50 प्रतिशत टैरिफ आयद किया था। उसके प्रत्युत्तर में चीन द्वारा अमेरिका पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ आयद किया गया तो चीन द्वारा भी अमेरिका पर 100 प्रतिशत टैरिफ आयद किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ आक्रमण का चीन द्वारा ट्रंप को उन्हीं की टैरिफ रणनीति में कड़ा आक्रामक जवाब दिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप अंततः चीन के विरुद्ध एकदम नरम पड़ गए और चीन पर केवल 10 प्रतिशत टैरिफ आयद करने पर आकर टिक गए। उल्लेखनीय है कि अपने विगत कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीन के विरुद्ध ट्रेड वार संचालित करने का ऐलान किया गया था। आखिरकार क्या परिणाम निकला। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में चीन और अधिक ताकतवर होकर उभरा। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी मिथ्या वाणी और दबाव परिवर्तित करने के लिए सारी दुनिया में जाने पहचाने गए हैं। अमेरिका के प्रति चीन का दृष्टिकोण और कार्यनीति से एकदम पृथक रही। अमेरिका द्वारा भारत पर आयद 50 प्रतिशत टैरिफ पर वस्तुतः भारत सरकार की प्रतिक्रिया अत्यंत संतुलित किंतु दो टूक रही है।

टैरिफ का फैसला अनुचित और बेबुनियाद

भारतीय विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ आयद करने के फैसले को एकदम अनुचित और बेबुनियाद करार दिया है। भारत सरकार का कहना है कि भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए तेल आयात करने का निर्णय लेना है। यकीनन भारत ने टैरिफ आयद करने पर अमेरिका को चीन और ब्राजील के लहजे में कदाचित नहीं ललकारा है। भारत सरकार ने अत्यंत शालीन और संतुलित शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत सरकार द्वारा अपने बयान में फिर से दोहरा दिया गया है कि अपने राष्ट्रीय हितों की हिफाजत करने की खातिर सभी आवश्यक फैसले ले लिए जाएंगे। भारत वस्तुतः अमेरिका से कोई कूटनीतिक तकरार में उलझना नहीं चाहता है। विगत दो दशक में निर्मित हुए भारत-अमेरिका संबंधों को कदाचित बिगाड़ना नहीं चाहता है। स्मरण करें कि जब एक ऐतिहासिक दौर में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सैन्य संगठन सेंट्रल ट्रीट्री ऑर्गेनाइजेशन (सेंटो) का सदस्य बनाया, पाक के साथ सैन्य संधि अंजाम देकर भारत के विरुद्ध उसको आधुनिकतम हथियारों से सन्नद किया था। उस दौर में भी भारत ने अमेरिका के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को सदैव सहज और सामान्य बनाए रखा था। भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति का परिपालन करते हुए कोल्ड वार के विकट दौर में भी दो शक्तिशाली सैन्य ध्रुवों के मध्य अपने कूटनीतिक संतुलन को कायम बनाए रखा गया था। सन् 1956 में स्वेज कैनाल सैन्य संकट और सन् 1961 में क्यूबा सैन्य संकट के दौरान विश्वयुद्ध के कगार पर खड़ी दुनिया को बचाने और संकटों का निदान करने के लिए इतिहास भारत के किरदार को स्मरण करेगा। यही कारण था कि 1962 में जब भारत पर चीन ने सैन्य आक्रमण अंजाम दिया था, उस वक्त भारत के पक्ष में सोवियत रूस और अमेरिका एक साथ खड़े हो गए थे। भले ही लोकतांत्रिक भारत में सरकारें तब्दील होती रही हैं किंतु भारत अपनी कसौटी पर खरी उतरी स्वतंत्र विदेश नीति पर निरंतर कायम बना रहा है।

मोदी का चीन दौरा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित चीन दौरा भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति अपने मित्र देशों पर टैरिफ के जरिए केवल कूटनीतिक दबाव कायम करने की कुटिल रणनीति है। रूस-भारत-चीन (आरआईसी) कूटनीतिक त्रिकोण को निर्मित करने का प्रयास निरंतर गति से जारी है। यदि वास्तव में यह प्रस्तावित कूटनीतिक त्रिकोण व्यवहार में आकार ले लेता है तो फिर भारत-चीन के मध्य विद्यमान रहा तनाव समाप्त हो सकता है। पाकिस्तान के प्रति चीन द्वारा अंजाम दिया जा रहा अंध समर्थन खत्म हो सकता है। राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल में भारत के लिए रेड कार्पेट के स्थान पर कांटे बिछा दिए गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को उम्मीद है कि टैरिफ आक्रमण से संभवतया रूस के साथ अपने गहरे व्यापारिक और सामरिक ताल्लुकात को तोड़ लेने के लिए भारत सरकार को विवश कर सकेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप को तनिक भी एहसास नहीं है कि भारतीय जनमानस में रूस के प्रति कितना गहन लगाव विद्यमान रहा है। जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका सहित समस्त पश्चिम कश्मीर पर भारत के विरुद्ध एकजुट था, तब तत्कालीन सोवियत रूस ने भारत के पक्ष में छह दफा वीटो का इस्तेमाल किया था। भारत इसको कैसे भूल सकता है। बांग्लादेश युद्ध के दौर में जब अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो गया था तो केवल रूस की सक्रिय इमदाद और सैन्य समर्थन से भारत ने यह युद्ध निर्णायक तौर पर जीत लिया था। आजादी के बाद भारत की औद्योगिक प्रगति में सोवियत रूस द्वारा अविस्मरणीय योगदान प्रदान किया गया। केंद्र में कोई भी हुकूमत कायम रहे, वह भारतीय जनमानस के रूस के प्रति अगाध सम्मान और स्नेह की उपेक्षा करके अमेरिका के दबाव में रूस से भारत का ऐतिहासिक संबंध तल्ख करने का खतरा नहीं उठा सकती।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

वैश्विक अर्थव्यवस्था हो सकती है प्रभावित

ट्रंप टैरिफ
प्रो. महेश चंद गुप्ता
शिक्षाविद्, विचारक एवं चिंतक

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के कारण अमेरिका लंबे समय से वैश्विक आर्थिक नीतियों पर दबदबा बनाए हुए है। यह दबदबा अब खुलेआम दादागिरी का रूप ले चुका है, खासकर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मनमाने टैरिफ लगाकर देशों को आर्थिक रूप से झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ की घोषणा ने इस दादागिरी को और स्पष्ट कर दिया है। यानी कुल मिलाकर 50 फीसदी का टैरिफ। यह न सिर्फ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार संतुलन पर भी असर डालेगा। ट्रंप को भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर आपत्ति है, जबकि विडंबना यह है कि चीन भी यही कर रहा है और अमेरिका स्वयं रूस से यूरेनियम और खाद खरीद रहा है। यानी सिद्धांत और व्यवहार में अमेरिकी नीति दोहरे मानदंडों से भरी है। सवाल यह है कि भारत क्यों अपने हितों को ताक पर रखकर अमेरिकी दबाव में काम करे? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत पर टैरिफ बढ़ोतरी के एलान के बाद पहली बार एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिक्रिया ने भारत के अडिग रुख को और मजबूती से सामने रखा है। उससे भारत का अडिग रवैया परिलक्षित हो रहा है।

राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता

मोदी ने साफ कह दिया है कि हमारे लिए, हमारे किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। यह वक्तव्य बताता है कि भारत अब वैश्विक दबावों के आगे नतमस्तक नहीं होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (यूएसटीआर) के आंकड़ों के अनुसार भारत-अमेरिका के बीच वार्षिक व्यापार 11 लाख करोड़ रुपये का है। भारत अमेरिका को 7.35 लाख करोड़ रुपये का निर्यात करता है, जिसमें दवाइयां, दूरसंचार उपकरण, जेम्स-एंड-ज्वेलरी, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग उत्पाद और वस्त्र शामिल हैं। वहीं, अमेरिका से भारत 3.46 लाख करोड़ रुपये का आयात करता है, जिसमें कच्चा तेल, कोयला, हीरे, विमान व अंतरिक्ष यानों के पुर्जे शामिल हैं। लेकिन यहां चिंता की बात यह है कि चीन, वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों पर अमेरिका ने इतना भारी शुल्क नहीं लगाया है, जिससे उनके उत्पाद भारतीय उत्पादों की तुलना में अमेरिकी बाजार में सस्ते पड़ेंगे। फिर भी, मोदी सरकार का रवैया दृढ़ है। साठ के दशक में हम गेहूं, दूध के लिए भी अमेरिका पर निर्भर थे लेकिन लगता है ट्रंप ने उन दिनों लिखी गई कोई किताब ताजा मानकर पढ़ ली है। उन्हें आज भी पुराना भारत दिख रहा है, जिसे वह झुकाने की सोच रहे हैं। उन्हें यह समझ में आ जाना चाहिए कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा है।

भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था

भारत आत्मनिर्भर एवं विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थ व्यवस्था है। इसका पूरे विश्व में दबदबा बढ़ रहा है। उद्योग जगत भी इस दबाव को एक

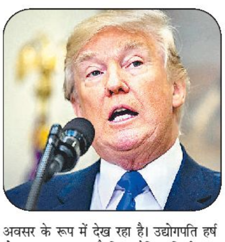

अवसर के रूप में देख रहा है। उद्योगपति हर्ष गोयनका का कहना है कि अमेरिका निर्यात पर टैरिफ लगा सकता है, लेकिन हमारी संप्रभुता पर नहीं। आनंद महिंद्रा ने तो यह भी कहा कि जैसे 1991 के विदेशी मुद्रा संकट ने उदारीकरण की राह खोली थी, वैसे ही यह टैरिफ संकट भी हमें आत्मनिर्भरता की दिशा में गति दे सकता है। ललित मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रंप को 2023 की उस रिपोर्ट की याद दिलाई है, जो अमेरिका की कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने ही जारी की थी। गोल्डमैन सैक्स ने इस रिपोर्ट में कहा था कि भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, जो न केवल जापान और जर्मनी, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। वर्तमान में, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से आगे बढ़ रही है। अमेरिका की आर्थिक दादागिरी कोई नई बात नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही वह वैश्विक आर्थिक नीतियों में अपनी शर्तें थोपता आया है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। चीन पहले ही उसके दबाव में नहीं आ रहा और अब भारत भी साफ संकेत दे रहा है कि उसकी प्राथमिकता अपने राष्ट्रीय हित हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-पाक युद्ध रोकने का श्रेय लेने की अमेरिकी कोशिश को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। यही रुख अब टैरिफ विवाद में भी नजर आ रहा है। मोदी सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है कि मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और इंडिया फर्स्ट जैसी नीतियों के जरिये 2047 तक भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। ऐसे में ट्रंप की टैरिफ राजनीति भारत के आत्मनिर्भरता अभियान को और तेज कर सकती है। धैर्य और संयम के साथ नेतृत्व करना भारत की ताकत है। रामचरितमानस का वह प्रसंग याद आता है जब विभीषण ने युद्ध के समय श्रीराम से कहा कि रावण के पास सब कुछ है, पर आपके पास कुछ नहीं। तब श्रीराम ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति धैर्य, शांति और सहनशीलता है। यही नीति आज भारत के नेतृत्व में झलक रही है, जहां ट्रंप अभिमान में हैं, वहीं भारत दृढ़ता और शांति के साथ आगे बढ़ रहा है। इतिहास ने साबित किया है कि अमेरिका कभी भी भारत का स्थायी मित्र नहीं रहा। ट्रंप की नीतियों का विरोध अमेरिका के भीतर भी हो रहा है। ऐसे में बदलते समीकरण भारत के लिए नए अवसर खोल सकते हैं। ट्रंप भले ही मनमाना रवैया अपनाए हुए हैं पर वह भी फंस रहे हैं। टैरिफ के मुद्दे पर उनका अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। बदले परिदृश्य में नए वैश्विक समीकरण बनने की संभावनाएं हैं। ट्रंप का रुख चीन के साथ भारत के संबंधों को बदल सकता है। पीएम मोदी इस महीने के आखिर में सात सालों के बाद चीन के दौरे पर जा रहे हैं। वह वहां तिआनजिन में आयोजित होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (एससीओ) समिट में शामिल होंगे।

चीन से सुधर सकता है रिश्ता

मोदी का यह चीन दौरा ऐसे समय में होने जा रहा है, जब दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की कोशिशें चल रही हैं। भारत बहुत बड़ा बाजार है, जिसकी चीन को सख्त जरूरत है। भारत में जब भी स्वदेशी का मुद्दा उठता है तो चीन इसे अपने खिलाफ मानता है। स्वदेशी की अवधारणा का चीनी उत्पादों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में चीन क्यों नहीं चाहेगा कि उसके भारत के साथ संबंध मधुर हों। खासकर, तब जब अमेरिका खुद ही भारत से दूरियां बढ़ा रहा है। चीन को भारत के विशाल बाजार की जरूरत है, और अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में दूरी बढ़ने से बीजिंग अपने संबंध सुधारने को उत्सुक होगा। अमेरिका की आर्थिक दादागिरी भले ही अभी भी जारी हो, पर बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत का आत्मविश्वास, अडिग रुख और दूरदर्शी नेतृत्व इसे न सिर्फ झेलने में सक्षम है, बल्कि इसे अपने विकास की सीढ़ी भी बना सकता है।

शुल्क युद्ध से एक हो रहे रूस, चीन व भारत

टैरिफ वार
विकेश कुमार बडोला
वरिष्ठ पत्रकार

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नीतिगत रूप से दिग्भ्रमित प्रतीत हो रहे हैं। पहल वे स्वयं डीप स्टेट के विरुद्ध अमेरिका और दुनिया में एक राजनीतिक विद्रोह छेड़े हुए थे, किंतु अब प्रतीत होता है कि वे भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करने के चंगुल में फंसकर शुल्क युद्ध छेड़े हुए हैं। भारत के विरुद्ध दस-बारह से आरंभ हुआ अमेरिकी शुल्क युद्ध अभी 25 तथा अगस्त बीतने पर 50 प्रतिशत हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार की निर्धारित, प्रमान्य एवं एक दशक से चल रही लगभग संतुलित नीतियों को अमेरिका ने वास्तव में असंतुलित कर दिया है। वस्तु उद्योग, सेवा उद्यम और वस्तु व सेवा की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को धरातल पर अमेरिकी पचास प्रतिशत शुल्क द्वारा वास्तव में कितनी हानि पहुंचेगी, यह तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन पचास प्रतिशत तक शुल्क बढ़ाने के अमेरिकी निर्णय ने भारत से संबंधों की गत एक दशक से बनी समझ, सामंजस्य तथा इसके परिणाम से उत्पन्न लाभ की स्थितियां लगभग समाप्त कर दी हैं। यह एक स्तर की हानि है। जैसे-जैसे समय व्यतीत होगा, दोनों देशों का व्यापार जगत, उपभोक्ता जगत, बैंकिंग, बीमा एवं शेयर बाजार का क्षेत्र भी भिन्न-भिन्न अज्ञात अर्थहानियों का सामना करेंगे।

रूस से तेल खरीद पर नाराज ट्रंप

राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ भारतवासी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कितना ही कोस लें, किंतु भारत पर शुल्क को पचास प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय ट्रंप के व्यक्तिगत अहंकार, हठ एवं श्रेष्ठता के दंभ के आलोक में ही नहीं देखा जाना चाहिए। वास्तव में यह यही इंगित करता है कि अमेरिका को रूस से कच्चा तेल आयात करने के भारत के जिस कार्य व निर्णय से सर्वाधिक समस्या है, उससे भारत को 2022 के बाद अत्यधिक लाभ हुआ है। लगभग पूरे वर्ष तक संपूर्ण यूरोप भारत के उस परिशोधित ईंधन पर ही आश्रित रहा, जो समुद्र या धरती के विशेष स्थानों से उत्खनन के बाद रूस द्वारा सीधे भारत को आयात किया जा रहा था। रूस से कच्चे तेल का आयात और परिशोधन के बाद यूरोप के 27 देशों समेत अनेक अन्य देशों को निर्यात, इस कार्य में भारत सिद्धहस्त हो चुका है। भारत से परिशोधित तेल मंगाने वाले देशों को दुनिया में सबसे निम्न मूल्य पर तेल उपलब्ध हो रहा है। तेल आयात एवं निर्यात आधारित यह पूरा चक्र एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसमें पहला बड़ा लाभार्थी भारत तो दूसरा रूस है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रूस इसी अर्थव्यवस्था के बल पर संपूर्ण यूरोप में पश्चिमी यूरोप का एकमात्र देश था, जिसकी अर्थव्यवस्था यूक्रेन युद्ध के बाद भी सबसे समृद्ध थी।

भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था

भारत ने इस आधार पर पहले फ्रांस, फिर इंग्लैंड और अब जापान को पीछे करके विश्व की चतुर्थ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। अब प्रथम स्थान पर 30.50 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ अमेरिका, 19.23 ट्रिलियन डॉलर के साथ द्वितीय स्थान पर चीन,

4.74 ट्रिलियन डॉलर के साथ तृतीय स्थान पर जर्मनी तथा 4.19 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत चतुर्थ स्थान पर है। भारत की आर्थिक स्थिति को अकस्मात, कोरोना महामारी के कारण अर्थजगत में मंदी के बाद भी, आगे बढ़ने का अवसर तब ही प्राप्त हुआ जब रूस से तेल आयात और फिर आशोधन के बाद उस तेल के निर्यात से भारत के लाभ व आरक्षितियों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। गत चार वर्ष में भारत इस उद्योग एवं व्यापार का एक अनुभवी देश बन चुका है। इस लाभार्जनकारी अनुभव के आधार पर भारत के उज्ज्वल आर्थिक भविष्य की नींव अत्यधिक शक्तिशाली हो चुकी है। रूस के साथ भारत का व्यापारिक एवं सामरिक संबंध हमेशा विश्वास व निष्ठा आधारित रहा है। दोनों देशों ने, विशेषकर रूस ने आसन्न संकटों के समय सदैव भारत का साथ दिया। दोनों देश पारस्परिक सहभागिता, सहकारिता एवं सहयोगपरक दृष्टिकोण के कारण ही कोरोना काल में भी अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं को तेल के कारोबार के कारण संतुलित रख पाए। कारोबार के सफल क्रियान्वयन को तीन-चार वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो अमेरिका को टीस उभरी है। पहले पहल अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोचा कि भारत-अमेरिका के मध्य होने वाले व्यापार अनुबंध में वे व्यापक व लाभकारी अमेरिकी हितों के अनुरूप भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को मनाकर उन्हें इसके लिए सहमत कर लेंगे और ऐसा होने पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था भारतीय उपभोक्ताओं एवं बाजारों के आधार पर अभूतपूर्व लाभ अर्जित करेगी। तब उन्हें भारत व रूस के तेल कारोबार से उभरती नई वैश्विक अर्थव्यवस्था से अधिक समस्या नहीं थी। किंतु पाकिस्तान आधारित अपने सामरिक हितों को भारत के सैन्याक्रमण से हुई हानि के बाद तो अमेरिका के लिए भारत केवल रूस के साथ तेल का कारोबार करके लाभार्जित करने वाले देश के रूप में ही नहीं, अपितु रूस की सहायता से अस्त्रों-शस्त्रों की नवोन्नत प्रौद्योगिकी विकसित करने वाले ऐसे देश के रूप में भी उभरा है, जिसके हथियार अमेरिकी हथियारों से भी श्रेष्ठ सिद्ध हुए हैं। इन्हीं वास्तविक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जब ट्रंप ने अनुभव किया कि मोदी उनके अनुरूप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वे कुंठित हो गये, और परिणामस्वरूप भारत पर अमेरिका की ओर से व्यापारिक शुल्क घोषित कर दिया। अमेरिका द्वारा उत्पन्न इस संकट की स्थिति में चीन ने भारत के आह्वान के बिना ही, स्वप्रेरित होकर भारत का पक्ष लेना आरंभ कर दिया है। उसके देशी-विदेशी मंत्रियों एवं भारत स्थित राजदूत की ओर से अमेरिका पर तरह-तरह के लांछन लगाये जाने लगे हैं। उसने रूस के साथ मिलकर अमेरिकी प्रतिरोध के लिए भारत का संबल बनने के हर संभव संकेत दे दिए हैं। इस वातावरण में भारत की रूस के साथ अनेक स्तरीय शिखर वार्ताएं हो रही हैं। संभावना है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की संक्षिप्त यात्रा पर आएं। संभावना ये भी है कि चीन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएं व शी से मिलें। इन दोनों संभावनाओं को दिनोंदिन बल मिल रहा है।

गुटसापेक्षता से सहमे ट्रंप

उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत विरोधी अपने शुल्क आरोपण अत्याचार की प्रतिक्रिया में आकार ले रही रूस, भारत व चीन (आरआईसी) की गुटसापेक्षता से सहम गये हैं। ब्रिक्स के प्रतिरोध में पहले उन्हें भारत के साथ स्वस्थ मैत्री के आधार पर कुछ यूएस हितैषी कार्य किये जाने की आशा थी भी, किंतु भारत पर शुल्कात्याचार के बाद तो अब अमेरिका तथा अमेरिकी डॉलर के समक्ष रूस, भारत व चीन के गठबंधन के बाद एक नवीन निरुपाय चुनौती खड़ी हो गई है। जिस दिन ये घोषणा हुई कि मोदी दुनिया के सबसे अधिक प्रिय नेता हैं और पहले पांच प्रिय नेताओं में ट्रंप अंतिम हैं, उसी दिन से अमेरिकी राष्ट्रपति किंकर्त्तव्यविमूढ़ होकर भारत विरोधी रणनीतियों को धरातल पर उतारने लगे थे।

इंडियन एक्सप्रेस समूह
जनसत्ता सरोकार
विमर्श
दो
जनसत्ता | 10 अगस्त, 2025

शुल्क और सतर्कता

विदेशी व्यापार, खासकर आयात के प्रति भारत का नजरिया बहुत संकुचित था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन और दक्षिण-दक्षिण सहयोग आदि के बावजूद। हम व्यापार और विदेशी निवेश के मामले में दूसरे देशों से सावधान रहते थे। हमने अपने दरवाजे बंद रखे और चार दशकों तक नहीं खोले। आयात-निर्यात के लिए हमने कठिन नियम बनाए: हर चीज के लिए लाइसेंस और परमिट चाहिए होते थे। अधिकतर आयात और कुछ निर्यात सरकारी निगमों के माध्यम से किए जाते थे। हमारे यहां आयात-निर्यात के लिए एक मुख्य नियंत्रक (चीफ कंट्रोलर आफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स) होता था, जिसके पास पूरे देश में अधिकारियों की एक फौज होती थी, जिनका एकमात्र काम आयात-निर्यात के लिए लाइसेंस जारी करना था। यह एक मुनाफे का कारोबार था। किसी ने भी स्पष्ट सवाल पूछने की कोशिश नहीं की, 'ठीक है, हम समझ सकते हैं कि आयात नियंत्रक क्यों है, लेकिन हमारे यहां निर्यात नियंत्रक क्यों है?'

शुरुआत

इस नीति ने न तो निर्यात को बढ़ावा दिया, न ही निर्यात-उन्मुख विनिर्माण क्षेत्र का निर्माण किया और न ही इससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। इस बीच, भारत के समान स्तर की अर्थव्यवस्था वाले कई देशों ने खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया तथा मुक्त व्यापार की अनुमति दी और समृद्ध हुए।

वर्ष 1990-91 में कई कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय संकट के कगार पर पहुंच गई। भारत को आर्थिक सुधारों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। व्यापार नीति और औद्योगिक नीति में सुधारों तथा वित्तीय अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करने से देश इस संकट से बाहर निकल पाया और अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर अग्रसर हो सकी। हमने शुल्क कम किए (वर्ष 2013 तक औसत 12 फीसद तक कम कर दिया गया) और गैर-शुल्क बाधाओं को भी दूर किया। भारत ने शुल्क और व्यापार को लेकर सामान्य समझौते (जीएटीटी) पर हस्ताक्षर किए और विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। हमने मुक्त व्यापार समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि देश के लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि एक खुली अर्थव्यवस्था हो।

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

> विदेशी संबंधों का पहला सबक यही है कि अगर कोई झुकता है, घुटने टेकता है तो उसे जमीन पर पटकना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती में यह सबक भूल गए। शुक्र है कि प्रतिरोध के संकेत मिल रहे हैं। भारत को अमेरिका को यह बताना होगा कि वह अपने रुख पर अडिग रहेगा, अपने हितों की रक्षा करेगा और निष्पक्ष व्यापार के लिए रास्ते खुले रहेंगे।

बीच का खेल

हालांकि, हैरानी की बात यह है कि जब विकासशील देशों ने खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो पहले से खुली अर्थव्यवस्था वाले देश 'संरक्षणवादी' हो गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका में तो यह सबसे ज्यादा हुआ है।

अस्थायी संकट को टालने के उपाय करने की बात तो समझ में आती है, मगर संरक्षणवाद को आधिकारिक आर्थिक नीति का दर्जा देना अलग बात है। ट्रंप बिना किसी संकोच के उच्च शुल्क, अपारदर्शी गैर-शुल्क उपायों, आयात को हतोत्साहित करने और हर देश के साथ संतुलित व्यापार करने के पक्ष में हैं और अमेरिकी कंपनियों को अमेरिका के बाहर अपने कारखाने न लगाने की धमकी देते हैं। उन्हें लगता है कि 'शुल्क' लगाने से वे मनचाहे परिणाम हासिल कर लेंगे। उन्होंने नीति-निर्माण में अजीबोगरीब मानदंड अपनाएं हैं, जैसे रिपब्लिकन-झुकाव वाले राज्यों को फायदा पहुंचाना, कनाडा के नेताओं के प्रति पूर्वाग्रह, झूठे तर्क जैसे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अब वहां के लोगों के लिए नए रोजगार पैदा नहीं करती है और विचित्र दावे कि उच्च शुल्क का बोझ निर्यातकों पर पड़ेगा, अमेरिकी उपभोक्ताओं पर नहीं। उन्होंने सिद्ध आर्थिक सच्चाइयों जैसे असमानताएं, विशेषज्ञता, श्रम विभाजन और वैश्विक आपूर्ति शृंखला आदि को नकार दिया है।

ट्रंप इस बात पर अड़े हुए हैं कि अमेरिकी कंपनियों को विनिर्माण वापस अमेरिका लाना होगा। वे इसे उत्पादन की स्वदेश वापसी कहते हैं। 'हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू' में 'ब्रिंगिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक टू यूएस इज ईजीयर सेड देन डन' (अमेरिका में विनिर्माण को वापस लाने को कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं) शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ था। इसमें कहा गया था, 'वे दिन अब लद गए, जब एक अकेला एवं पूरी तरह से एकीकृत निर्माता उत्पाद तैयार करने के लिए जरूरी सभी या ज्यादातर कल-पुर्जे और अन्य सामान का डिजाइन तथा निर्माण खुद कर सकता था। तकनीक बहुत जटिल है और एक ही जगह पर सभी जरूरी कौशल को जुटाना नामुमकिन है।' अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने ट्रंप को एक सामान्य समझ वाला व्यक्ति बताया है, जो 21वीं सदी में विनिर्माण की जटिलताओं को न तो समझते हैं और न ही समझ सकते हैं।

ट्रंप ने शुल्क को हथियार बनाकर उन देशों को 'पुरस्कृत' किया है, जो झुक गए (आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया) और उन देशों को 'दंडित' किया है, जो अपने रुख पर कायम हैं (कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, ब्राजील)। भारत तब तक 'अनिश्चित' श्रेणी में था, जब तक कि ट्रंप ने स्टील, एल्युमीनियम और तांबे पर भारी शुल्क नहीं लगा दिया और भारतीय वस्तुओं पर पचास फीसद का आधार शुल्क (कुछ छूट और विलंबित प्रभाव के साथ) लगाया, जिसमें रूसी तेल खरीदने पर जुर्माना भी शामिल था। भारत ने जवाब दिया, 'हम आवश्यक कदम उठाएंगे।'

क्या हो सकता है

जाहिर है, भारत झुक नहीं सकता। न ही भारत को अवज्ञा की जरूरत है। हमें बातचीत के लिए अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से घोषित करनी होगी, चाहे यह प्रक्रिया कितनी भी लंबी और तकलीफदेह क्यों न हो। अर्थशास्त्र के नियम ट्रंप को शुल्क को अपना हथियार बनाने की नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेंगे: उच्च शुल्क से अमेरिका में सैकड़ों वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, अमेरिकी कंपनियां विनिर्माण को स्वदेश लाने से अपने कदम पीछे खींचेंगी, नौकरियां नहीं बढ़ेंगी और अंततः अमेरिकी विकास दर धीमी पड़ जाएगी। वर्ष 2026 के मध्यावधि चुनाव ट्रंप के अहंकार पर लगाम लगा सकते हैं।

इस बीच, भारत सीमित निर्यात उत्पादों और सीमित निर्यात बाजारों वाला एक आलसी निर्यातक नहीं बना रह सकता। हमें निर्यातकों पर धीरे-धीरे बढ़ते नियंत्रणों को खत्म करना होगा। हमें अपने उत्पादों का दायरा बढ़ाना होगा। हमें सक्रिय रूप से नए बाजारों की तलाश करनी होगी, जो 4,500 करोड़ (45 बिलियन) अमेरिकी डालर तक के उत्पादों (2024-25 में अमेरिका को भारत द्वारा निर्यात किए गए गए उत्पादों का मूल्य) को समाहित कर सकें। हमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को उदार बनाना होगा। अल्पावधि में हमें निर्यातकों को प्रोत्साहन देना होगा। हम निर्यातकों की क्षतिपूर्ति के लिए विनिमय दर को समायोजित करने पर विचार कर सकते हैं, भले ही इससे आयात की लागत बढ़ जाएगी। सभी अनावश्यक आयातों पर अस्थायी रूप से अंकुश लगाया जा सकता है।

विदेशी संबंधों का पहला सबक यही है कि अगर कोई झुकता है, घुटने टेकता है तो उसे जमीन पर पटकना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती में यह सबक भूल गए। शुक्र है कि प्रतिरोध के संकेत मिल रहे हैं। भारत को अमेरिका को यह बताना होगा कि वह अपने रुख पर अडिग रहेगा, अपने हितों की रक्षा करेगा, निष्पक्ष व्यापार के लिए रास्ते खुले रहेंगे तथा बातचीत और समझौते के लिए हम तैयार हैं, चाहे प्रक्रिया कितनी भी कठिन क्यों न हो।

खतरे की घंटी

पिछले सप्ताह ऐसा लगा जैसे इस देश के अच्छे दिन कहीं उड़ गए हैं। उत्तराखंड में ऐसी आपदा आई कि पूरे गांव के गांव बह गए नदियों के पानी में। अभी तय नहीं है कि भागीरथी नदी में उफान बादल फटने से आया था या हिमालय की ऊंचाइयों में किसी बर्फीली झील के अचानक पिघल जाने से। कारण से क्या वास्ता, जब इतनी तबाही देखने को मिलती है। मौसम विशेषज्ञों से जब पूछा गया कारण के बारे में, तो उन्होंने साफ कह दिया कि यह सवाल बाद में पूछे जाएंगे, फिलहाल जरूरी है उन लोगों को बचाना, जिनको बचाया जा सकता है। बात है तो सही, लेकिन इस बात को हम सुनते आए हैं जाने कब से। हर साल इस तरह के नजारे दिखते हैं। हर साल सुनते हैं कि पहाड़ों में जो अनियोजित शहर बन गए हैं, उन्होंने पहाड़ों को कमजोर कर दिया है, लेकिन नदियां शांत होने के बाद हम भूल जाते हैं इस बात को।

मेरी पढ़ाई देहरादून में हुई थी, इसलिए मैंने अपनी आंखों से देखे हैं वे दिन जब इन पहाड़ों में छोटे गांवों के अलावा कुछ नहीं होता था। उन गांवों को शहरों में तब्दील होने किसने दिया है जब दुनिया जानती थी उन दिनों से कि पहाड़ों में अगर शहर बनते हैं, तो उनको नियोजित तरीके से बनाना चाहिए ताकि पहाड़ कमजोर न हों। जहां अब चौड़ी सड़कें बन गई हैं उन दिनों कच्ची पगडंडियां और पतली सड़कें हुआ करती थीं। हम स्कूल से अक्सर घूमने जाते थे इन पहाड़ों में और अक्सर पैदल जाया करते थे चढ़ाई करने।

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

> विकास को कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए विकास होता ही गया, लेकिन प्रकृति को ध्यान में रख कर नहीं। हमारे शासकों को जब दिखता है कि अनियोजित निर्माण से उनका निजी लाभ होता है, तो रोकेगा कौन? कुछ ऐसा ही हुआ है और अगर इस बार भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं अनियोजित शहरीकरण रोकने के लिए, तो ऐसी आपदा अगले साल भी आएगी।

विकास को कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए विकास होता ही गया, लेकिन प्रकृति को ध्यान में रख कर नहीं। हमारे शासकों को जब दिखता है कि अनियोजित निर्माण से उनका निजी लाभ होता है, तो रोकेगा कौन? कुछ ऐसा ही हुआ है और अगर इस बार भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं अनियोजित शहरीकरण रोकने के लिए, तो ऐसी आपदा अगले साल भी आएगी। इस बार आपदा पर अगर हमारा ध्यान कम गया है, तो इसलिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा झटका दिया है भारत की अर्थव्यवस्था और हमारी कूटनीति को कि भारत सरकार के ऊंचे गलियारों में कम ही लोग हैं जो समझ सकते हैं फिलहाल कि नरेंद्र मोदी का यह कथित जिगरी दोस्त क्यों अब दोस्त न रहा।

हम अपने राजनीतिक पंडितों की नजरों से देखें, तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमारे प्रधानमंत्री ने क्रोधित किया था जब लोकसभा के अंदर उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि 'आपरेशन सिंदूर' को किसी भी विदेशी नेता के कहने पर नहीं रोका गया था। ट्रंप कई बार कह चुके हैं और आज भी कहते रहते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका। ऐसा कहना जरूरी हो गया है शायद इसलिए कि उनका दावा था कि उनके राष्ट्रपति बनने के चौबीस घंटे बाद वह रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक सकेंगे और इजराइल का गाजा पर हमला भी। ऐसा जब नहीं हुआ, तो नोबेल शांति पुरस्कार का सपना डूबने लगा सो कहना पड़ रहा है कि 'कई और युद्ध मैंने रोके हैं, भारत और पाकिस्तान वाले युद्ध को मैंने रोका है।'

विदेशी पंडितों का कहना कुछ और है। उनका कहना है कि भारत पर 50 फीसद शुल्क लगाए गए हैं रूस को नियंत्रण में लाने के लिए। पुतिन ने जब से यूक्रेन पर हमला बोला है, उन पर आर्थिक पाबंदियां सख्ती से लगाई हैं यूरोप और अमेरिका ने। मगर रूस की अर्थव्यवस्था पर नुकसान इतना नहीं दिखा है क्योंकि भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े ग्राहक बन गए हैं। चीन हमसे कहीं ज्यादा रूसी ऊर्जा खरीदता है, लेकिन ट्रंप जानते हैं कि चीन की आर्थिक शक्ति इतनी है कि उससे पंगा लेना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था पर धावा बोला जाए, ताकि पुतिन की अकड़ थोड़ी कम हो जाए। इसका असर हुआ है, वह इससे पता लगता है कि ट्रंप अब पुतिन से मिलने की बातें कर रहे हैं।

तो हमको क्या करना चाहिए अब? मोदी अगर अपने पुराने दोस्त के दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद करते हैं, तो भारतवासियों की नजर में गिर जाएंगे। देश के आत्मसमान को गहरी चोट लग जाएगी। सो फिलहाल उन्होंने बीच का रास्ता चुना है और ट्रंप के सामने नहीं झुकने का कारण बता रहे हैं 'हमारे किसानों का हित'। ट्रंप के लोगों से जब शुल्क की 'डील' बनाने गए थे वाणिज्य मंत्री और उनके आला अधिकारी तो बातचीत इस पर अटक गई कि हम अपना कृषि क्षेत्र नहीं खोल पाएंगे अमेरिका के लिए। बात ठीक भी है। हमारे किसान ज्यादातर मुश्किल से गुजारा करते हैं पहले से, तो अगर अमेरिकी किसानों के उत्पाद से उनको मुकाबला करना पड़ेगा, तो अवश्य पिट जाएंगे।

लेकिन क्या इस मुसीबत में कोई ऐसे सुधार किए जा सकते हैं कृषि क्षेत्र में, जिनसे हमारे किसानों को नए अवसर मिलें दुनिया के बाजारों में अपना सामान बेचने के लिए? 'कोल्ड स्टोरेज' का निर्माण होता है युद्धस्तर पर तो, जो सत्तर फीसद से ज्यादा फल, सब्जियां और फूल मरते हैं खेतों में, उनको बाजारों तक लाने का एक जरिया मिल जाएगा। विदेशी बाजार भी खुल जाएंगे और हो सकता है हमारे किसानों के जीवन में थोड़ी सी समृद्धि भी आने लगेगी। आर्थिक सुधार और भी हैं जो लटके पड़े हैं बरसों से और जिनके किए जाने से हमारी अर्थव्यवस्था की शक्ल बदल सकती है।

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत में आर्थिक सुधार तब ही किए जाते हैं जब कोई बड़ी समस्या आन पड़ती है। पिछली बार ऐसा ही हुआ था जब लाइसेंस राज समाप्त करने का फैसला किया गया था। अब ट्रंप की मेहरबानी से इंस्पेक्टर राज समाप्त करने का अवसर मिलेगा हमें।

साम्राज्यवाद को चुनौती

हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। यह भविष्य के लिए संकल्प के साथ इतिहास के पिटारे से भूले-बिसरे, उपेक्षित घटनाओं को स्मृति पटल पर लाने का भी अवसर है। इतिहास का फलक जितना बड़ा और अन्वेषी होता है, पीढ़ियों की बुनियाद उतनी ही मजबूत बनती है। भारतीय इतिहास को निष्पक्ष बनाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसका अर्थ है अति सामान्य लोगों ने कैसे उपनिवेशवाद का मुकाबला किया, उसे उजागर करना है। वैसा ही 1921 में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार पर था। इस मुकदमे का महत्त्व दो कारणों से है। पहला, हेडगेवार ने पूर्ण स्वतंत्रता का तर्क रखा था।

उन्नीस अगस्त 1919 को नागपुर न्यायालय के न्यायाधीश ने हेडगेवार पर फैसला सुनाते हुए कहा, 'आपके भाषण में राजद्रोह है। आप अगले एक साल तक भाषण नहीं करेंगे। इसके लिए दो हजार रुपए की जमानत और एक हजार रुपए की गारंटी देनी होगी।' डा हेडगेवार पर असहयोग आंदोलन के दौरान भाषणों से लोगों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भड़काने का आरोप था। मुकदमा धारा-108 के अन्तर्गत था। न्यायाधीश स्मेली के फैसले पर हेडगेवार ने साम्राज्यवाद को ललकारते हुए कहा, 'आप कोई भी फैसला दीजिए। मैं निर्दोष हूं। यह मेरी अंतरात्मा की आवाज है। विदेशी शासकों के अपने पापों का पश्चाताप का समय शीघ्र ही आएगा। मैं जमानत भरने से इनकार करता हूं।'

हेडगेवार द्वारा न्यायाधीश से कहे गए शब्दों में एक वैश्विक लोकतंत्र और समानता की स्थापना थी। उन्होंने कहा, 'इंग्लैंड को परतंत्र करके उनके ऊपर राज करने की हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन जिस तरह इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड में, जर्मनी के लोग जर्मनी में राज करते हैं ,उसी तरह हम हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान का मालिक बन कर राज करना चाहते हैं। अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर रह कर अंग्रेजों के स्थायी गुलाम बन कर रहने की हमारी कतई इच्छा नहीं है।' उनके ये शब्द जितना भारत पर लागू होते थे, उतना ही अफ्रीका पर भी।

हेडगेवार की साम्राज्यवाद-विरोधी आक्रमकता को देखने और सुनने सैकड़ों लोग जिरह के दिन आते थे। वे तब बड़े नेता नहीं थे। न ही बड़ा नाम था। मगर उनमें राष्ट्रभक्ति की चेतना का सूचकांक जरूर बड़ा था। उसका स्वरूप उनकी 'पूर्ण स्वतंत्रता' प्राप्त करने की उद्घोषणा में दिखाई दिया। कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। इसने साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को नया स्वरूप और दिशा देने का काम किया। मगर जमीनी स्तर पर यह भावना पहले से विद्यमान थी। लाहौर प्रस्ताव से आठ वर्ष पूर्व हेडगेवार ने पांच अगस्त 1921 को नागपुर न्यायालय में कहा, 'हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और हम लेकर रहेंगे।'

पूर्ण स्वतंत्रता पर कांग्रेस के 750 शब्दों के प्रस्ताव में भारतीयों के दमन, शोषण और राज करने के अधिकार को छीने जाने का तर्क था। मगर हेडगेवार ने साम्राज्यवाद पर नैतिक प्रश्न खड़ा कर इसकी बुनियाद पर कुल्हाड़ी चलाने का काम किया। उन्होंने सरकारी वकील से पूछा, 'इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे क्या ? क्या ऐसा एक भी कानून है, जिसमें एक देश के लोगों को दूसरे देश के लोगों पर शासन करने का अधिकार मिलता है? हिंदुस्तान के लोगों को पैरों तले कुचल कर और उसके ऊपर शासन करने का अधिकार किसने दिया है? अंग्रेजों का दावा करना कि वे हिंदुस्तान के मालिक हैं, नैतिकता और धर्म का कत्ल करना नहीं है तो और क्या है?'

उनके शब्दों का अभिप्राय सिर्फ भारत की ही स्वतंत्रता नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी, फ्रांसीसी और पुर्तगाली साम्राज्यवादी ताकतों पर सीधा प्रहार था। अखबार 'महाराष्ट्र' ने 24 अगस्त 1921 को 19 अगस्त के फैसले की रपट प्रकाशित की थी। हेडगेवार ने जब जमानत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तब न्यायाधीश ने उन्हें एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। जेल जाने से पूर्व उन्होंने उपस्थित सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए जो कहा वह राष्ट्रभक्ति की मिसाल है, वह यह कि 'राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए कारावास क्या कालेपानी की सजा या फांसी पर चढ़ जाने की अपनी तैयारी होनी चाहिए'

किसी भी आंदोलन और साम्राज्यवाद विरोधी कार्यक्रमों की अपेक्षा अदालत में साम्राज्यवाद को तर्क शून्य कर देना, सजा मिलने के भय

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

संदर्भ

राकेश सिन्हा

> हेडगेवार की साम्राज्यवाद-विरोधी आक्रमकता को देखने और सुनने सैकड़ों लोग जिरह के दिन आते थे। वे तब बड़े नेता नहीं थे। न ही बड़ा नाम था। मगर उनमें राष्ट्रभक्ति की चेतना का सूचकांक जरूर बड़ा था। उसका स्वरूप उनकी 'पूर्ण स्वतंत्रता' प्राप्त करने की उद्घोषणा में दिखा। कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। इसने साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को नया स्वरूप और दिशा देने का काम किया।

को उपजने नहीं देना और न्यायालय की वैधानिकता को चुनौती देना उनका प्रभावी हथियार था। इसलिए हेडगेवार ने जेल से बाहर एकत्रित लोगों के माध्यम से संदेश प्रसारित किया कि 'अपने ऊपर मुकदमा होने पर अपना बचाव नहीं करते हुए खटमल जैसे कुचल कर मरना मुझे उचित नहीं लगता है। अपना पक्ष रखते हुए विरोधियों की कुनीतियों को हमें दुनिया के सामने उजागर जरूर करना चाहिए। वैसा करना देश की सेवा है, नहीं करना आत्मघात जैसा है।'

हेडगेवार से पूर्व और बाद में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 12 मई 1930 को न्यायालय में देशभक्ति का गीत गाकर और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा कर क्रोधित न्यायाधीशों को और भी उत्तेजित कर दिया। 23 जुलाई 1909 में लंदन की अदालत में मदन लाल ढींगरा ने अपने संक्षिप्त वक्तव्य में साम्राज्यवाद को दुत्कारा था। अफ्रीका के घाना में क्वामे नक्रूमा ने और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने इसी मार्ग को अपनाया था। डा हेडगेवार का यह मुकदमा स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के आईने की तरह है। उनकी दृष्टि की तार्किक व्यापकता उन्हें साम्राज्यवादी आंदोलन का एक जीता जागता उदाहरण बना देती है।

नाचती गाती आती धमकी

इन दिनों 'वक्ता' का मतलब 'वक्ता' नहीं, 'श्रोता' तय करते हैं। एक विपक्षी नेता ने शिकायत करनी शुरू कर दी कि एक दिवंगत केंद्रीय मंत्री ने किसान आंदोलन के दौरान मुझे 'धमकी' दी थी। जवाब में दिवंगत मंत्री के बेटे ने कहा कि मेरे पिता का निधन किसान आंदोलन से पहले हो गया था, तब धमकी कैसे! धमकी उनकी आदत न थी! 'धमकीबाजी' के इस दौर में चुनाव आयोग कई दिन कुटा। उसका 'एसआइआर' अभियान भी खूब कुटा। फिर उसके वोटिंग आकंड़े कुटे!

संवाददाता सम्मेलन में विपक्ष के नेताजी ने आयोग द्वारा की गई 'वोट चोरी' के पांच तरीके बताए: मृतक वोटर, दो-दो पहचान पत्र वाले मतदाता, अनुपस्थित मतदाता और एक ही पते पर कई मतदाता..! उधर अपना चुनाव आयोग भी कम नहीं! पहले उसने बिहार के एक विपक्षी नेता जी के दो-दो पहचान पत्र दिखाकर रक्षात्मक माहौल बनाया, लेकिन उनके प्रवक्ता आक्रामक ही बने रहे और प्रत्यारोप लगाते रहे कि आयोग बताए कि इकसठ लाख मतदाता कैसे गायब हुए। ऐसी सूचनाएं हैं कि चुनाव अधिकारियों के घरों में सूचियां बनाई गई हैं।

इसके बाद मामला एकदम 'ताल ठोंक' हो गया। इधर विपक्ष के नेता जी का संवाददाता सम्मेलन खत्म, उधर चुनाव आयोग का विपक्ष के नेता जी को एक नोटिस कि आपने जो आरोप लगाए हैं, वे बेबुनियाद हैं... आप उनके लिए माफी मांगें या सारे आरोपों को हलफनामे के साथ अपने हस्ताक्षरों सहित लिख कर दें। इसी बीच बड़ी अदालत ने विपक्ष के नेता जी द्वारा सेना संबंधी बयान पर कड़ी टिप्पणी की थी।

फिर एक विपक्षी प्रवक्ता ने आतंकवाद की एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश की कि भूख और बेरोजगारी आतंकवादी बनाती है। फिर एक 'फर्जी खबर' फेंकी कि पहलगाम में धर्म पूछ कर नहीं मारा!

बाखबर

सुधीश पचौरी

> जब भारत ने धमकी का करारा जवाब दे दिया कि अपना काम देखो अंकल जी... तो एक एंकर ने कहा कि भारत ने भी आईना दिखा दिया कि सिर्फ हम ही नहीं, आपका देश भी रूस से कारोबार करता है। चीन समेत और बहुत से देश रूस से तेल खरीदते हैं। तब हमारे ऊपर ही आपकी 'नजर-ए-इनायत' क्यों?

बहरहाल, 'धमकी' की दूसरी किस्त अंकल सैम की ओर से ही आई कि मैं इंडिया पर शुल्क और बढ़ाने वाला हूं। फिर शुल्क को पच्चीस फीसद और बढ़ा कर कुल पचास फीसद तक कर दिया और आगे के लिए भी धमकाया कि देखते जाइए... अभी बहुत कुछ होना है..! आजकल अंकल सैम जब भी दिखते हैं, हाथ नचाते दिखते हैं। अंकल की धमकी भी नाचती गाती आती है।

जब भारत ने इस धमकी का करारा जवाब दे दिया कि अपना काम देखो अंकल जी... तो एक एंकर ने कहा कि भारत ने भी आईना दिखा दिया कि सिर्फ हम ही नहीं, आपका देश भी रूस से कारोबार करता है। चीन समेत और बहुत से देश रूस से तेल खरीदते हैं। तब हमारे ऊपर ही आपकी इतनी 'नजर-ए-इनायत' क्यों? एक चर्चक ने कहा कि लगता है ऐसे जवाब को देख अंकल और बौखला गए लगते हैं..!

अंकल की इस नई धमकी को सुनते ही विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया। एक नेता जी ने तुरंत कटाक्ष किया कि यह तो बड़ी 'जादू की झप्पी' देते थे, 'हाउडी मोदी' और 'मेरे दोस्त' कहा करते थे, लेकिन अब 'दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा..!' अंकल सैम अपने विपक्ष के 'हीरो' बनते दिखे। वे कहे कि 'सरेंडर', तो यहां भी कुछ गाने लगते 'सरेंडर-सरेंडर'। वे कहे कि 'भारतीय अर्थव्यवस्था मृत है' तो यहां भी कुछ लोग गाने लगे कि 'भारत की अर्थव्यवस्था बेजान'! लेकिन अगर 'इंडिया' की अर्थव्यवस्था 'बेजान' तो आप इतने खुश क्यों सर जी?

गनीमत रही कि विपक्ष के ही अन्य बड़े नेताओं ने अपने नेता से अलग सुर लगाते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है। विपक्ष के नेता जी कहते रहे कि वे डरपोक हैं... वे दबे हुए हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में खुलेआम कह दिया कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों के हितों के साथ समझौता नहीं करेगा... इसकी जो भी कीमत होगी, वे देंगे... तो भी कहा जाता रहा कि वे सीधे मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं देते। एक चर्चक कहिन कि सर जी! कूटनीति को भी क्या 'सड़क छाप' बनाओगे? मगर कूटनीति और राजनीति की किसे पड़ी है। सबको बस दिखना है और हर पर्दे पर दिखना है।

फिर भी इतना मानना होगा कि इन दिनों खबर बनाने में दो ही आगे हैं- एक अंकल सैम, दूसरे अपने विपक्ष के नेता! लेकिन अफसोस कि उत्तराखंड के धराली और हर्षिल इलाके में बादल फटने से आई भयावह बाढ़ और जनधन की बड़ी हानि की ओर सरकार के अलावा किसी अन्य नेता का अपेक्षित ध्यान नहीं गया।

अंतरात्मा की आवाज सदैव सही राह दिखाती है

आतंकरोधी अभियान

कश्मीर के कुलगाम के घने जंगलों में आतंकियों के खिलाफ सेना एवं सुरक्षा बलों के अभियान का नौवें दिन भी जारी रहना यह बताता है कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों की कमर तोड़ना अभी भी शेष है। यह काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सामान्य बात नहीं कि कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ नौ दिन तक अभियान चलाना पड़े और फिर भी उनका अंत न हो। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कश्मीर के इस सबसे लंबे आतंकरोधी अभियान में हमारे दो सैनिकों को अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। राष्ट्र इनका सदैव ऋणी रहेगा। ऐसे सर्वोच्च बलिदान का स्मरण रखने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आतंकी किसी भी तरह हमारे जवानों को क्षति न पहुंचाने पाएं। कुलगाम के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ जिस दिन अभियान शुरू किया गया, उसी दिन एक आतंकी को मार गिराया गया था। शेष बचे आतंकी इतने दिनों तक सेना एवं सुरक्षा बलों का सामना करने में चाहे जिन कारणों से सफल रहे हों, उनका समूल नाश किया जाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी के साथ यदि यह साबित होता है कि कुलगाम के दुर्गम इलाके में छिपे आतंकी पाकिस्तान से आए थे अथवा इन आतंकियों के पीछे पाकिस्तान का सहयोग और समर्थन है तो सरकार एवं सेना को यह बताने-स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं कि आपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं। पाकिस्तान को नए सिरे से और कठोर सबक सिखाने की तैयारी की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत को विश्व समुदाय को यह भी बताना चाहिए कि आपरेशन सिंदूर के जरिये पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की कठोरतम कार्रवाई के बाद भी उसके होश ठिकाने नहीं आए हैं। पाकिस्तान की हरकतों के लिए परोक्ष रूप से ही सही, विश्व के प्रमुख राष्ट्रों और विशेष रूप से अमेरिका को कठघरे में खड़ा करने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को तो खास तौर पर यह याद दिलाना चाहिए कि वह जिस पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, वह आतंक का गढ़ और भारत के लिए खतरा बना हुआ है। हो सकता है कि ट्रंप जिहादी सोच वाले और पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर को आगे भी अमेरिका बुलाकर भोज कराना पसंद करें, लेकिन भारत को यह तो कहना ही चाहिए कि उसने यह तय कर लिया है कि किसी भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले को युद्ध की तरह देखेगा और प्रतिकार करेगा। यह सही समय है कि भारत सरकार कश्मीर में आतंकियों के खुले-छिपे समर्थकों के खिलाफ भी और अधिक सख्त हो।

गंभीरता से हो जांच

वाल्मीकिनगर थाने के पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों का हमला चिंताजनक है। इससे पूर्व भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। गंभीरता से पड़ताल की जरूरत है कि इसके पीछे का कारण क्या है। विधि व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस और आमजन के बीच अच्छे संबंध जरूरी हैं, पर इस तरह की घटनाओं से इस पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। मामला बालू से जुड़ा है। अधिसंख्य मामलों में देखा गया है कि पुलिस बालू और शराब को लेकर जब भी कोई कार्रवाई करती है तो विरोध हमले तक का रूप ले लेता है। यह सामान्य बात नहीं है। जो लोग इसमें संलिप्त हैं, उनकी ओर से विरोध तो स्वाभाविक है, पर गांवों के आमजन इसमें सहभागी बन जाएं तो मामला गंभीर है। वे कौन हैं, जो ग्रामीणों को अपने प्रभाव में लेकर पुलिस तक पर हमले का दुस्साहस कर रहे। उनकी पहचान जरूरी है, ऐसे लोगों को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, अन्यथा स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। दूसरे पक्ष को भी देखे जाने की जरूरत है कि बालू के खेल में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं तो उनकी भी पहचान जरूरी है, क्योंकि इन मामलों में पूर्व में भी कई पुलिसकर्मी जांच और कार्रवाई के घेरे में आ चुके हैं। इससे उन पुलिसकर्मियों के लिए भी परेशानी उठ खड़ी होती है, जो बालू के अवैध खनन को रोकने का प्रयास करते हैं। बाल्मीकिनगर थाने की पुलिस टीम पर भी हमला इसलिए किया गया कि कागज नहीं दिखा पाने पर बालू को जब्त करने की कार्रवाई की गई थी।

> ग्रामीणों को अपने प्रभाव में लेकर जो लोग पुलिस पर हमले का दुस्साहस कर रहे, उन पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या राहुल गांधी द्वारा शपथपत्र देने से इन्कार करने पर चुनाव आयोग को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए?

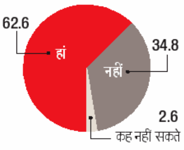

आज का सवाल

क्या आइसीआइसीआइ बैंक द्वारा खाते में न्यूनतम 50 हजार रुपये की राशि रखने का फैसला सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

कूटनीतिक कौशल दिखाने का समय

संजय गुप्त

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विचित्र रवैये को देखते हुए भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी कूटनीतिक चतुराई के जरिये उनसे पार पाने की ठोस रणनीति बनाए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ और अपने मित्र देशों के नेताओं तथा अर्थशास्त्रियों के तर्कों को दरकिनार कर पहले भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया और फिर रूस से तेल खरीदने को तूल देकर और इतने ही प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। अब उन्होंने भारत के साथ होने वाली व्यापार वार्ता से किनारा करने की भी बात कह दी। इस वार्ता के लिए एक अमेरिकी दल इसी माह के अंत में दिल्ली आने वाला था। ट्रंप की चिढ़ का मूल कारण भारत-पाकिस्तान के बीच तथाकथित संघर्ष विराम कराने के उनके दावे पर भारत का सहमत न होना है। वे अपने इस फर्जी दावे को कई बार दोहरा चुके हैं कि आपरेशन सिंदूर इसलिए थमा, क्योंकि उन्होंने दखल दिया था और दोनों देशों को एक बड़े युद्ध से बचाया था। भारत उनके दावे को सही नहीं मान रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में साफ कर दिया कि आपरेशन सिंदूर रोकने के बारे में विश्व के किसी भी नेता ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद ट्रंप और अधिक बौखला गए और अब वे भारत के खिलाफ न केवल टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, बल्कि वर्षों की मेहनत से बनाए गए दोनों देशों के संबंधों को नष्ट करने का भी काम कर रहे हैं। उनके दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन गए थे तो दोनों नेताओं ने यह तय किया था कि एक अंतरिम व्यापार समझौता शीघ्र कर लिया जाएगा, लेकिन अब भारत से चिढ़े हुए ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने भारत को चिढ़ाने के मकसद से ही पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाकर भोज कराया और उनकी तारीफ भी की। इसके बदले में मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की जरूरत जताई। पता नहीं उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलेगा या नहीं, लेकिन यह साफ है कि वे यह पुरस्कार पाने के लिए कुछ ज्यादा ही बेचैन हैं। इसका एक प्रमाण यह है कि वे विभिन्न देशों के छोटे-बड़े टकराव को रोकने के लिए मध्यस्थता करते रहते हैं। वे अपने को शांति का मसीहा साबित करने पर तुले हैं, लेकिन सब जानते हैं कि रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने में नाकाम हैं।

ट्रंप अपनी खीझ निकालने के लिए यह कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन युद्ध में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मदद कर रहा है। ट्रंप भारत को टैरिफ किंग बताकर अपनी शर्तों के हिसाब से व्यापार समझौता करना चाहते हैं और दबाव बनाने के लिए रूस से तेल खरीद को तूल देने में लगे हुए हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि रूस भारत को तेल बेचे बगैर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रख सकता है, क्योंकि वह चीन के साथ अन्य देशों को भी तेल बेच रहा है और यह किसी से छिपा नहीं कि ट्रंप का चीन पर कोई जोर नहीं चल पा रहा है। सच तो यह है कि जो ट्रंप भारत पर रूस से तेल खरीदने का आरोप लगा रहे हैं, वे यह नहीं देखना चाहते कि खुद अमेरिका उससे यूरेनियम और उर्वरक खरीद रहा है। इसके अतिरिक्त तथ्य यह भी है कि यूरोपीय देश रूस से गैस खरीद रहे हैं। इस पर आश्चर्य नहीं कि ट्रंप के दोहरेपन को दुनिया के कई जाने-माने लोगों के साथ-साथ खुद उनके देश के लोग बेनकाब कर रहे हैं। ट्रंप की दोहरी नीतियों और मनमाने फैसलों से पूरा विश्व परेशान है। अब तो विश्व के प्रमुख देश इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि जैसे-तैसे ट्रंप के शेष कार्यकाल को झेलना पड़ेगा।

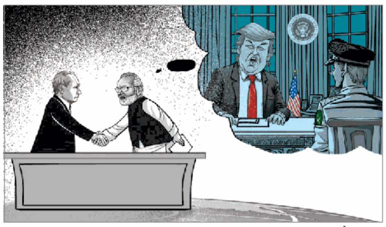

अवधेश राजपूत

अभी ट्रंप ने फार्मा और आइटी कंपनियों को टैरिफ वार से मुक्त कर रखा है, लेकिन भारत को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि उनकी निगाहें इन कंपनियों पर टेढ़ी नहीं होंगी। मनमानापन दिखा रहे ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। अब तो यह भी स्पष्ट हो रहा है कि वे भारत की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति बढ़ती हुई नहीं देखना चाहते और इसीलिए उस पाकिस्तान को पुचकार रहे हैं, जो अमेरिका को कई बार धोखा दे चुका है। ट्रंप के विचित्र रवैये को देखते हुए भारत के लिए आवश्यक है कि वह अपने कूटनीतिक कौशल के जरिये उनसे पार पाने की और कारगर रणनीति बनाए। अच्छा होता कि भारत दूसरी बार राष्ट्रपति बने ट्रंप के बदले रवैये को देखते हुए कूटनीतिक चतुराई दिखाता और उनके अहं को तुष्ट करने के बारे में सोचता। तब शायद ट्रंप इतना गर्जन-तर्जन नहीं कर रहे होते और अमेरिका से अंतरिम व्यापार समझौता भी हो गया होता। इस पर विचार होना चाहिए कि क्या ट्रंप के मामले में आवश्यक कूटनीतिक चतुराई नहीं दिखाई जा सकी? अब तो कूटनीतिक कौशल पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही भारत को अपने उद्योगों की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने पर भी जोर देना होगा।

ट्रंप के भारत विरोधी रवैये ने हमारे समक्ष एक अवसर खड़ा कर दिया है। आगे चलकर ट्रंप के टैरिफ युद्ध की चपेट में कुछ और देश भी आ सकते हैं। जो भी हो, भारत के लिए यही उचित है कि वह यह स्पष्ट करता रहे कि वह उनके आगे नहीं झुकेगा। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका के कृषि और डेरी उत्पादों के लिए अपने बाजार खोल दे। इसके लिए मोदी सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेरी उत्पादकों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इन वर्गों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई कीमत चुकानी पड़ी, तो वे इसके लिए तैयार हैं। यह साफ नहीं कि व्यक्तिगत नुकसान से उनका आशय क्या है, लेकिन इसकी अनदेखी न की जाए कि अमेरिका दूसरे देशों के चुनावों में दखल देता रहा है। अमेरिका से सावधान रहने के साथ भारत को अपने किसानों के हितों की रक्षा करनी होगी और इस पर भी ध्यान देना होगा कि भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए? इस मामले में सबसे बड़ी विडंबना कुछ किसान नेताओं का किसान हित विरोधी रवैया है। वे जानबूझकर कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण में रोड़ा अटका रहे हैं।

response@jagran.com

भोजन पर नसीहत के पकवान

हास्य-व्यंग्य

अभिजित दुबे

> ट्रंप को मुनीर से कहना पड़ा कि भाषा की समझ अगर तुम लोगों को होती तो पूर्वी पाकिस्तान तुमसे अलग ही क्यों होता

एक समय था जब इंटरनेट मीडिया मंचों पर डोनाल्ड ट्रंप को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इससे सबक लेते हुए उन्होंने 'ट्रुथ' नाम से अपना खुद का इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म बना लिया। इसका नाम भले ही ट्रुथ हो, लेकिन इसी पर रोजाना झूठ की चौपाल लगती है। इसी मंच पर वह अपने आपको घनघोर ज्ञानी साबित करते रहते हैं। हालांकि उनका ज्ञान भी चिराग तले अंधेरे जैसा है कि उन्हें यह पता है कि भारत पुराने दोस्त रूस से कौनसा पदार्थ कितनी मात्रा में खरीद रहा है, लेकिन इसकी कोई भनक नहीं कि उनका अपना देश रूस से क्या-क्या और कितना खरीद रहा है। विश्वशांति के हिमायती के रूप में नोबेल पर रोज का दावा आम बात हो गई है। 'ट्रुथ' पर ट्रंप कभी टैरिफ के लिए टरटराते तो कभी ब्रिक्स देशों को धमकाते हैं। शेयर मार्केट के सूचकांक के बदलने से पहले वह टैरिफ की नई दर घोषित कर देते हैं। कभी 'बिग ब्यूटीफुल बिल' पर अपनी ही पीठ थपथपाते हैं तो कभी अपने पूर्ववर्ती को सारी अराजकता का जिम्मेदार ठहरा देते हैं।

एक समय पाकिस्तान को फटकारने वाले ट्रंप का मन ऐसा बदला कि अब उसे ही पुचकारने लगे हैं। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान के अघोषित मुखिया और फेल्ड मार्शल, माफ कीजिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को न्योता भेजा। खैर, भोजन के बाद मुनीर ने ट्रंप के समक्ष 90 डिग्री के कोण पर झुकते हुए कहा-''डिनर के लिए आभार। यह बताएं नेवता कहां लिखवाना है।'' ट्रंप ने पूछा-''नेवता क्या होता है?'' जवाब मिला, ''नेवता एक प्राचीन प्रथा है जो अविभाजित हिंदुस्तान में सदियों से चली आ रही है। हम लोग जब शादी-विवाह में दोस्त या हित-नातेदार के यहां जाते हैं तो उपहारस्वरूप कुछ राशि भेंट देते हैं, जिसे नेवता कहा जाता है।'' ''अरे कंगाल देश तू हमें क्या नेवता देगा! बलूच संभल नहीं रहे तुमसे, आतंक की फैक्ट्री चलाने की औकात भी रही नहीं, आए हो हमें नेवता देने।'' ट्रंप अपनी शैली में बड़बड़ाए।

मुनीर ने जी-हुजूरी करते हुए फिर पूछा, 'सर, कृपया बताएं नेवता कहां लिखवाना है?'' ट्रंप ने फटाक से मुनीर के गाल पर एक रसीद किया। मुनीर ने दर्द से कराहते हुए पूछ लिया, ''आपने ऐसा क्यों किया?'' ट्रंपः ''चलो दूसरा गाल आगे करो।'' मुनीरः ''दूसरा गाल क्यों?'' ट्रंपः ''तुम तो गांधी की संतान हो न!'' मुनीरः ''नहीं-नहीं मैं जिन्ना की औलाद हूं।'' ट्रंपः ''अच्छा तभी 1947 में जो कटोरा हाथ में थामा था, वह आज तक नहीं छोड़ पाए। पूरी दुनिया में कटोरा लिए घूमते फिरते हो।'' मुनीरः ''आप हमारे दुश्मन मुल्क की जुबान क्यों बोल रहे हैं हुजूर? हमारी वफादारी का यह इनाम।'' ट्रंपः ''यह जुबान नहीं, भाषा है मेरे प्यारे मुनीर। मेरी जुबान तो अमेरिका को फिर से महान बनाने में लगी हुई है। वैसे भाषा की समझ अगर तुम लोगों को होती तो पूर्वी पाकिस्तान तुमसे अलग ही क्यों होता!'' मुनीरः 'हमारी दुखती रग पर क्यों हाथ रख रहे हैं माई-बाप!'' ट्रंपः ''वैसे थोड़ी देर पहले तुमने जिन्ना को अपना बाप बताया, अब मुझे! माजरा क्या है!'' मुनीरः 'हुजूर घर में खाने को आटा नहीं है। पिछले लोन से मिली हुई राशि तो हम कबकी डकार चुके। अब कुछ नया लोन का जुगाड़ करवा दो ताकि दाल-रोटी चलती रहे।'' ऐसी मिजाजपुर्सी से खुश होकर ट्रंप ने खैरात दे डाली और मुनीर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की तरह लड़खड़ा गए।

पाकिस्तानी मीडिया में खबर छपी कि आर्थिक सहायता मिलने के आश्वासन पर मुनीर मारे खुशी के उछल पड़े। खुशी संभल नहीं पाई तो फिर लड़खड़ाकर गिर गए। उधर गिरे हुए मुनीर को उठाने के लिए ट्रंप साहब ने उसकी ओर 'दोस्ती का बूट' बढ़ा दिया, जिसे मुनीर ने पलक झपकने से पहले लपक भी लिया। कुल मिलाकर, भोजन पर नसीहत के नाना-प्रकार के पकवान परोसे गए और मुनीर ने सब पचा भी लिए। यह दर्शाता है कि उनका हाजमा कितना दुरुस्त है।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य

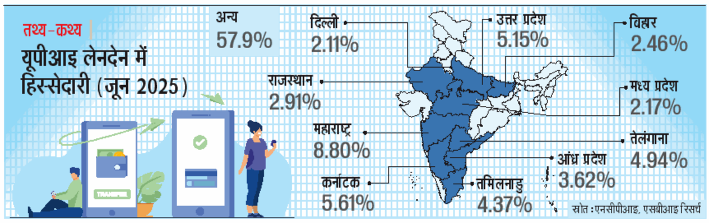

ऊर्जा

वर्तमान की आधारशिला

सामान्यतः लोग अतीत की गलतियों और भावी आशंकाओं के लिए दुखी रहते हैं। जबकि भूत कभी लौटता नहीं और भविष्य कोई जानता नहीं। इसलिए विद्वान वर्तमान में जीने की प्रेरणा देते हैं। दार्शनिक ओशो कहते हैं कि वर्तमान क्षण ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या है। भूत-भविष्य दुख देने वाले हैं। मानव के अतिरिक्त अन्य जीवों को इनका संज्ञान भी नहीं, इसलिए दुखी नहीं होते। सच है कि अतीत की पीड़ा और उज्ज्वल भविष्य की चाहत वर्तमान का सुख छीन लेती है, पर यह भी सच है कि यही वर्तमान के आधार बनते हैं। भूतकाल की त्रुटियां और भविष्य की चुनौतियां वर्तमान को संवारने का काम करती हैं। यदि ऐसा न होता तो आज भी हम पाषाणकाल में जी रहे होते। विकास की यह अकल्पनीय यात्रा इन्हीं की प्रेरणा से संभव हुई है। ये दोनों मनुष्य के सबसे अच्छे गुरु हैं, जो सदा संग रहकर वर्तमान का निर्धारण करते हैं। इनसे शिक्षा न लेना अपने ही दुर्भाग्य को आमंत्रित करना है।

हमारे ऋषि-मुनियों ने तीनों कालों को हथेली पर रखे आंवले के समान देखकर और अनुभव से जांच-परखकर वर्तमान की जो बुनियाद रखी थी, वह सह-अस्तित्व पर केंद्रित होने से समाज के लिए संजीवनी थी। देश-काल एवं भेद निरपेक्ष होने से वह आज भी समाज में एकता शक्ति को बढ़ाकर सुख-शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। हालांकि दुर्भाग्य है कि हम देश में भाषा, जाति, पंथ और मजहब के नाम पर निरर्थक भेद-भाव बढ़ाकर संघर्ष को जन्म देते हैं। दूसरी ओर, अतीत की युद्ध विभीषिकाओं के परिणाम देख चुकी दुनिया उनसे सीख लिए बिना तीसरे विश्व युद्ध की ओर अग्रसर है। यह चिंता का विषय है। वस्तुतः जो समाज अतीत की गलतियों से सीख लेकर अपनी क्रियाविधियों में परिमार्जन नहीं करता, उसका न वर्तमान मंगलकारी होता है, न भविष्य। इनसे अभिप्रेरित होकर अपने लिए सुखद वर्तमान और भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करें।

डा. सत्यप्रकाश मिश्र

लिखत-पढ़त

राजनीतिक दलों की आक्रामकता के बावजूद सामान्यतया चुप्पी साधे रहने वाले चुनाव आयोग ने अब तय कर लिया है कि अपनी साख बचानी है तो मुखर भी होना पड़ेगा और सब कुछ लिखत-पढ़त में भी होगा। एकतरफा कुछ भी नहीं चलने दिया जाएगा। हाल में चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पोस्ट पर 'भ्रामक' का ठप्पा लगाकर अपना जवाब सार्वजनिक कर दिया। कर्नाटक में कांग्रेस नेता चुनाव आयोग के दफ्तर गए और कोई दस्तावेज नहीं दिया तो वह भी लिखत-पढ़त में सार्वजनिक कर दिया और बता दिया कि उन्होंने शपथपत्र तो दूर, दस्तावेज ही नहीं दिया, तो जांच कैसे हो। वैसे भी सरकारी कामकाज औपचारिक और नियम-कायदे के अनुसार ही होते हैं। यानी अब जब भी राहुल गांधी आरोप लगाएंगे तो चुनाव आयोग उनसे कहेगा कि आकर हमसे भी तो मिलें, हमें लिखित शिकायत भी दें। साफ है कि अब आने वाले समय में इंटरनेट मीडिया पर भी चुनाव आयोग की सक्रियता काफी दिखेगी।

राजरंग

रहस्यमय चुप्पी

सरकारी नीतियों और वैश्विक उथल-पुथल को लेकर बढ़-चढ़कर बोलने वाले भारतीय उद्योग चैंबर्स की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ पर चुप्पी की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। सरकार की ओर से अमेरिका के 50 प्रतिशत टैरिफ के खिलाफ खुलकर बयान आ रहे हैं, लेकिन उद्योग चैंबर्स की ओर से इसके खिलाफ अभी तक एक भी बयान नहीं आया है। आनंद महिंद्रा और हर्ष गोयनका जैसे इक्का-दुक्का उद्योगपतियों ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रिया जरूर दी है। इनमें से कई उद्योग चैंबर्स के अमेरिकी उद्योग चैंबर्स के साथ सहयोग का समझौता भी है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ वार के खिलाफ उनमें कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। चर्चा है कि कहीं इस रहस्यमय चुप्पी की वजह उद्योग चैंबर्स से संबंधित उद्योगपतियों के अमेरिका और यूरोपीय देशों से जुड़े आर्थिक हित तो नहीं हैं।

अमेरिका में इंतजार

ट्रंप की नीतियों से सिर्फ विदेशी सरकारें ही परेशान नहीं हैं। पिछले दिनों जब कारोबारी समझौते को लेकर भारतीय अधिकारियों की वाशिंगटन में बैठक हुई तो वहां उपस्थित एक अधिकारी ने काफी पीने के दौरान जो बातें कहीं वे तो अमेरिका के भीतर की बेचैनी को दर्शाती हैं। वार्ता की शुरुआत में ही यह साफ हो गया था कि बात बनने वाली नहीं है। इस बीच ब्रेक में भारतीय दल के एक प्रतिनिधि ने अमेरिकी प्रतिनिधि से अनौपचारिक तौर पर कहा कि जब बात नहीं बनेगी तो हम इंतजार करेंगे। इस पर अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि 'कोई बात नहीं। हमें भी साढ़े तीन साल इंतजार करना है, आप भी करो।' बताने की जरूरत नहीं कि जनवरी 2025 में ट्रंप ने दोबारा सत्ता संभाली है और उनका कार्यकाल दिसंबर 2028 तक है।

लालू नाम केवलम

पार्टी और परिवार से अलग-थलग पड़ने के बाद तेज प्रताप यादव ने गाड़ी का झंडा और टोपी का रंग तो बदल लिया, लेकिन लालू यादव पर अधिकार जताने की रफ्तार बढ़ा दी है। अब हर मंच पर और हर मुलाकात में वह 'लालू पुत्र' होने का अहसास कराना नहीं भूलते हैं। विधानसभा चुनाव सिर पर है और तेज प्रताप जानते हैं कि अपने बूते मैदान साधना आसान नहीं होगा। परिवार ने साथ नहीं दिया तो राह मुश्किल है। ऐसे में लालू यादव का नाम उनके लिए भावनात्मक जुड़ाव से ज्यादा रणनीतिक जरूरत बन गया है। इसलिए अब हर महफिल में तेज प्रताप को बताना पड़ता है कि 'मैं ही हूं लालू का असली वारिस!' अब वक्त बताएगा कि लालू की माला जपकर तेज प्रताप अपने आसन्न संकट से कैसे निजात पाते हैं।

X पोस्ट

वायुसेना प्रमुख ने पूरा ब्योरा पेश किया कि आपरेशन सिंदूर के दौरान हमने कितने पाकिस्तानी विमान मार गिराए। अब पाकिस्तान के 'फेल्ड मार्शल' दुनिया भर में दौरे करके अपने सहयोगियों के कंधे पर सिर रखकर रोना-गाना कर सकते हैं और मुगालते में रहने वाली उनकी जनता अपनी फर्जी जीत का जश्न मनाती रहे।

प्रियंका चतुर्वेदी@priyankac19

प्रश्न है कि क्या आप डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास करेंगे या भारतीय वायु सेना के मुखिया की बात पर? यह निर्भर करता है कि आपकी परवरिश किस हिसाब से हुई है। अपनी बात करूं तो मुझे हमेशा अपने सैन्य बलों पर भरोसा रहेगा।

ब्रजमोहन सिंह@brajjourno

जापानी बुलेट ट्रेन अपने गंतव्य पर 35 सेकेंड देरी से पहुंची तो परिचालक ने सभी यात्रियों से माफी मांगते हुए उनका किराया वापस कर दिया। जापान असल में अनुशासन और प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करने वाला ऐसा देश है, जिससे हम सभी को सीखना चाहिए।

उदय कोटक@udaykotak

जनपथ

तिकड़ी आए साथ तो बन जाएगी बात,
भारत, चीन औ रूस मिल करें नई शुरुआत।
करें नई शुरुआत भूल कर वाद पुराने,
तो ताऊ की अक्ल तुरत लग जाय ठिकाने!
सबको देते धौंस बहुत है आदत बिगड़ी,
देगी इन्हें सुधार तीन देशों की तिकड़ी!!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर. बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 120

****

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

दैनिक जागरण
अंतरात्मा की आवाज सदैव सही राह दिखाती है

आतंकरोधी अभियान

कश्मीर के कुलगाम के घने जंगलों में आतंकियों के खिलाफ सेना एवं सुरक्षा बलों के अभियान का नौवें दिन भी जारी रहना यह बताता है कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों की कमर तोड़ना अभी भी शेष है। यह काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सामान्य बात नहीं कि कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ नौ दिन तक अभियान चलाना पड़े और फिर भी उनका अंत न हो। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कश्मीर के इस सबसे लंबे आतंकरोधी अभियान में हमारे दो सैनिकों को अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। राष्ट्र इनका सदैव ऋणी रहेगा। ऐसे सर्वोच्च बलिदान का स्मरण रखने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आतंकी किसी भी तरह हमारे जवानों को क्षति न पहुंचाने पाएं। कुलगाम के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ जिस दिन अभियान शुरू किया गया, उसी दिन एक आतंकी को मार गिराया गया था। शेष बचे आतंकी इतने दिनों तक सेना एवं सुरक्षा बलों का सामना करने में चाहे जिन कारणों से सफल रहे हों, उनका समूल नाश किया जाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी के साथ यदि यह साबित होता है कि कुलगाम के दुर्गम इलाके में छिपे आतंकी पाकिस्तान से आए थे अथवा इन आतंकियों के पीछे पाकिस्तान का सहयोग और समर्थन है तो सरकार एवं सेना को यह बताने-स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं कि आपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं। पाकिस्तान को नए सिरे से और कठोर सबक सिखाने की तैयारी की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत को विश्व समुदाय को यह भी बताना चाहिए कि आपरेशन सिंदूर के जरिये पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की कठोरतम कार्रवाई के बाद भी उसके होश ठिकाने नहीं आए हैं।

पाकिस्तान की हरकतों के लिए परोक्ष रूप से ही सही, विश्व के प्रमुख राष्ट्रों और विशेष रूप से अमेरिका को कठघरे में खड़ा करने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को तो खास तौर पर यह याद दिलाना चाहिए कि वह जिस पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, वह आतंक का गढ़ और भारत के लिए खतरा बना हुआ है। हो सकता है कि ट्रंप जिहादी सोच वाले और पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर को आगे भी अमेरिका बुलाकर भोज कराना पसंद करें, लेकिन भारत को यह तो कहना ही चाहिए कि उसने यह तय कर लिया है कि किसी भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले को युद्ध की तरह देखेगा और प्रतिकार करेगा। यह सही समय है कि भारत सरकार कश्मीर में आतंकियों के खुले-छिपे समर्थकों के खिलाफ भी और अधिक सख्त हो।

सार्थक पहल

बीते माह राजस्थान में एक विद्यालय भवन के ध्वस्त होने और उसमें कई छात्रों के मारे जाने के बाद से देश के अनेक राज्यों में स्कूली भवनों की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के स्कूल भवनों की स्थिति का आकलन भी किया जा रहा है। अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें कई विद्यालयों की स्थिति जर्जर मिली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा भी कि है कि जहां विद्यालय भवन खराब स्थिति में हैं, वहां बच्चों को नहीं पढ़ाया जाए। उन भवनों को ध्वस्त करते हुए नए भवन बनाए जाएं। मुख्यमंत्री ने सबसे सहयोग की अपील की है। 'दैनिक जागरण' ने भी अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए स्कूल भवनों की स्थिति को शासन के समक्ष लाने के उद्देश्य से समाचारीय अभियान चलाया है। इस सबका असर भी दिख रहा है। हरदोई में चीनी मिलों ने स्कूलों को गोद लेने की घोषणा की है। आगे बढ़कर कुछ विद्यालयों को आदर्श बनाने की पहल भी अधिकारियों ने शुरू की है। विधायकों के साथ ही लखनऊ में तो वार्ड पार्षदों ने भी स्कूल-अध्ययन कक्ष बनवाने में योगदान की घोषणा की है। केवल सरकारी मदद से संपूर्ण परिवर्तन की आस हमेशा नहीं की जा सकती है। ऐसे में सामुदायिक पहल भी आवश्यक है, जो प्रभावी हो सकती है। हाल ही में राजस्थान में हुए स्कूल हादसे में सात मासूमों की मौत ने देश को झकझोरा है। समूचा प्रशासनिक तंत्र इस ओर जागरूक हो रहा है। ऐसे में सरकार ने सहायता प्राप्त स्कूलों की मरम्मत के लिए भी 50 साल पुराने होने की बाध्यता में बदलाव किया है। ऐसे तीन हजार स्कूलों के भवन जर्जर हैं। निश्चय ही समवेत प्रयास रंग लाएगा और नन्हे-मुन्नों को सुरक्षित छत मिल सकेगी।

> नौनिहालों की पढ़ाई को सुरक्षित बनाने में सरकार के साथ ही सामुदायिक पहल भी आवश्यक है

कूटनीतिक कौशल दिखाने का समय

संजय गुप्त

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विचित्र रवैये को देखते हुए भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी कूटनीतिक चतुराई के जरिये उनसे पार पाने की ठोस रणनीति बनाए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ और अपने मित्र देशों के नेताओं तथा अर्थशास्त्रियों के तर्कों को दरकिनार कर पहले भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया और फिर रूस से तेल खरीदने को तूल देकर और इतने ही प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। अब उन्होंने भारत के साथ होने वाली व्यापार वार्ता से किनारा करने की भी बात कह दी। इस वार्ता के लिए एक अमेरिकी दल इसी माह के अंत में दिल्ली आने वाला था। ट्रंप की चिढ़ का मूल कारण भारत-पाकिस्तान के बीच तथाकथित संघर्ष विराम कराने के उनके दावे पर भारत का सहमत न होना है। वे अपने इस फर्जी दावे को कई बार दोहरा चुके हैं कि आपरेशन सिंदूर इसलिए थमा, क्योंकि उन्होंने दखल दिया था और दोनों देशों को एक बड़े युद्ध से बचाया था। भारत उनके दावे को सही नहीं मान रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में साफ कर दिया कि आपरेशन सिंदूर रोकने के बारे में विश्व के किसी भी नेता ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद ट्रंप और अधिक बौखला गए और अब वे भारत के खिलाफ न केवल टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, बल्कि वर्षों की मेहनत से बनाए गए दोनों देशों के संबंधों को नष्ट करने का भी काम कर रहे हैं। उनके दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन गए थे तो दोनों नेताओं ने यह तय किया था कि एक अंतरिम व्यापार समझौता शीघ्र कर लिया जाएगा, लेकिन अब भारत से चिढ़े हुए ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने भारत को चिढ़ाने के मकसद से ही पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाकर भोज कराया और उनकी तारीफ भी की। इसके बदले में मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की जरूरत जताई। पता नहीं उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलेगा या नहीं, लेकिन यह साफ है कि वे यह पुरस्कार पाने के लिए कुछ ज्यादा ही बेचैन हैं। इसका एक प्रमाण यह है कि वे विभिन्न देशों के छोटे-बड़े टकराव को रोकने के लिए मध्यस्थता करते रहते हैं। वे अपने को शांति का मसीहा साबित करने पर तुले हैं, लेकिन सब जानते हैं कि रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने में नाकाम हैं।

ट्रंप अपनी खीझ निकालने के लिए यह कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन युद्ध में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मदद कर रहा है। ट्रंप भारत को टैरिफ किंग बताकर अपनी शर्तों के हिसाब से व्यापार समझौता करना चाहते हैं और दबाव बनाने के लिए रूस से तेल खरीद को तूल देने में लगे हुए हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि रूस भारत को तेल बेचे बगैर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रख सकता है, क्योंकि वह चीन के साथ अन्य देशों को भी तेल बेच रहा है और यह किसी से छिपा नहीं कि ट्रंप का चीन पर कोई जोर नहीं चल पा रहा है। सच तो यह है कि जो ट्रंप भारत पर रूस से तेल खरीदने का आरोप लगा रहे हैं, वे यह नहीं देखना चाहते कि खुद अमेरिका उससे यूरेनियम और उर्वरक खरीद रहा है। इसके अतिरिक्त तथ्य यह भी है कि यूरोपीय देश रूस से गैस खरीद रहे हैं। इस पर आश्चर्य नहीं कि ट्रंप के दोहरेपन को दुनिया के कई जाने-माने लोगों के साथ-साथ खुद उनके देश के लोग बेनकाब कर रहे हैं। ट्रंप की दोहरी नीतियों और मनमाने फैसलों से पूरा विश्व परेशान है। अब तो विश्व के प्रमुख देश इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि जैसे-तैसे ट्रंप के शेष कार्यकाल को झेलना पड़ेगा।

अवधेश राजपूत

अभी ट्रंप ने फार्मा और आइटी कंपनियों को टैरिफ वार से मुक्त कर रखा है, लेकिन भारत को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि उनकी निगाहें इन कंपनियों पर टेढ़ी नहीं होंगी। मनमानापन दिखा रहे ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। अब तो यह भी स्पष्ट हो रहा है कि वे भारत की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति बढ़ती हुई नहीं देखना चाहते और इसीलिए उस पाकिस्तान को पुचकार रहे हैं, जो अमेरिका को कई बार धोखा दे चुका है। ट्रंप के विचित्र रवैये को देखते हुए भारत के लिए आवश्यक है कि वह अपने कूटनीतिक कौशल के जरिये उनसे पार पाने की और कारगर रणनीति बनाए। अच्छा होता कि भारत दूसरी बार राष्ट्रपति बने ट्रंप के बदले रवैये को देखते हुए कूटनीतिक चतुराई दिखाता और उनके अहं को तुष्ट करने के बारे में सोचता। तब शायद ट्रंप इतना गर्जन-तर्जन नहीं कर रहे होते और अमेरिका से अंतरिम व्यापार समझौता भी हो गया होता। इस पर विचार होना चाहिए कि क्या ट्रंप के मामले में आवश्यक कूटनीतिक चतुराई नहीं दिखाई जा सकी? अब तो कूटनीतिक कौशल पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही भारत को अपने उद्योगों की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने पर भी जोर देना होगा।

ट्रंप के भारत विरोधी रवैये ने हमारे समक्ष एक अवसर खड़ा कर दिया है। आगे चलकर ट्रंप के टैरिफ युद्ध की चपेट में कुछ और देश भी आ सकते हैं। जो भी हो, भारत के लिए यही उचित है कि वह यह स्पष्ट करता रहे कि वह उनके आगे नहीं झुकेगा। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका के कृषि और डेरी उत्पादों के लिए अपने बाजार खोल दे। इसके लिए मोदी सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेरी उत्पादकों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इन वर्गों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई कीमत चुकानी पड़ी, तो वे इसके लिए तैयार हैं। यह साफ नहीं कि व्यक्तिगत नुकसान से उनका आशय क्या है, लेकिन इसकी अनदेखी न की जाए कि अमेरिका दूसरे देशों के चुनावों में दखल देता रहा है। अमेरिका से सावधान रहने के साथ भारत को अपने किसानों के हितों की रक्षा करनी होगी और इस पर भी ध्यान देना होगा कि भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए? इस मामले में सबसे बड़ी विडंबना कुछ किसान नेताओं का किसान हित विरोधी रवैया है। वे जानबूझकर कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण में रोड़ा अटका रहे हैं।

response@jagran.com

भोजन पर नसीहत के पकवान

हास्य-व्यंग्य

एक समय था जब इंटरनेट मीडिया मंचों पर डोनाल्ड ट्रंप को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इससे सबक लेते हुए उन्होंने 'ट्रुथ' नाम से अपना खुद का इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म बना लिया। इसका नाम भले ही ट्रुथ हो, लेकिन इसी पर रोजाना झूठ की चौपाल लगती है। इसी मंच पर वह अपने आपको घनघोर ज्ञानी साबित करते रहते हैं। हालांकि उनका ज्ञान भी चिराग तले अंधेरे जैसा है कि उन्हें यह पता है कि भारत पुराने दोस्त रूस से कौनसा पदार्थ कितनी मात्रा में खरीद रहा है, लेकिन इसकी कोई भनक नहीं कि उनका अपना देश रूस से क्या-क्या और कितना खरीद रहा है। विश्वशांति के हिमायती के रूप में नोबेल पर रोज का दावा आम बात हो गई है। 'ट्रुथ' पर ट्रंप कभी टैरिफ के लिए टरटराते तो कभी ब्रिक्स देशों को धमकाते हैं। शेयर मार्केट के सूचकांक के बदलने से पहले वह टैरिफ की नई दर घोषित कर देते हैं। कभी 'बिग ब्यूटीफुल बिल' पर अपनी पीठ थपथपाते हैं तो कभी अपने पूर्ववर्ती को सारी अराजकता का जिम्मेदार ठहरा देते हैं।

एक समय पाकिस्तान को फटकारने वाले ट्रंप का मन ऐसा बदला कि अब उसे ही पुचकारने लगे हैं। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान के अघोषित मुखिया और फेल्ड मार्शल, माफ कीजिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को न्योता भेजा। खैर, भोजन के बाद मुनीर ने ट्रंप के समक्ष 90 डिग्री के कोण पर झुकते हुए कहा-''डिनर के लिए आभार। यह बताएं नेवता कहां लिखवाना है।'' ट्रंप ने पूछा-''नेवता क्या होता है?'' जवाब मिला, ''नेवता एक प्राचीन प्रथा है जो अविभाजित हिंदुस्तान में सदियों से चली आ रही है। हम लोग जब शादी-विवाह में दोस्त या हित-नातेदार के यहां जाते हैं तो उपहारस्वरूप कुछ राशि भेंट देते हैं, जिसे नेवता कहा जाता है।'' ''अरे कंगाल देश तू हमें क्या नेवता देगा! बलूच संभल नहीं रहे तुमसे, आतंक की फैक्ट्री चलाने की औकात भी रही नहीं, आए हो हमें नेवता देने।'' ट्रंप बड़बड़ाए।

मुनीर ने जी-हुजूरी करते हुए फिर पूछा, 'सर, कृपया बताएं नेवता कहां लिखवाना है?'' ट्रंप ने फटाक से मुनीर के गाल पर एक रसीद किया। मुनीर ने दर्द से कराहते हुए पूछ लिया, ''आपने ऐसा क्यों किया?'' ट्रंपः ''चलो दूसरा गाल आगे करो।'' मुनीरः ''दूसरा गाल क्यों?'' ट्रंपः ''तुम तो गांधी की संतान हो न!'' मुनीरः ''नहीं-नहीं मैं जिन्ना की औलाद हूं।'' ट्रंपः ''अच्छा तभी 1947 में जो कटोरा हाथ में थामा था, वह आज तक नहीं छोड़ पाए। पूरी दुनिया में कटोरा लिए घूमते फिरते हो।'' मुनीरः ''आप हमारे दुश्मन मुल्क की जुबान क्यों बोल रहे हैं हुजूर? हमारी वफादारी का यह इनाम।'' ट्रंपः ''यह जुबान नहीं, भाषा है मेरे प्यारे मुनीर। मेरी जुबान तो अमेरिका को फिर से महान बनाने में लगी हुई है। वैसे भाषा की समझ अगर तुम लोगों को होती तो पूर्वी पाकिस्तान तुमसे अलग ही क्यों होता!'' मुनीरः ''हमारी दुखती रग पर क्यों हाथ रख रहे हैं माई-बाप!'' ट्रंपः 'वैसे थोड़ी देर पहले तुमने जिन्ना को अपना बाप बताया, अब मुझे। माजरा क्या है!'' मुनीरः ''हुजूर घर में खाने को आटा नहीं है। पिछले लोन से मिली हुई राशि तो हम कबकी डकार चुके। अब कुछ नए लोन का जुगाड़ करवा दो ताकि दाल-रोटी चलती रहे।'' ऐसी मिजाजपुर्सी से खुश होकर ट्रंप ने खैरात दे डाली और मुनीर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की तरह लड़खड़ा गए।

पाकिस्तानी मीडिया में खबर छपी कि आर्थिक सहायता मिलने के आश्वासन पर मुनीर मारे खुशी के उछल पड़े। खुशी संभल नहीं पाई तो फिर लड़खड़ाकर गिर गए। उधर गिरे हुए मुनीर को उठाने के लिए ट्रंप साहब ने उनकी ओर 'दोस्ती का बूट' बढ़ा दिया, जिसे मुनीर ने पलक झपकने से पहले लपक भी लिया। कुल मिलाकर, भोजन पर नसीहत के नाना-प्रकार के पकवान परोसे गए और मुनीर ने सब पचा भी लिए। यह दर्शाता है कि उनका 'हाजमा' कितना दुरुस्त है।

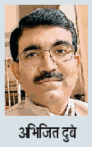

अभिजित दुबे

> ट्रंप को मुनीर से कहना पड़ा कि भाषा की समझ अगर तुम लोगों को होती तो पूर्वी पाकिस्तान तुमसे अलग ही क्यों होता

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

ऊर्जा

वर्तमान की आधारशिला

सामान्यतः लोग अतीत की गलतियों और भावी आशंकाओं के लिए दुखी रहते हैं। जबकि भूत कभी लौटता नहीं और भविष्य कोई जानता नहीं। इसलिए विद्वान वर्तमान में जीने की प्रेरणा देते हैं। दार्शनिक ओशो कहते हैं कि वर्तमान क्षण ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या है। भूत-भविष्य दुख देने वाले हैं। मानव के अतिरिक्त अन्य जीवों को इनका संज्ञान भी नहीं, इसलिए दुखी नहीं होते। सच है कि अतीत की पीड़ा और उज्ज्वल भविष्य की चाहत वर्तमान का सुख छीन लेती है, पर यह भी सच है कि यही वर्तमान के आधार बनते हैं। भूतकाल की त्रुटियां और भविष्य की चुनौतियां वर्तमान को संवारने का काम करती हैं। यदि ऐसा न होता तो आज भी हम पाषाणकाल में जी रहे होते। विकास की यह अकल्पनीय यात्रा इन्हीं की प्रेरणा से संभव हुई है। ये दोनों मनुष्य के सबसे अच्छे गुरु हैं, जो सदा संग रहकर वर्तमान का निर्धारण करते हैं। इनसे शिक्षा न लेना अपने ही दुर्भाग्य को आमंत्रित करना है।

हमारे ऋषि-मुनियों ने तीनों कालों को हथेली पर रखे आंवले के समान देखकर और अनुभव से जांच-परखकर वर्तमान की जो बुनियाद रखी थी, वह सह-अस्तित्व पर केंद्रित होने से समाज के लिए संजीवनी थी। देश-काल एवं भेद निरपेक्ष होने से वह आज भी समाज में एकता शक्ति को बढ़ाकर सुख-शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। हालांकि दुर्भाग्य है कि हम देश में भाषा, जाति, पंथ और मजहब के नाम पर निरर्थक भेद-भाव बढ़ाकर संघर्ष को जन्म देते हैं। दूसरी ओर, अतीत की युद्ध विभीषिकाओं के परिणाम देख चुकी दुनिया उनसे सीख लिए बिना तीसरे विश्व युद्ध की ओर अग्रसर है। यह चिंता का विषय है। वस्तुतः जो समाज अतीत की गलतियों से सीख लेकर अपनी क्रियाविधियों में परिमार्जन नहीं करता, उसका न वर्तमान मंगलकारी होता है, न भविष्य। इनसे अभिप्रेरित होकर अपने लिए सुखद वर्तमान और भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करें।

डा. सत्यप्रकाश मिश्र

तथ्य-कथ्य

यूपीआइ लेनदेन में हिस्सेदारी (जून 2025)

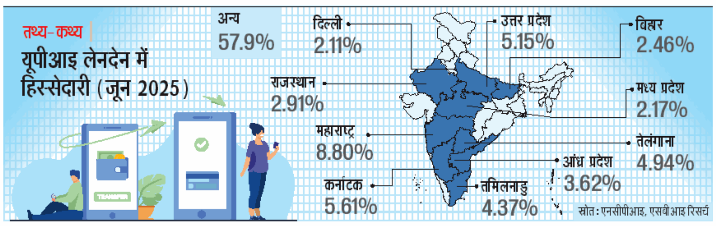

स्रोत: एनसीपीआइ, एसबीआइ रिसर्च

अस्तित्व के संकट से जूझतीं प्रवाल भित्तियां

प्रदीप

> जलवायु परिवर्तन, गरमाते समुद्र, प्रदूषण और तटीय विकास प्रवाल भित्तियों पर निरंतर दबाव डाल रहे हैं

प्रवाल भित्तियां (कोरल रीफ) पृथ्वी के समुद्री जैवविविधता तंत्र के अनोखे और नाजुक अंग हैं। आस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट आफ मरीन साइंस के अनुसार, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति 'ग्रेट बैरियर रीफ' में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न ताप, तनाव, चक्रवात और प्रवाल-भक्षी स्टारफिश के प्रकोप के कारण तेजी से क्षरण हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में कठोर प्रवाल आवरण 70 प्रतिशत से अधिक घट गया है। इस क्षरण की सबसे बड़ी वजह साल 2024 में घटित सामूहिक कोरल ब्लीचिंग घटना को माना जा रहा है, जिसे जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न समुद्री ऊष्मा तनाव ने जन्म दिया है। इसके अलावा चक्रवातों का प्रकोप और 'क्राउन-आफ-थांर्स' नामक प्रवाल-भक्षी स्टारफिश का फैलाव इस क्षति को और गंभीर बना दिया है।

पृथ्वी के विविध पारितंत्रों के बीच पारस्परिक समन्वय ही जीवन की विविधता को बनाए रखता है। प्रवाल भित्तियां भी अन्य पारितंत्रों की तरह जीवन के संरक्षण और विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। प्रवाल भित्तियों से बनी चट्टाननुमा संरचनाएं समुद्री लहरों की तीव्रता को तट तक पहुंचने से पहले ही कम कर देती हैं, जिससे तटवर्ती क्षेत्रों में मैंग्रोव जैसी वनस्पतियों के पनपने के अनुकूल वातावरण बनता है। अगर ये प्रवाल-निर्मित चट्टानें न हों, तो लहरों का तेज बहाव मैंग्रोव के विकास में बाधा डाल सकता है। मैंग्रोव वनस्पतियां न केवल समृद्ध जैवविविधता को आश्रय देती हैं, बल्कि सुनामी लहरों से भी तटीय क्षेत्रों की प्रभावी रक्षा करती हैं। इस तरह समुद्री लहरों के प्रकोप से तटीय आबादी की सुरक्षा में प्रवाल भित्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। फ्लोरिडा शहर में अगर प्रवाल भित्तियां न होतीं, तो यह अब तक समुद्र में समा चुका होता।

जलवायु परिवर्तन, गरमाते समुद्र, महासागरीय जल का अम्लीकरण, प्रदूषण, अंधाधुंध मछली पकड़ना और तटीय विकास प्रवाल भित्तियों पर निरंतर दबाव डाल रहे हैं। बढ़ते तापमान की वजह से कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं प्रवालों को मृतप्राय बना रही हैं। वहीं पर्यावरण में बढ़ता कार्बन डाइआक्साइड सागर के पानी में घुलकर उसके पीएच स्तर को घटा रहा है, जिससे प्रवालों के कैल्शियम कार्बोनेट आधारित ढांचे का निर्माण प्रभावित हो रहा है।

चिंता की बात यह है कि कई विज्ञानी मानते हैं कि यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो इस सदी के आखिर तक विश्व की ज्यादातर प्रवाल भित्तियां नष्ट हो सकती हैं! यह केवल समुद्री जैवविविधता के लिए ही नहीं, बल्कि मछली पालन, पर्यटन उद्योग, तटीय सुरक्षा और लाखों तटीय लोगों की आजीविका के लिए भी प्रत्यक्ष खतरा है। प्रवाल भित्तियों का संरक्षण अब सिर्फ पर्यावरणीय दायित्व ही नहीं, बल्कि वैश्विक अस्तित्व की अपरिहार्य कसौटी बन चुका है।

(लेखक विज्ञान संचारक हैं)

लिखत-पढ़त

राजनीतिक दलों की आक्रामकता के बावजूद सामान्यतया चुप्पी साधे रहने वाले चुनाव आयोग ने अब तय कर लिया है कि अपनी साख बचानी है तो मुखर भी होना पड़ेगा और सब कुछ लिखत-पढ़त में भी होगा। एकतरफा कुछ भी नहीं चलने दिया जाएगा। हाल में चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पोस्ट पर 'भ्रामक' का ठप्पा लगाकर अपना जवाब सार्वजनिक कर दिया। कर्नाटक में कांग्रेस नेता चुनाव आयोग के दफ्तर गए और कोई दस्तावेज नहीं दिया तो वह भी लिखत-पढ़त में सार्वजनिक कर दिया और बता दिया कि उन्होंने शपथपत्र तो दूर, दस्तावेज ही नहीं दिया, तो जांच कैसे हो। वैसे भी सरकारी कामकाज औपचारिक और नियम-कायदे के अनुसार ही होते हैं। यानी अब जब भी राहुल गांधी आरोप लगाएंगे तो चुनाव आयोग उनसे कहेगा कि आकर हमसे भी तो मिलें, हमें लिखित शिकायत भी दें। साफ है कि अब आने वाले समय में इंटरनेट मीडिया पर भी चुनाव आयोग की सक्रियता काफी दिखेगी।

राजरंग

रहस्यमय चुप्पी

सरकारी नीतियों और वैश्विक उथल-पुथल को लेकर बढ़-चढ़कर बोलने वाले भारतीय उद्योग चैंबर्स की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ पर चुप्पी की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। सरकार की ओर से अमेरिका के 50 प्रतिशत टैरिफ के खिलाफ खुलकर बयान आ रहे हैं, लेकिन उद्योग चैंबर्स की ओर से इसके खिलाफ अभी तक एक भी बयान नहीं आया है। आनंद महिंद्रा और हर्ष गोयनका जैसे इक्का-दुक्का उद्योगपतियों ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रिया जरूर दी है। इनमें से कई उद्योग चैंबर्स के अमेरिकी उद्योग चैंबर्स के साथ सहयोग का समझौता भी है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ वार के खिलाफ उनमें कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। चर्चा है कि कहीं इस रहस्यमय चुप्पी की वजह उद्योग चैंबर्स से संबंधित उद्योगपतियों के अमेरिका और यूरोपीय देशों से जुड़े आर्थिक हित तो नहीं हैं।

अमेरिका में इंतजार

ट्रंप की नीतियों से सिर्फ विदेशी सरकारें ही परेशान नहीं हैं। पिछले दिनों जब कारोबारी समझौते को लेकर भारतीय अधिकारियों की वाशिंगटन में बैठक हुई तो वहां उपस्थित एक अधिकारी ने काफी पीने के दौरान जो बातें कहीं वे तो अमेरिका के भीतर की बेचैनी को दर्शाती हैं। वार्ता की शुरुआत में ही यह साफ हो गया था कि बात बनने वाली नहीं है। इस बीच ब्रेक में भारतीय दल के एक प्रतिनिधि ने अमेरिकी प्रतिनिधि से अनौपचारिक तौर पर कहा कि जब बात नहीं बनेगी तो हम इंतजार करेंगे। इस पर अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि 'कोई बात नहीं। हमें भी साढ़े तीन साल इंतजार करना है, आप भी करो।' बताने की जरूरत नहीं कि जनवरी 2025 में ट्रंप ने दोबारा सत्ता संभाली है और उनका कार्यकाल दिसंबर 2028 तक है।

लालू नाम केवलम

पार्टी और परिवार से अलग-थलग पड़ने के बाद तेज प्रताप यादव ने गाड़ी का झंडा और टोपी का रंग तो बदल लिया, लेकिन लालू यादव पर अधिकार जताने की रफ्तार बढ़ा दी है। अब हर मंच पर और हर मुलाकात में वह 'लालू पुत्र' होने का अहसास कराना नहीं भूलते हैं। विधानसभा चुनाव सिर पर है और तेज प्रताप जानते हैं कि अपने बूते मैदान साधना आसान नहीं होगा। परिवार ने साथ नहीं दिया तो राह मुश्किल है। ऐसे में लालू यादव का नाम उनके लिए भावनात्मक जुड़ाव से ज्यादा रणनीतिक जरूरत बन गया है। इसलिए अब हर महफिल में तेज प्रताप को बताना पड़ता है कि 'मैं ही हूं लालू का असली वारिस!' अब वक्त बताएगा कि लालू की माला जपकर तेज प्रताप अपने आसन्न संकट से कैसे निजात पाते हैं।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

एक्स से

कारगिल युद्ध के दौरान भारत को अमेरिका और अन्य देशों के कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। इससे चुनौतियां पैदा हुईं, इसके बावजूद हम सफल रहे। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है- जनरल वीपी मलिक/पूर्व सेनाध्यक्ष

कभी अपनी बुलंदी भी देखिए

भारत जैसा जीवट कम देशों ने दिखाया है। लगभग दो सौ साल तक हिन्दुस्तान में लूट-खसोट का शासन चलाने वाले अंग्रेजों के देश इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को हमने सिर्फ साढ़े सात दशकों में पछाड़ दिया है। यही वजह है कि जब कोई देश टूटने की बात करता है, तो मुझे हंसी आती है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर जॉनसन द्वारा दान किया गया लाल गेहूं जेहन में उभरता है। जब हम वे दुर्दिन काट गए, तो यह बला भला कौन सी बला है?

आजकल स्तंभ के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

शशि शेखर

आजकल

किसी देश की दशा-दिशा आंकनी हो, तो उसके एक आम आदमी की जिंदगी में झांक देखिए, सब साफ हो जाएगा। पेश है, एक अनाम भारतीय का सफरनामा।

उसका बचपन, साल 1966।

मिर्जापुर शहर में वह अगस्त की दोपहर थी। एक राजकीय अधिकारी ने अपने छोटे से परिवार के साथ भोजन शुरू ही किया था कि उसकी साढ़े चार साल की बेटी ने रोना शुरू कर दिया। अगला नंबर उसके छह वर्ष के बेटे का था। इस हाय-तौबा की वजह थी लाल रंग की वे रोटियां, जो उस दिन पहली बार परोसी गई थीं। उनका स्वाद अजीब था। बच्चे छोटे थे, लेकिन स्वाद और गंध उम्र के गुलाम नहीं होते। उन दिनों अमेरिका जो गेहूं हमारे देश को दान में देता था, उसे वहां मुर्गियां खाती थीं। वह गेहूं भी महज नसीब वालों तक सीमित था। मिर्जापुर के आदिवासी तो कंद-मूल पर जिंदगी काट रहे थे। अवर्षण की वजह से भयंकर सूखा पड़ा था और खेत चटके पड़े थे। दुकानों पर कोका कोला उपलब्ध था, पर तमाम गांवों के जल भंडार सूखे पड़े थे।

दस्तावेज बताते हैं कि साल 1965-66 में महज 72.3 मिलियन टन खाद्यान्न देश में उपजा था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कुर्सी सम्हालते ही अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन से अन्नदान की गुहार लगानी पड़ी थी। आप यह जानकर खुश हो सकते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में हिन्दुस्तानी खेतों में 353.95 मिलियन टन अनाज उपजा। हाथ फैलाने वाले से अन्न निर्यातक तक की यह भारतीय यात्रा रोचक, रोमांचक और प्रेरणादायक है।

इंदिरा गांधी से पहले लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्हीं के वक्त में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरी जंग हुई थी। उस दौरान शास्त्री जी ने 'जय जवान, जय किसान' का जो नारा दिया, वह आज तक लोकप्रिय है, लेकिन उनके एक आह्वान की अब बहुत चर्चा नहीं होती, जबकि उसकी याद नई पीढ़ी के लिए प्रेरक हो सकती है। शास्त्री ने अनुरोध किया था कि सप्ताह में एक दिन एक वक्त का खाना न खाएं, क्योंकि देश में अनाज की कमी है। मेरे आदर्शवादी पिता और माता ने इसे तत्काल अमल में लाना शुरू कर दिया था। हम बच्चों से भी कहा गया था कि कुछ भी खाने का न बिगाड़ें, क्योंकि बहुत से लोगों को इतना भोजन भी नसीब नहीं है। आगे चलकर यह उस परिवार का संस्कार बन गया। उस जैसे हजारों परिवार इस संकल्प का आज तक पालन करते हैं।

कौन कहता है कि राजनेता समाज नहीं बदल सकते?

उसका यौवन, साल 1988।

लाल किले के प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश को संबोधित कर रहे थे। उसी समय वाराणसी रेल इंजन कारखाने के अस्पताल में एक बच्ची जन्म लेती है। बच्ची का पिता उस समय दूसरे शहर में एक दैनिक अखबार का स्थानीय संपादक था। शाम को जब वह राजीव गांधी के भाषण की अंतिम कॉपी बांच रहा था, उसे सूचना मिलती है कि वह पिता बन चुका है। उस खबरनवीस तक जीवन की सबसे जरूरी खबरों में से एक इस खबर को पहुंचने में सुबह से रात हो गई थी। कारण? दिन भर फोन नहीं लग सका था।

इन दिनों जब कोई भी सूचना कुछ सेकंड में दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच जाती है, तब उन दिनों को याद करना अचंभे की अंधी खोह में यात्रा का रोमांच देता है। तब मोबाइल और इंटरनेट नहीं थे। महज मुट्ठी भर नसीब वालों को लैंडलाइन फोन हासिल थे। उन्हें भी पहले ट्रंक कॉल और फिर सीधी ट्रंक डायल सेवा की आमद के बावजूद कभी-कभी घंटों इंतजार करना होता था। यह लैंडलाइन फोन पाने के लिए भी सांसद अथवा संचार मंत्री तक की शरण में जाना पड़ता था, क्योंकि आमजन के लिए बरसों की प्रतीक्षा सूची होती थी। आज उसी भारत में संसार के सर्वाधिक मोबाइल उपभोक्ता हैं। यही नहीं, लगभग 50 करोड़ यूपीआई उपयोगकर्ता दुनिया को अचंभित करते हैं। महानगरों में बसे अति दक्ष व्यवसायियों से अबूझमाड़ के जंगलों में बसे आदिवासियों तक लेन-देन की यह तकनीक आम आदमी के जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाई है।

उसका रोजनामचा, 1978 से आजतक।

1970 के दशक के अंत और 80 के दशक में ऐसा कई बार लगा कि यह देश टूट जाएगा। उन दिनों कश्मीर में आज जैसा आतंकवाद नहीं था, लेकिन पंजाब धधक पड़ा था। पाकिस्तान पोषित इस आतंकवाद में एक शोध के अनुसार, 1980 से 2000 के बीच 11,694 आमजन मारे गए थे। पंजाब पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के 1,784 जवानों और अधिकारियों ने अपनी आहुति दी या वे गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। हालांकि, तमाम लोग इन आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखते। इसी बीच 1982 में जनरैल सिंह भिंडरावाले की अगुवाई में हिंसक अलगाववादियों का जत्था हरमंदिर साहिब में घुसकर बैठ गया था। उन्हें निकालने के लिए 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' करना पड़ा। इस वजह से इंदिरा गांधी को उनके ही सरकारी बंगले में 'भरोसे' के सिख अंगरक्षकों ने 31 अक्तूबर, 1984 को मार डाला। यह हादसा अभूतपूर्व था। उसके बाद जिस तरह सिखों पर कहर ढाया गया, वह हमारे लिए आज तक शर्म की वजह है। नवंबर, 1984 में तो ऐसा लगने लगा था कि सिखों के प्रति उपजी बेवजह की यह घृणा इस बहादुर कौम को हमसे छीन लेगी।

ऐसा नहीं हुआ। भारतीय समाज में अपनी दरारों को पाट लेने की अद्भुत क्षमता है।

उन दिनों पूर्वोत्तर के तमाम प्रदेश अलगाव की आग से सुलग रहे थे। ऐसा लगता था, यह देश कई हिस्सों में बंट जाएगा। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा समय-समय पर अखबारों के संपादकीय पन्नों पर ऐसी चिंता जताई जाती थी। आज वे दिन धूमिल अतीत का हिस्सा हैं। कश्मीर में पड़ोस प्रायोजित आतंकवाद को छोड़ दें, तो बाकी राज्यों से आतंकवाद दम तोड़ चुका है। भारत से अलग होकर दूसरा राष्ट्र बनाने की बातें अब निरर्थक साबित हो चुकी हैं। जो माओवादी एक दशक पहले तक बहुत मजबूत नजर आते थे, वे भी अब चला-चली की स्थिति में हैं।

एक राष्ट्र-राज्य के तौर पर हम अगस्त 1947 में भले उभरे हों, पर हमारा राष्ट्रीय एका हजारों साल में परत-दर-परत पुख्ता हुआ है।

भारत की यह यात्रा बताती है कि भारत जैसा जीवट कम देशों ने दिखाया है। लगभग दो सौ साल तक हिन्दुस्तान में लूट-खसोट का शासन चलाने वाले अंग्रेजों के देश इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को हमने सिर्फ साढ़े सात दशकों में पछाड़ दिया है। कुछ सालों में हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि जब कोई देश टूटने की बात करता है, तो मुझे हंसी आती है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर जॉनसन द्वारा दान किया गया लाल गेहूं जेहन में उभरता है। जब हम वे दुर्दिन काट गए, तो यह बला भला कौन सी बला है? इस अविरल यात्रा में आगे भी दिक्कतें आएंगी, उनसे भी पार पा लेंगे। बस, आपको एक विनम्र योगदान करना है।

अपने जन्मदिन की भांति देश की आजादी के दिन, यानी इस 15 अगस्त को आप खुद किसी कुरीति से जूझने की कसम क्यों नहीं खाते? अपनी मातृभूमि के प्रति इससे बेहतर अवदान भला और क्या हो सकता है?

@shekharkahin
@shashishekhar.journalist

जीने की राह

शंकर मीणा
कृषक एवं उद्यमी

खेती-किसानी को चाहिए शंकर जैसे धुन के पक्के

एमबीए की पढ़ाई बीच में छोड़ने का फैसला बहुत सारी आलोचनाएं लेकर आया। वह जिस समुदाय से आते हैं, उसमें आईएएस और आईपीएस की बड़ी तादाद है। गांव के लोगों ने शंकर की क्षमता का उपहास उड़ाया। मगर उन तंज-तानों को दरगुजर कर वह अपनी तलाश में जुटे रहे।

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर जो तनातनी है, उसके मूल में एक बड़ी वजह है, भारतीय किसानों की हित-चिंता! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से इसके संकेत दिए हैं। दरअसल, अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को उसके कृषि उत्पादों के लिए खोल दे, ताकि वह अपने उत्पाद यहां के बाजार में उतार सके। भारत राजी नहीं। अमेरिका अपने किसानों को भारी रियायतें देता है और हमारे किसान उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा कृषि क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि सामाजिक अमन-चैन का भी बड़ा आधार है। इसमें हो रहे नए-नए प्रयोग हमें शंकर मीणा जैसे युवा किसान-कारोबारी दे रहे हैं, जो पढ़े-लिखे नौजवानों को खेती-किसानी की ओर लौटने को प्रेरित करते हैं। उन्हें जीने की राह दिखाते हैं।

जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर सांगानेर तहसील में एक छोटा-सा गांव है दांतली। यहीं के एक किसान परिवार में अगस्त 1993 में शंकर पैदा हुए। पिता मंगल राम मीणा इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। पत्नी कैलाशी देवी और उनकी बड़ी तमन्ना थी कि वे अपने तीनों बेटों को ऊंची से ऊंची तालीम दिलाएं। ऊंचे सपने ऊंची कीमत भी मांगते हैं। तीन-तीन बेटों की बेहतर परवरिश का ख्वाब मंगल राम को अपने खेत में पहुंचा देता, जहां वह हाड़तोड़ मेहनत करते। अपने खेतों में उनकी बड़ी आस्था रही। इलेक्ट्रीशियन का काम करते हुए भी उन्होंने कभी अपने इस विश्वास को डिगने नहीं दिया था।

शंकर का बचपन गेहूं और सरसों के खेतों में खेलते-कूदते कुछ यूं बीता कि खेती-किसानी से लगाव का बीज मन में कब अंकुरित हो गया, पता ही नहीं चला। साल-दर-साल उम्र की सीढ़ियां चढ़ते हुए किशोर शंकर ने यह महसूस किया था कि पिता फसलों को लेकर कई बार बहुत उदास हो जाते हैं। क्यों? दरअसल, कुदरती कोप से फसलें खराब हो जातीं, तो कमाई पर इसका बुरा असर पड़ता। ऐसे में, अपनों के सपनों को पूरा न कर सकने की टीस उन्हें निराश कर देती।

किशोरावस्था के दिनों से ही शंकर के मन को यह बात मथने लगी थी कि उन्हें इस उदासी का हल निकालना है और हल भी वही कारगर होगा, जो किसानों की आमदमी को एक स्थिरता दे। गांव के स्कूल से आठवीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद शंकर पड़ोस के गांव में स्थित हाई स्कूल पहुंचे, जहां से उन्होंने दसवीं तक की पढ़ाई पूरी की और उसके आगे की शिक्षा के लिए वह जयपुर आ गए। जयपुर के कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद उनका नया ठिकाना बना 'आरए पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट।' मगर पहले सेमेस्टर के बाद लगा कि वह वक्त जाया कर रहे हैं।

यह साल 2012 की बात है। शंकर का मन तो खेतों में रमा हुआ था। उसे लेकर उनके मन में नए-नए विचार आते, मगर वह खेती और कारोबार को जोड़ने वाले किसी ठोस रास्ते की तलाश में थे। लिहाजा, पहले सेमेस्टर के बाद ही एमबीए की पढ़ाई छोड़कर वह एग्रो-बिजनेस के व्यावहारिक पहलुओं की पड़ताल में जुट गए। यह फैसला बहुत सारी आलोचनाएं लेकर आया। वह जिस मीणा समुदाय से आते हैं, उसमें आईएएस और आईपीएस की बड़ी तादाद को देखते हुए गांव के कई लोगों ने शंकर की क्षमता का उपहास उड़ाया। मगर उन तंज-तानों को दरगुजर कर शंकर अपनी तलाश में जुटे रहे।

कुछ ही दिनों में उनकी तलाश पूरी हो गई। शंकर ने मशरूम की खेती के बारे में गहन अध्ययन किया था। विटामिन डी का स्रोत होने के अलावा इसे उगाने में मिट्टी की जरूरत न पड़ने और सीमित जगह में कई परतों में उगाने की सुविधा ने शंकर को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन दिनों घरों में इसके व्यंजन कम ही बनते थे, मगर होटलों में वे लोकप्रिय हो चुके थे। शंकर को लग गया कि इसका व्यवसाय भविष्य में बढ़ने वाला है। फिर क्या था, मशरूम की खेती से जुड़ी बारीक जानकारियों के लिए वह सोलन स्थित आईसीएआर मशरूम अनुसंधान निदेशालय पहुंच गए।

सोलन से लौटने के बाद शंकर ने घर का एक कमरा खाली किया और उसमें मशरूम उगाने का काम शुरू कर दिया। जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि राजस्थान में मशरूम के बीजों की कोई इकाई नहीं है। पारखी मन को इसके बिजनेस का मौका दिख गया। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण का आवेदन दिया। नौ लाख रुपये मंजूर हुए। जरूरत के लिहाज से रुपये कम पड़े, तो कुछ दोस्तों-रिश्तेदारों ने मदद का हाथ बढ़ाया और आईसीएआर, सोलन ने भी पूरा-पूरा साथ दिया। लगभग नौ हजार वर्गफुट में शंकर के सपनों की पहली प्रयोगशाला खड़ी हो गई। उन्नत तकनीकी से युक्त।

साल 2017 में कंचन अर्द्धांगिनी बनकर शंकर की जिंदगी में आईं और उन्होंने भी पति के सपनों को साकार करने में पूरा-पूरा सहयोग किया। पति-पत्नी, दोनों ने कृषि वैज्ञानिक डॉ प्रदीप सिंह शेखावत से मशरूम के बीज तैयार करने का गुर सीखा और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी मार्केटिंग शुरू कर दी। अगले छह महीने, हैरानी, खुशी और नई उड़ान के थे। मांग इतनी बढ़ी कि 2017 में ही शंकर को अपनी कंपनी 'जीवन मशरूम प्राइवेट लिमिटेड' की शुरुआत करनी पड़ी। आज उनकी प्रयोगशाला में विकसित बीजों की मांग देश ही नहीं, विदेश से भी आ रही है। उनकी कंपनी नेपाल, भूटान और यूएई को बीज की आपूर्ति कर रही है। उसका सालाना कारोबार सवा करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच चुका है।

आज शंकर की प्रयोगशाला में विकसित मशरूम के बीजों की मांग पूरे देश व कई बाहरी मुल्कों में बढ़ रही है। उनकी कंपनी का सालाना कारोबार सवा करोड़ रुपये से ऊपर जा चुका है। शंकर की सफलता बताती है कि सपनों को जीना आना चाहिए, कामयाबी तो झक मारकर आपके पास आएगी।

शंकर की अगली योजना एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की है। स्टार्टअप इंडिया द्वारा उन्हें 'इनोवेटिव एग्रीकल्चरल स्टार्टअप' से सम्मानित किया जा चुका है। शंकर की सफलता यही बताती है कि सपनों को जीना आना चाहिए, कामयाबी तो झक मारकर आपके पास आएगी।

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह

वो लम्हा

रितु कुमार
फैशन डिजाइनर

बेहाल कारीगरों ने बेचैन कर दिया

गुलामी की सदियों में दुनिया के अनेक देशों ने अपने वस्त्र और अपनी संस्कृति को बिसार दिया, पर भारत के कारीगर नहीं भूल पाए। गोरों ने कोशिश तो बहुत की थी कि भारत अपनी प्रतिभा भूल जाए और केवल 'गोरी-प्रतिभा' का ग्राहक बना रहे।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

दुनिया अक्सर हम भारतीयों को कम आंकने की गलती करती है और हम भी अपने पारंपरिक वैभव की ओर से मुंह बिचकाने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि विदेशियों ने ही हमें सब कुछ सिखाया, हमें तो कुछ नहीं आता था। हमारे पास आखिर था ही क्या? पर सच यह है कि इस देश के बारे में आप क्या-क्या बताएंगे? यहां के कपड़ों की ही बात कर लीजिए। उनके रंगों में भी केवल सफेद की बात कर लीजिए, तो यहां श्वेत वस्त्रों के ही कम से कम 15 शेड्स हैं। श्वेत के इतने शेड्स किसी भी अन्य देश में नहीं हैं और अपना देश अकेला ऐसा है, जहां लाखों लोग आज भी बिना सिले कपड़े बहुत शौक से पहनते हैं।

गुलामी की सदियों में दुनिया के अनेक देशों ने अपने वस्त्र और अपनी संस्कृति को बिसार दिया, पर भारत के कारीगर नहीं भूल पाए। गोरों ने कोशिश तो बहुत की थी कि भारत अपनी प्रतिभा भूल जाए, केवल 'गोरी-प्रतिभा' का ग्राहक बना रहे। यह कोशिश आज भी जारी है और भारतीय कारीगर खुद को दिलोजान से बचाने में जुटे हैं। 1960 के दशक के आखिर में भी कारीगर इसी कवायद में लगे थे। उनकी एक उजड़ती हुई बस्ती कोलकाता के बाहरी इलाके सेरामपुर हुआ करती थी। वहां के पुश्तैनी कारीगर कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंटिंग का काम करते थे और बेहद गरीब थे।

यह संयोग है कि इतिहास और संग्रहालय विज्ञान की एक विद्वान लड़की एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए सेरामपुर जा पहुंची। इरादा यही था कि यहां मरती हुई कला को इतिहास में दर्ज कर लिया जाए। संग्रहालयों में सजा लिया जाए, पर जब कारीगरों से बात शुरू हुई, तो कमाल हो गया। वहां के हालात देख, 25 वर्षीय युवती स्तब्ध रह गई। अमृतसर में जन्मी और दिल्ली, न्यूयॉर्क में पढ़ी-लिखी, दुनिया घूम चुकी युवती के मन में सवाल पैदा हो गया कि इस बचे हुए वर्तमान से यह पूछ तो लो, क्या यह इतिहास बनने को तैयार है? वाकई, जितने कारीगर मिले, कोई भी हार मानने को तैयार न था, जहां तक कला निभ जाए, उसकी सेवा हो जाए, इस देश की माटी के कारीगर निभा देना चाहते थे।

सेरामपुर ने उस युवती को एक अलग ही संसार में ला खड़ा किया और युवती ने लकड़ी के एक प्रिंटिंग ब्लॉक को अपनी मुट्ठी में प्यार से सहेजने की कोशिश करते हुए संकल्प लिया कि इस विरल कला को इतिहास में जाने से बचाना होगा।

कारीगरों की गरीबी देखी नहीं जाती थी। एक वस्त्र बनाने में कई-कई दिन लगते थे, तब चंद दिनों का निवाला जुटता था। कारीगरों के पास न अच्छे मकान थे और न अच्छा परिवेश। मैले-कुचैले से माहौल में भी वे राजसी वस्त्र तैयार करने में जुटे थे। उनके बनाए शानदार वस्त्र देख विश्वास नहीं होता था कि इन्हें बनाने वाले दो वक्त की रोटी के लिए भी तरसते होंगे।

फिर क्या था, उस विद्वान युवती ने वहीं सेरामपुर में एक उद्यम की नींव रखी। कुछ ब्लॉक प्रिंटर और दो मेजों के साथ शुरुआत हुई। कारीगरों को उनके परिवेश से निकालकर कहीं और ले जाना ठीक नहीं था, तो पहले उद्यम के लिए उन्होंने सेरामपुर को ही चुना। कढ़ाईकारों के काम को नए डिजाइन के साथ पेश करने की जरूरत थी, ताकि लोगों को तैयार वस्त्रों में कुछ खास नजर आए।

उन देशी कारीगरों ने ही सबसे पहले पहचाना कि यह मैडम रितु कुमार हैं, जो कारीगरों के हित में कुछ करना चाहती हैं। रितु ने साड़ियों को डिजाइन करना शुरू किया। कारीगरों ने अपने अंदाज को कुछ बदला और धीरे-धीरे अच्छी साड़ियां उतरने लगीं। कारीगर पूरे मन से बनाने लगे। अब समस्या यह आई कि कोलकाता ही नहीं, देश में कहीं भी ढंग की कोई कपड़े की दुकान न थी। बुटीक कल्चर कल्पना में नहीं था। उस दौर में दिल्ली में रितु कुमार ने अपना पहला बुटीक खोला। कोलकाता से दिल्ली पहुंचकर साड़ियां बिकने लगीं और उनकी कंपनी चल निकली। मांग बढ़ी, तो शहर-दर-शहर उनके स्टोर खुलने लगे। अनेक प्रकार की लुप्त वस्त्र कलाओं को उन्होंने पेश करना शुरू किया। भारतीय जरदोजी की सदियों पुरानी कला नए डिजाइन के साथ चर्चा में आ गई। ऊंचे दामों में बिकने लगी। कारीगरों की जिंदगी संवरने लगी। कुछ ही वर्षों में रितु कुमार (जन्म 1944) ने अपने वस्त्र शिल्प कारोबार को करोड़ों-अरबों में पहुंचा दिया।

आज दुनिया उन्हें श्रेष्ठ भारतीय डिजाइनर के रूप में जानती है। वह देश के उन चुनिंदा सम्मानित उद्यमियों में हैं, जिन्होंने यह साबित किया है कि भारत के पास दुनिया को बेचने के लिए बहुत कुछ है, बस थोड़े नवाचार की जरूरत है।

बेशक, भारतीय वस्त्र शिल्प ने लंबा रास्ता तय किया है, पर उन्हें अब भी संतोष नहीं है। वह अफसोस जताती हैं कि मैं अपने देश के हथकरघे के साथ वह नहीं कर पाई, जो मैंने कढ़ाई और प्रिंट के साथ किया। अभी तो देश में बहुत काम शेष हैं।

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

ऐसे मिले कि मिलने का अफसोस रह गया

तिरछी नजर

सुधीश पचौरी हिंदी साहित्यकार

वह वहां मिले। बहुत दिनों बाद मिले। ऐसा लगा, युगों बाद मिले हैं। लेकिन वह मिले, तो ऐसा लगा, जैसे मिले ही नहीं। उनका दायां हाथ हल्के से उठा और बैठ गया। मैं उनको देख रहा था, लेकिन 'नो आई कांटेक्ट', जैसे मैं वहां हूं ही नहीं।

गोष्ठियां, सेमिनार, सम्मेलन व सांस्कृतिक स्पेस होते हैं, जहां मित्र-मिलन होता है। कुछ गप्पें-गपास्टिक होती हैं, बहुत कुछ बेमतलब होता है, लेकिन इस बेमतलब का भी मतलब होता है। लेकिन इन दिनों कोई किसी से मिलकर भी नहीं मिलता! यूं सब ऑनलाइन मिलते रहते हैं और इतना-इतना मिलते हैं कि ऑफलाइन मिलने की जरूरत ही नहीं रहती। इस जमाने में हरेक बंदा हर बंदे की खबर रखता है। कौन क्या करता है? कब करता है? किससे मिलता है? क्या लिखता है? क्या पढ़ता है? उसकी लाइन क्या है? सबको सब मालूम रहता है।

यह आज की 'जेंजी' पीढ़ी का लेखक है, जो 'चौबीस बाई सात' के हिसाब से 'सोशल मीडिया' में जीता-मरता है। वह जो कुछ करता है, जो कुछ लिखता-पढ़ता है, पहनता-ओढ़ता है, खाता-पीता है, इन सबकी खबर वह सबको देता-लेता रहता है।

ये अति संपर्कित तो होते हैं, लेकिन संबंधित नहीं। इस संपर्कवादी दौर में संपर्क साधना ही असली साधना है। सिर्फ साहित्य साधना तो बेवकूफों का काम है... मतलब कि इतने पढ़ने-लिखने की क्या जरूरत? जिन सीनियरों ने सब कुछ पढ़-लिख लिया, उन्होंने साहित्य में कौन सा तीर मार लिया? क्या पता, किस-किस का माल मारा? कोई क्यों पढ़े और क्यों अपना भेजा खराब करे? जब बड़े से बड़े साहित्य साधकों को सीधे साधा जा सकता है, तो फिर साधना-आराधना करने का कष्ट क्यों किया जाए?

यूं भी जिन्होंने साहित्य की गहन साधना की, उन्हीं को क्या मिल गया? जीते जी तो उनको किसी ने जाना नहीं, चेले न होते, तो उनको कोई कैसे जानता? जिंदगी भर कलम घिसी, तो उनके सौ-पचास जानने वाले हुए, जबकि हम तो पहले दिन से ही हिट हैं।

पहले वाले लेखक जाने कितने कागज काले करते थे, साथ ही गुरुओं की चरण वंदनाएं करते, उनका आशीर्वाद लेते-लेते बूढ़े हो जाते थे। अगर गुरु कृपा हो गई, तो कुछ बन-बना गए, वरना किसी गुरु के चेले-चमचे ही बने रह जाते। गुरु जन चेलों को फांसे रहते। सपने दिखाते रहते। उनसे तरह-तरह की सेवाएं लेते रहते। चेले सोचते रहते कि बस, एक बार 'गृरु कृपा' हो जाए, तो यह जन्म सफल हो जाए। वे सोचते, गुरु जी जिसके माथे पर अंगूठा छुआ देंगे, वह कुछ भी बन सकता है।

पहले शिष्य गुरु जी की सेवा करते-करते ही निपट जाते थे। उनकी कृपा हो जाती, तो हो जाती। चेला कुछ बन जाता, तो बन जाता और उसी में खुश रहता, अब हालात ये हैं कि गुरु जी ही चेले से कहते हैं- 'भाई कुछ करो... मेरा पचहत्तरवां मनाओ, अस्सीवां मनाओ, नब्बेवां मनाओ, अभिनदंन ग्रंथ निकालो, सामग्री मैं दे दूंगा, कुछ पैसे मैं लगाऊंगा, कुछ तुम लगाओ... उस-उस का हो गया, मेरा भी कराओ।' इसके बाद हर तरफ चेले गुरुजी की महानता के गुण गाते दिखेंगे। लेकिन जैसे ही गुरु जी सिधारे, वैसे ही अपनी पर उतर आएंगे कि अबे, काहे के गुरु? सब कुछ तो हमसे लिखवाया, पर नाम डाला अपना। कमेटी की सेवा करवाई हमसे, खर्च किया हमने, लेकिन सम्मान ले उड़े वह... बस मुंह न खुलवाओ... क्या आता था उनको?

एक गुरु जी जब बीमार पड़े, तो आखिरी वक्त में उनके पास घर वालों के अलावा कोई चेला न था। जब तक उनसे काम निकलना था, निकलवाया, लेकिन जैसे ही स्वर्ग सिधारे, सब भूल गए। सच! आजकल सब मतलब से देखते हैं, वरना अनदेखा कर देते हैं, लेकिन हमारे जैसे क्या करें, जो आज भी तुलसी की तरह सोचते हैं-
आवत ही हरषै नहीं, नैनन नहीं सनेह!/ तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेह!!

कटाक्ष

राजेंद्र धोड़पकर

संस्थापकः शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

म्हारो प्रणाम बांके बिहारी जी

भगवान कृष्ण की क्रीड़ास्थली श्री वृन्दावन में करोड़ों हिन्दू भक्तों की अटूट आस्था है। यहां स्थित श्री बांके बिहारी जी का मन्दिर इस आस्था का संगम है। मगर मन्दिर के प्रबन्धन व इसके आसपास बनाये जाने वाले कारीडोर को लेकर खासा विवाद उत्पन्न हो गया है। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चाहती है कि मन्दिर में आने वाले भक्तों की अपार भीड़ को देखते हुए मन्दिर का प्रबन्धन कुशल हाथों में दिया जाये। इसके लिए राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर मन्दिर का न्यास गठित करने की व्यवस्था की थी। सरकार ने यह फैसला तब किया था जब सर्वोच्च न्यायालय की ही एक पीठ ने कहा था कि मन्दिर के प्रबन्धन का कार्य एक न्यास मंडल करेगा और उसे श्री बांके बिहारी के नाम से खुले बैंक खातों से धन निकालने का अधिकार होगा। यह न्यास मन्दिर के आसपास की सात एकड़ जमीन खरीद सकेगा मगर वह जमीन श्री बांके बिहारी के नाम पर ही होगी। इसके बाद योगी सरकार ने एक मन्दिर न्यास गठित करने की घोषणा की थी।

विगत दिन सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सूर्यकान्त व जायमाल्या बागची की पीठ ने इस फैसले को बदलने की बात कही और कहा कि जब तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मन्दिर के अध्यादेश सम्बन्धी याचिका पर अन्तिम फैसला नहीं आता है तब तक अध्यादेश पर रोक रहेगी। मगर जहां तक मन्दिर के सुचारू प्रबन्धन का सवाल है तो न्यायालय अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगा जिसमें चुनौती देने वाले गोस्वामी परिवारों के व्यक्ति भी शामिल किये जा सकते हैं। असल में 16वीं सदी में इस मन्दिर के संस्थापक गोस्वामी हरिदास के वंशज गोस्वामी परिवार मन्दिर पर निजी मालिकाना हक मानते हैं और वर्तमान में मन्दिर का प्रबन्धन ये लोग ही चलाते हैं। राज्य सरकार चाहती है कि मन्दिर में बढ़ती भक्तों की भीड़ के मद्देनजर मन्दिर की प्राचीन बनावट को यथावत रखते हुए इसके प्रचीन परिसर के स्थान पर विशाल परिसर बनाया जाये जिससे हर वर्ष करोड़ों की संख्या में आने वाले भक्तगणों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। गोस्वामी परिवार के वंशज इसका विरोध कर रहे हैं। वास्तव में हिन्दुओं के मन्दिर किसी की निजी सम्पत्ति नहीं होते हैं बल्कि उन पर पूरे समाज का अधिकार होता है क्योंकि परोक्ष रूप से उनके द्वारा चढ़ाये गये चढ़ावे से ही मन्दिर की आय होती है। सरकार चाहती है कि मन्दिर में श्रद्धा रखने वाले भक्तों की सही से देखभाल के लिए जरूरी है कि कारीडोर बनाया जाये जिससे यात्रियों को मन्दिर में उनके इष्ट देव की पूजा या दर्शन करने का मार्ग सुगम हो सके। इसे देखते हुए ही राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया था।

> **मगर जहां तक मन्दिर के सुचारू प्रबन्धन का सवाल है तो न्यायालय अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगा जिसमें चुनौती देने वाले गोस्वामी परिवारों के व्यक्ति भी शामिल किये जा सकते हैं। असल में 16वीं सदी में इस मन्दिर के संस्थापक गोस्वामी हरिदास के वंशज गोस्वामी परिवार मन्दिर पर निजी मालिकाना हक मानते हैं और वर्तमान में मन्दिर का प्रबन्धन ये लोग ही चलाते हैं। राज्य सरकार चाहती है कि मन्दिर में बढ़ती भक्तों की भीड़ के मद्देनजर मन्दिर की प्राचीन बनावट को यथावत रखते हुए इसके प्रचीन परिसर के स्थान पर विशाल परिसर बनाया जाये जिससे हर वर्ष करोड़ों की संख्या में आने वाले भक्तगणों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।**

मगर शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने इस अध्यादेश को निलम्बन में रखने का आदेश दिया और कहा कि वह प्रबन्धन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा जिसमें सरकारी अधिकारी व गोस्वामी परिवारों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकान्त ने तो यहां तक कहा कि वह मई महीने में इसी न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा पारित उस फैसले को भी वापस लेंगे जिसमें राज्य सरकार को पुनर्विकास कार्यों के लिए मन्दिर कोष से धन निकालने की अनुमति दी गई थी। मन्दिर के कोष में सैकड़ों करोड़ रुपये बताये जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी साफ कर दिया कि वह याचिकाकर्ताओं को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अध्यादेश को चुनौती देने की स्वतन्त्रता भी देता है। फिलहाल यह अध्यादेश तब तक निलम्बित रहेगा जब तक कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसकी वैधता के बारे में अपना अन्तिम फैसला नहीं देता है। सर्वोच्च न्यायालय में अध्यादेश की वैधानिकता को चुनौती गोस्वामी परिवारों की ओर से दी गई है। इस मामले में यह स्पष्ट होना चाहिए कि भगवान कृष्ण का बांके बिहारी स्वरूप हिन्दी साहित्य के भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक में अनुपम माना जाता है। कृष्णभक्त मीरा का यह भजन,

म्हारो प्रणाम बांके बिहारी जी...

भारतीय शास्त्रीय संगीत का अद्वितीय भजन माना जाता है जिसे प्रख्यात शास्त्रीय गायिका स्व. किशोरी अमोनकर ने गाया था। किशोरी जी को उनकी संगीत विधा पर भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया था। इतना ही नहीं कुछ वर्ष पहले तक वृन्दावन में स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन भी हुआ करता था जिसमें किशोरी जी कई बार स्वयं भी उपस्थित हुईं और उन्होंने म्हारों प्रणाम भजन भी गाया। इसके साथ ही भक्ति आन्दोलन के महानायकों में से एक गोस्वामी तुलसीदास की वृन्दावन यात्रा का संस्मरण भी खूब प्रचलित है जिसमें तुलसी दास जी बांके बिहारी जी की मोहक छटा को देखकर मुग्ध तो होते हैं परन्तु अपने भगवान राम के उपासक होने का भाव भी नहीं छिपाते हैं। इसे एक दोहे में इस प्रकार पिरोया गया है,

मोर, मुकुट कटि काछनी
भले लगो हों नाथ
तुलसी मस्तक तब झुके
जब धनुष बाण लो हाथ

अत: बांके बिहारी जी के मन्दिर के प्रबन्धन को लेकर उठा विवाद निश्चित रूप से अप्रिय तो है ही।

जमीनी हकीकत दिखाना जरूरी है

"अहंकार के शिखर पर चढ़े व्यक्ति को
जमीनी हकीकत दिखाना जरूरी है,
टैरिफ की ब्लैकमेलिंग पर एक उचित
प्रतिउत्तर आना जरूरी है,
अपने देश के नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए
हर नुक्सान उठाने को तत्पर हैं हम,
महाशक्ति का दंभ भरने वाले मुल्क को यह समझाना जरूरी है...।"

गीता पाढा

जारी है ऑपरेशन जिन्दगी

आपदाग्रस्त धराली में मलबे के ऊंचे ढेरों के बीच खोजी कुत्तों, ड्रोन और बचावकर्मियों की सहायता से लापता लोगों की तलाश जारी रही जबकि फंसे हुए 250 श्रद्धालुओं तथा स्थानीय व्यक्तियों को बाहर निकाल लिया गया। चार दिन पहले बादल फटने के कारण खीरगाड़ बरसाती नाले में आयी भीषण बाढ़ में आधा धराली गांव तबाह हो गया था तथा कई लोग लापता हो गए थे। यह सेना ही है जिसने टूटे हुए पुल का निर्माण किया और लोगों को मलबे से निकालने का दुष्कर काम कर दिखाया। सेना अभी भी वहां राहत कार्यों को युद्ध की तरह चला रही है। ऑपरेशन जिन्दगी अभी जारी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मंगलवार से अब तक 650 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है जिनमें से 400 बृहस्पतिवार को और 250 अन्य लोग शुक्रवार को निकाले गए। उन्होंने कहा कि शेष लोगों को भी जल्द ही निकाल लिया जाएगा। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तीन दिन तक बाधित रही संचार सेवाएं शुक्रवार को बहाल हो गयी। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि इससे बचाव कार्यों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। धराली से लौटने के बाद धामी ने संवाददाताओं से कहा, "इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल हो गयी है। प्रभावित क्षेत्र में एयरटेल ने काम करना शुरू कर दिया है। इससे बचाव अभियान में तेजी आएगी।" हालांकि, उन्होंने कहा कि धराली, हर्षिल और उत्तरकाशी के बीच सड़के अवरूद्ध हैं या टूटी हुई हैं और बिजली आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित है।

उन्होंने कहा कि एक जनरेटर सेट उत्तरकाशी लाया गया है जिसे प्रभावित क्षेत्र में पहुंचाया जाएगा। बचाव और राहत कार्यों पर करीब से निगाह रखने के लिए तीन दिन तक यहां डेरा डाले रहे मुख्यमंत्री ने कहा, 'स्थिति निश्चित रूप से कठिन है लेकिन हम जल्दी से जल्दी चीजों को पटरी पर वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं।" उन्होंने बताया कि गंगनानी के पास लिंचागाड़ पर बैली पुल बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। गढ़वाल के आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय ने कहा कि यह पुल दो दिन में तैयार हो जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पांच अगस्त को आयी आपदा में चार लोगों की मृत्यु हो गयी थी। आपदा स्थल से बुधवार को दो शव बरामद किये गए हैं।

उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, आपदा में सेना के नौ जवानों समेत 16 लोग लापता हुए हैं। हालांकि, धराली के पास स्थित मुखबा तथा अन्य गांवों के लोगों का कहना है कि आपदा में लापता हुए लोगों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती हैं क्योंकि घटना के समय वहां निर्माणाधीन होटलों में काम कर रहे नेपाल और बिहार के मजदूर तथा होटलों में रुके पर्यटक भी थे। धराली, गंगोत्री के रास्ते में पड़ने वाला एक प्रमुख पड़ाव है। उत्तराखंड राज्य आपदा नियंत्रण प्राधिकरण ने बताया कि घटनास्थल पर बचाव एवं राहत कार्यों में सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा प्रतिवादान बल और पुलिस के 800 से ज्यादा बचावकर्मी जुटे हैं। जीवित बचे लोगों को ढूंढने तथा मलबे के विशाल ढेर के नीचे दबे शवों का पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों और रडारों का उपयोग किया जा रहा है।

बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए सेना ने भागीरथी नदी पर एक पुल बना दिया है। सेना के एक अधिकारी ने कहा, "आज हमने भागीरथी नदी पर पुल बना दिया है जिसका उपयोग करके घायलों और फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा रहा है।" लोगों को अपने परिजनों से संपर्क करने में मदद के लिए सेना ने सैटेलाइट और रेडियो रिले प्रणाली समेत अपना संचार नेटवर्क सक्रिय कर दिया है। बाहर निकाले गए बहुत से लोगों ने अपने परिवार के लोगों से संक्षिप्त बातचीत भी की और उन्हें बताया कि वे सुरक्षित हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा ने कहा कि गंगोत्री में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा, "नागरिक प्रशासन, नागरिक हेलीकॉप्टरों और भारतीय वायुसेना की मदद से हम हर्षिल से करीब 355 लोगों को बाहर निकालकर मातली पहुंचा चुके हैं जहां से उत्तराखंड सरकार उन्हें देहरादून भेज रही है।"

उन्होंने कहा, "फिलहाल हमारा ध्यान उत्तरकाशी, हर्षिल और धराली के बीच सड़क संपर्क बनाने पर है। दूसरा, हम हर्षिल के उत्तर में रह रहे ग्रामीणों के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी और बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं जो तात्कालिक जरूरत है।"

● यह सेना ही है जो सारे कठिन काम को एक युद्ध की तरह अंजाम दे रही है और टूटे पुल को भी बना चुकी है

लेफ्टिनेंट जन मिश्रा ने कहा कि सेना ने मेडिकल का सामान पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा, "इस घटना से प्रभावित हुए सभी लोगों को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।" धराली में लगे मलबे के ढेर में लापता लोगों की तलाश के लिए जरूरी उन्नत उपकरणों को हेलीकॉप्टरों के जरिए मौके पर पहुंचाया जा रहा है। सेना के दो चिनूक एवं दो एमआई-17 हेलीकॉप्टरों के अलावा उत्तराखंड नागरिक उडडयन विकास प्राधिकरण के आठ हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जा रहा है। मलबे में कुछ ढूंढना एक कठिन कार्य है क्योंकि कई स्थानों पर मलबे के ढेर 50-60 फुट तक ऊंचे हैं।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के एक अधिकारी ने कहा कि विभिन्न जगहों पर सड़कें टूटी होने के कारण फंसे लोगों को बाहर निकालने तथा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री तथा अन्य जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए हवाई मार्ग का सहारा लेने पर ही जोर है।

धामी धराली गांव भी पहुंचे और वहां स्थानीय लोगों तथा एनडीआरएफ कर्मियों से मुलाकात भी की। इससे पहले दिन में उन्होंने आईटीबीपी, एनडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशकों समेत अन्र अधिकारियों से मुलाकात की तथा उनसे बचाव और राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली। धामी ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि अधिकारियों को सड़क, संचार और बिजली की बहाली के साथ-साथ खाद्यान्न आपूर्ति के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने उत्तरकाशी में चलाए जा रहे बचाव और राहत कार्यों में अपना एक माह का वेतन देने की भी घोषणा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वयं सेवी संस्थाओं और आम नागरिकों से आपदा ग्रस्त क्षेत्र में जारी राहत कार्यों के लिए अपना योगदान देने की अपील भी की।

काकोरी ट्रेन एक्शन पर क्या कहते हैं वंशज

लखनऊ के ऐतिहासिक 'काकोरी ट्रेन एक्शन' के 100 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में इस ऐतिहासिक घटना में भाग लेने वाले कुछ क्रांतिकारियों के वंशजों का मानना है कि 'काकोरी ट्रेन एक्शन' के शैक्षणिक दायरे का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि उनके पूर्वजों को अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।

भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ अपनी क्रांति के लिए हथियार खरीदने के लिए नौ अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन से ले जाया जा रहा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लिया था। वर्ष 1927 में, ब्रिटिश सरकार ने राम प्रसाद 'बिस्मिल', अशफाकउल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को इस घटना में दोषी करार देते हुए फांसी पर लटका दिया था। साल 2021 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्रांतिकारी घटना का नाम बदलकर 'काकोरी ट्रेन एक्शन' कर दिया था। हालांकि पहले आमतौर पर इसे 'काकोरी ट्रेन डकैती' या 'काकोरी ट्रेन षड्यंत्र' के रूप में वर्णित किया जाता था।

क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान के पोते अफाकउल्लाह खान ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, यह ऐतिहासिक घटना इतिहास के पन्नों में बमुश्किल कुछ पैराग्राफ तक ही सीमित है। इस ऐतिहासिक घटना को कक्षा आठ से कक्षा 12 तक एक अध्याय के रूप में शामिल करने की सख्त जरूरत है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी वास्तव में जान सके कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए कितने संघर्ष किए और कष्ट सहे। खान ने कहा कि 1857 से 1947 तक जिन गुमनाम क्रांतिकारियों ने शहादत दी, उनके बारे में विस्तृत जानकारी और प्रश्न होने चाहिए, जो छात्रों से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने चाहिए। उन्होंने का कि इससे छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। खान ने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी इस घटना को मुगलकाल की तरह एक विशेष विषय के रूप में पढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कि अगर इस घटना को सिर्फ़ पढ़ाने के लिए पढ़ाया जाएगा तो इससे कोई फायदा नहीं होगा बल्कि असली फ़ायदा तब होगा जब विभिन्न परीक्षाओं में इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछे जाएंगे।

खान ने कहा, "धीरे-धीरे, इससे युवाओं में राष्ट्रवाद की एक नयी भावना जागृत होगी। मैंने दसवीं कक्षा तक रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान के बारे में पढ़ा था। अब वे पाठ्यक्रम में हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। एक बार जब हमारे बच्चे यह जान जाएंगे कि हमारे देश को आजादी किन परिस्थितियों में मिली, तो वे स्वत: ही राष्ट्रवादी हो जाएंगे। खान ने यह भी कहा कि हमारे क्रांतिकारियों को उनकी जयंती, पुण्यतिथि और उनसे जुड़ी कुछ अन्य विशेष तिथियों से आगे भी याद रखने की जरूरत है। ठाकुर रोशन सिंह के पोते राजीव सिंह ने संपर्क करने पर 'कहा, विश्वविद्यालय स्तर पर काकोरी ट्रेन एक्शन पर और अधिक शोध किया जाना चाहिए। मैंने अपने दादा ठाकुर रोशन सिंह के बारे में सिर्फ सुना है, मुझे उन्हें जीवित देखने का सौभाग्य कभी नहीं मिला। मेरे दादा ने देश के लिए जो किया, उसे वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। राजीव ने कहा, मेरी बस यही इच्छा है कि मेरे दादा द्वारा किए गए कार्यों को उचित सम्मान मिले, आखिरकार उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। बच्चों को उनके और अन्य क्रांतिकारियों के बारे में और अधिक अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। शचींद्र नाथ बख्शी की पोती मीता बख्शी ने ' कहा कि ऐसे समय में, जब लोग आमतौर पर क्रांतिकारियों को भूल जाते हैं, उन्हें याद रखना अपने आप में एक बड़ी बात है।

उन्होंने का कि उनका मानना है कि स्कूलों में पढ़ाए जा रहे काकोरी ट्रेन एक्शन के दायरे को काफी बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे इस जगह के समृद्ध इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम पर इसके प्रभाव के बारे में और जान सकें। बख्शी ने कहा, "लखनऊ में स्थित बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में छह अगस्त से आठ अगस्त तक काकोरी की बरसी मनाई जा रही है। एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों ने पोस्टर भी बनाए। उन्होंने (बीबीएयू) काकोरी पर पाठ्येतर गतिविधियां आयोजित करने की पहल की।

● शहीद हुए क्रांतिकारियों के वंशज चाहते हैं कि इस कुर्बानी के बारे में अध्ययन का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए

विश्व संस्कृत दिवस पर मोदी ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर 'विश्व संस्कृत दिवस' के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। संस्कृत को ज्ञान और अभिव्यक्ति का एक शाश्वत स्रोत बताते हुए प्रधानमंत्री ने विविध क्षेत्रों में इसके स्थायी प्रभाव को रेखांकित किया। पीएम मोदी ने दुनिया भर के विद्वानों, छात्रों और उत्साही लोगों के समर्पण की सराहना की जो संस्कृत सीखने, सिखाने और उसे लोकप्रिय बनाने में निरंतर लगे हुए हैं। 'विश्व संस्कृत दिवस' के अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं में तीन अलग-अलग पोस्ट साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन दुनियाभर में संस्कृत सीखने और इसे लोकप्रिय बनाने वाले हर व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करने का सुअवसर है। उन्होंने लिखा, हम श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मना रहे हैं। संस्कृत ज्ञान और अभिव्यक्ति का एक शाश्वत स्रोत है। इसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। यह दिन दुनियाभर में संस्कृत सीखने और उसे लोकप्रिय बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करने का सुअवसर है।

कुत्तों का बढ़ता आतंक

श्रीमती किरण चोपड़ा
डायरेक्टर- पंजाब केसरी दैनिक समाचार लि.
चेयरपर्सन- वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब
मुख्य संरक्षिका- चौपाल
सदस्या- राष्ट्रीय सलाहकार मण्डल, एकल
संरक्षिका- भारतीय लोक विकास परिषद
f/kiranchopra01
kiranchopra@punjabkesari.com
kiranchopradesk@gmail.com

दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है तथा कुत्तों के काटने से लोगों के दिलों में खौफ बढ़ रहा है। दिल्ली के अलावा देश के अनेक राज्यों के बड़े शहरों में कुत्तों के नागरिकों पर हमले से हुई मौतों के प्रति प्रशासन क्या भूमिका निभा रहा है, इस बात को लेकर लोग चिन्तित हैं। नोएडा की सोसायटी में स्कूली बच्चों पर कुत्तों का हमला हो या दिल्ली के पूठकलां में एक 6 साल की बच्ची की कुत्ते के काटने से मौत का मामला हो या फिर बुजुर्गों पर कुत्तों के हमलों की वारदातें हों, हालात अच्छे नहीं हैं जो प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। दिल्ली में बच्ची की कुत्ते से काटने से हुई मौत की घटना का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है।

पिछले दिनों आवारा कुत्तों के हमलों और रेबीज के बढ़ रहे मामलों पर एक अखबार की मीडिया रिपोर्ट सामने आई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्वत: संज्ञान ले लिया है। पीठ ने बताया कि इस रिपोर्ट में कई चिंताजनक और परेशान करने वाले आंकड़े और तथ्य हैं। इसमें यह भी जानकारी दी गई है कि शहरों और ग्रामीण इलाकों में हर रोज कुत्तों के काटने की सैकड़ों घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें बुजुर्ग और बच्चे रेबीज से होने वाली बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। पीठ ने कहा है कि इस रिपोर्ट को प्रधान न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा। सड़कों के दोनों ओर कुत्तों के झुंड वाहनों के पीछे भागते हैं तो दुर्घटनाएं भी हो रही हैं।

कुत्तों के हमले से कोई बचे तो कैसे? इसका समाधान भी खोजना बहुत जरूरी है।

इस रिपोर्ट में आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हुए दो बच्चों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दिल्ली के पूठकलां इलाके में पागल कुत्ते के काटने की वजह से एक छह साल की बच्ची की मौत हो गई थी। कुत्ते के काटने के बाद वह रेबीज का शिकार हो गई, जिसके बाद इलाज शुरू होने के बावजूद भी उसे नहीं बचाया जा सका और 26 जुलाई को उसकी मौत हो गई। इस बच्ची के अलावा एक चार साल के छोटे बच्चे पर भी कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया था, जिससे बच्चा बुरी तरह घायल हो गया था। रिपोर्ट में यह बताया गया कि बच्चों के परिवार वालों के बार-बार शिकायत करने पर कथित तौर पर स्थानीय अधिकारी ने कोई कदम नहीं उठाया। जो लोग घरों में कुत्ते पालते हैं वे काफी हद तक उनसे आत्मीयता का भाव रखते हुए निभाते भी हैं लेकिन यदाकदा अंजान मेहनान या आगंतुक पर पालतू कुत्ते हमला भी कर देते हैं।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

पिछले दिनों भी 22 जुलाई को सरकार ने लोकसभा में एनसीडीसी की एक रिपोर्ट को सामने रखा था। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में कुत्तों के काटने के 37 लाख मामले सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने लिखित तौर पर जानकारी दी कि 2024 में कुत्तों के काटने के कुल 37,17,336 मामले सामने आए और रेबीज के कारण हुई संदिग्ध 54 मौतें दर्ज की गईं। सचमुच यह चौंकाने वाला है।

आवारा कुत्तों को खाना खिलाने तथा इसका विरोध करने वालों के मामले में भी दर्जनों केस हाईकोर्ट में व सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। दिल्ली के अनेक इलाकों में आरडब्ल्यूए तथा कुत्तों के लवर ग्रुप के बीच झगड़ों की खबरें भी विवादों के रूप में कोर्ट तक सुनवाई के दौर से गुजर रही हैं। लोग घरों के पास कुत्तों के जमा होकर बसेरे बना लेने के खिलाफ जब शिकायत करते हैं तो एमसीडी डागदस्ता उन्हें पकड़ने आता है तो डॉग लवर्स ग्रुप और अन्य संरक्षक संस्थानों के बीच जंग छिड़ जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नागरिक आवारा कुत्तों को खाना खिलाना चाहते हैं, उन्हें अपने घरों के भीतर ऐसा करने पर विचार करना चाहिए। हालत यह है कि न्यायालय कि यह टिप्पणी आवारा कुत्तों को लेकर समाज में मौजूद नैतिक मतभेद को उजागर करती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि कानून के अनुसार आवारा कुत्तों की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन प्रशासन को आम लोगों की चिंता को भी ध्यान में रखना होगा, ताकि सड़क पर चलने-फिरने में कुत्तों के हमलों से बाधा न आए।

संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 243(डब्ल्यू) नगर पालिकाओं को आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने का आदेश देता है। वहीं, अनुच्छेद 51ए (जी) के तहत नागरिकों का मौलिक कर्त्तव्य है कि वे "जीवित प्राणियों के प्रति करुणा का भाव" रखें।

इसी कड़ी में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत बनाए गए पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 का उद्देश्य बंध्याकरण के माध्यम से आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करना और टीकाकरण द्वारा रेबीज के प्रसार को रोकना है। इतना ही नहीं इन नियमों में सामुदायिक जानवरों को भोजन देने की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस या स्थानीय निकायों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिलाकर कुत्तों के आतंक पर चिन्ता नहीं उपाय किए जाने चाहिए तभी दिल्ली व अन्य शहरों या गांवों के बच्चे -बुजुर्ग-महिलाएं सुरक्षित रह सकेंगे।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

महत्वाकांक्षी लोग कुछ भी कर सकते हैं। यह उनके मार्गदर्शक सिद्धांतों पर निर्भर है। -नेपोलियन बोनापार्ट

महत्वाकांक्षा एक वरदान के साथ एक अभिशाप भी हो सकती है। महत्वाकांक्षी लोग बड़े लक्ष्यों का पीछा करना पसंद करते हैं, ठोकरें उन्हें जल्दी डिगा नहीं पातीं और वे कम भावुक होते हैं। लेकिन कई बार यही गुण उन्हें निर्दयी, चालाक, रुतबे के मोह में डूबे और सांसारिक सफलता पर इतना केंद्रित बना देते हैं कि वे अंदर से खोखले हो जाते हैं।

क्या महत्वाकांक्षी होना बुरा है

डेविड ब्रूक्स
द न्यूयॉर्क टाइम्स

आप जो करते हैं, उसमें अच्छा बनने की आंतरिक इच्छा से कितने प्रेरित होते हैं? अगर आप सिर्फ पैसे और शोहरत के लिए काम कर रहे हैं, तो आपमें अपने काम के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता और समर्पण की कमी होगी, और यही आपके अंदर जुनून की कमी के रूप में काम और जिंदगी में साफ दिखाई देगी।

महत्वाकांक्षी लोग ऊर्जावान होते हैं, वे बड़ी चीजें हासिल करने की कोशिश करते हैं और जिंदगी का भरपूर आनंद लेते हैं। उनकी प्रबल इच्छाशक्ति उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी सहनशक्ति प्रदान करती है। लेकिन, महत्वाकांक्षा एक वरदान के साथ एक अभिशाप भी हो सकती है। कई बार महत्वाकांक्षी लोग निर्दयी, चालाक, रुतबे के मोह में डूबे और सांसारिक सफलता पर इतना अधिक केंद्रित हो जाते हैं कि वे अंदर से खोखले हो जाते हैं। शेक्सपियर का नाटक *मैकबेथ* ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में है, जो महत्वाकांक्षा का गुलाम बन जाता है, जो उसे कठोर, अलग-थलग और नष्ट कर देती है। तो लाख टके का सवाल यह है कि आप महत्वाकांक्षा की ऊर्जा को उसकी अतृप्त मांगों से ग्रस्त हुए बिना कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? कुछ संत कहते हैं- ऐसा करने की कोशिश भी मत करो। महत्वाकांक्षा पर तुम्हारा कोई बस नहीं, इसलिए तुम्हें उसका त्याग कर देना चाहिए। दुर्भाग्य से, हममें से कई लोग (जिनमें मैं भी शामिल हूं) ऐसा कर पाने में असमर्थ हैं। मेरी परोपकारी इच्छाएं इतनी शक्तिशाली नहीं हैं कि कुछ भी बड़ा करने के लिए आवश्यक कठिन परिश्रम करने को प्रेरित होऊं। जब मुझे सचमुच प्रेरित होना होता है, तो निस्वार्थ और स्वार्थी, दोनों तरह की प्रेरणाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। मुझे लगता है कि हममें से ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। अब अमेरिका के पहले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को ही ले लीजिए। वह अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे। लिंकन व्हाइट हाउस पहुंचे, पर रास्ते में हर कदम पर आप उन्हें अपनी महत्वाकांक्षा से जूझते हुए देखते हैं। वह अपनी महत्वाकांक्षा को बगैर भ्रष्ट हुए ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अपनी महत्वाकांक्षा से ऐसा संघर्ष एक खतरनाक उद्यम है।

मुझे लगता है कि महत्वाकांक्षा के अजगर के साथ इस संघर्ष को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, यदि इसे पांच घटक संघर्षों में विभाजित कर दिया जाए-

■ शिल्प और उपलब्धि के बीच संघर्ष

अपने 1941 के उपन्यास, *व्हाट मेक्स सैमी रन?* में बड शुलबर्ग एक उग्र, आत्म-केंद्रित और महत्वाकांक्षी व्यक्ति का वर्णन करते हैं, जो हॉलीवुड में पटकथा लेखक के रूप में बड़ा नाम कमाता है। वह साहित्यिक चोरी करता है, दूसरों के विचार चुराता है, शॉर्टकट अपनाता है, और एक ऐसी पटकथा से खुश होता है, जो पैसा कमाती है, भले ही वह औसत दर्जे की ही क्यों न हो। यह एक महत्वपूर्ण बात है- आप जो करते हैं, उसमें अच्छा बनने की आंतरिक इच्छा से कितने प्रेरित होते हैं? अगर आप सिर्फ पैसे और शोहरत के लिए काम कर रहे हैं, तो आपमें अपने काम के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता और समर्पण की कमी होगी, और आपके अंदर जुनून की कमी के रूप में काम और जिंदगी में साफ दिखाई देगी।

■ उपहार में मिले प्रेम और जरूरत के प्रेम में संघर्ष

अपनी पुस्तक *द फोर लव्स* में, सी.एस. लुईस ने लिखा है कि हमारे कुछ प्रेम पूर्णता से उत्पन्न होते हैं और कुछ शून्य से। अगर बचपन में किसी ने आप पर अपार प्रेम बरसाया हो और आप भी अपने पड़ोसियों, सहकर्मियों और उत्पादों पर अपार प्रेम बरसाना चाहते हैं, तो वह उपहार में मिला प्रेम है। लुईस जरूरत के प्रेम के उदाहरण के रूप में मिसेज फिडगेट नामक एक पात्र का उदाहरण देते हैं, जो अपने परिवार की देखभाल के लिए समर्पित है। पर वह हमेशा अपने त्याग का बखान करती रहती है। वह चालाक और नियंत्रणकारी है और अपने दिल के खालीपन को भरने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसका प्यार आत्म-केंद्रित है। उपहार में मिला प्रेम मूलतः संसार से प्रसन्न होता है; जबकि जरूरत का प्रेम अतृप्ति और असफलता के भय से युक्त होता है। उपहार में मिला प्रेम मानवीय जुड़ाव को बढ़ावा देता है; जरूरत का प्रेम व्यक्ति को स्वयं में ही सीमित कर देता है, और एकाकीपन की ओर ले जाता है।

■ उत्कृष्टता और श्रेष्ठता के बीच संघर्ष

कुछ लोगों की लालसाएं तुलनात्मक नहीं होतीं। अगर वे किसी चीज में अच्छे हैं, तो वह संतुष्टि ही उसकी उपलब्धि है। जबकि कुछ दूसरे लोगों की लालसाएं मुख्यतः प्रतिस्पर्धात्मक होती हैं। उनका अच्छा होना ही काफी नहीं है; उन्हें दूसरों से बेहतर भी होना होता है। हमारा पूरा योग्यता-तंत्र (मेरिटोक्रेसी) श्रेष्ठता की चाहत के इर्द-गिर्द बुना गया है। सोशल मीडिया की दुनिया रैंकिंग और तुलना की एक क्रूर दुनिया है। येल धर्मशास्त्री मिरोस्लाव वोल्फ *द कॉस्ट ऑफ एंबिशन* में लिखते हैं, 'श्रेष्ठता के लिए कुंठित प्रयास अक्सर आक्रामक आत्म-प्रवंचना के रूप में राहत ढूंढता है, जिसमें श्रेष्ठ को नैतिक रूप से अपूर्ण, अभिमानी और दमनकारी बताया जाता है।' यह पर्याप्त नहीं है कि मैं ऊपर उठूं, दूसरों को गिराया भी जाना चाहिए।

■ उच्च और तुच्छ इच्छाओं के बीच संघर्ष-

आपकी महत्वाकांक्षा की गुणवत्ता उस लक्ष्य से निर्धारित होगी, जिसे आप पाना चाहते हैं। सदियों से विद्वान कहते आए हैं, अगर आप शक्ति के भूखे हैं, तो आप हमेशा शक्तिहीन महसूस करेंगे और विश्वासघात से डरेंगे; यदि आप समझ के भूखे हैं, तो आपका संसार हमेशा आश्चर्यों से भरा रहेगा; और यदि आप ईश्वर के भूखे हैं, तो आप स्वयं पूर्ण प्रेम के भूखे होंगे और आपकी भूख, मेरा विश्वास है, उस प्रेम से शुद्ध हो जाएगी। हम सभी सहज रूप से जानते हैं कि कुछ इच्छाएं नैतिक रूप से दूसरों से श्रेष्ठ होती हैं। हम प्यार करना और प्यार पाना चाहते हैं, जो एक महान महत्वाकांक्षा है, लेकिन हमें लगता है कि अच्छा दिखने, जानकार होने और लोगों के बीच लोकप्रिय होने से हम इसे पा सकते हैं। संत ऑगस्टाइन ने चेतावनी दी थी कि आप जिससे प्यार करते हैं, उसके प्रति सावधान रहें, क्योंकि अंततः आप उसी के रूप में बदल जाते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि नैतिक जीवन का अर्थ है अपने प्रेम को सही क्रम में रखना और उससे भी बेहतर की चाहत रखना।

■ महत्वाकांक्षा और आकांक्षा के बीच संघर्ष-

महत्वाकांक्षा दुनिया में ऊंचा उठने की चाहत है। आकांक्षा दुनिया में एक बेहतर इन्सान बनने की चाहत है। पहली सामाजिक गतिशीलता के बारे में है, जबकि दूसरी आंतरिक परिवर्तन के बारे में है। मैं महत्वाकांक्षा की सराहना करता हूं, लेकिन आकांक्षा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। ऐसे रिश्ते बनाने के लिए साहस चाहिए, जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किए। जब आप बाहरी प्रभाव के बजाय आंतरिक पवित्रता के लिए खुद को समर्पित करते हैं, तो दुनिया आपकी उतनी सराहना नहीं करती। पेशेवर सफलता अक्सर पूरे मन से, बिना किसी शर्त के एक लक्ष्य का पीछा करने से मिलती है। लेकिन जो लोग हमें पसंद आते हैं, वे थोड़े संशय के साथ बगैर मंजिल का तनाव लिए रास्तों का मजा लेते हुए दिखते हैं।

कुक्षिसंधारणाद् धात्री
जननाज्जननी स्मृता।
अङ्गानां वर्धनादम्बा
वीरसूत्वेन वीरसूः।।

अर्थात् माता संतान को गर्भ में धारण करने के कारण धात्री, जन्म देने के कारण जननी, शिशु के अंगवर्धन (पालन-पोषण) करने से अम्बा तथा वीर संतान का प्रसव करने के कारण वीरसू कही गई है।

-शांतिपर्व 266/32

(महर्षि गौतम के पुत्र चिरकारी का स्वकथन)

प्रस्तुति : **विवेक चौरसिया**

यह टहलना कुछ अलग है

डेनिएल फ्रीडमैन
द न्यूयॉर्क टाइम्स

सुबह की सैर सबको पसंद है, लेकिन अगर आप बगैर आलस इसे अपनी आदत बनाना चाहते हैं, तो जापानी वॉकिंग एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।

टहलना सबसे आसान व्यायामों में से एक है, लेकिन सभी प्रकार की सैर (टहलना) समान रूप से प्रभावी नहीं होतीं। सोशल मीडिया पर खासी चर्चित 'जापानी वॉकिंग' (अंतराल या इंटरवल वॉकिंग ट्रेनिंग) नामक एक विधि, एक साधारण सैर या यहां तक कि एक दिन में 8,000 या उससे अधिक कदम मध्यम गति से चलने की तुलना में अधिक लाभप्रद है।

इस रणनीति की शुरुआत दो दशक पहले जापान के शिंशु यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मेडिसिन के व्यायाम विज्ञानी हिरोशी नाज के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन से हुई थी। यह देश दुनिया की सबसे बुजुर्ग आबादी वाले देशों में से एक है, और डॉ. नोज को उम्मीद थी कि शीर्ष एथलीटों द्वारा आजमाई जाने वाली अंतराल-प्रशिक्षण तकनीकों को बुजुर्गों पर लागू करके वह उनके स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं और देश की चिकित्सा लागत को कम कर सकते हैं। इंटरवल वॉकिंग व्यायाम का एक रूप है, जिसमें बारी-बारी से तेजी और आराम से टहलना शामिल है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन फ्रांसिस्को में प्राथमिक देखभाल खेल चिकित्सा के प्रमुख डॉ. कार्लिन सेंटर ने बताया कि उच्च तीव्रता अंतराल के बेहद पारंपरिक रूपों की तुलना में, सामान्य इंटरवल वॉकिंग कई लोगों के लिए अधिक सुलभ है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए, जिन्होंने कुछ समय से व्यायाम नहीं किया है या जो चोटों से उबर रहे हैं। इसके लिए आपको बस आरामदायक जूते, चलने के लिए सुरक्षित जगह और एक टाइमर की आवश्यकता है। डॉ. नाज धीमे अंतरालों की तुलना में तेज अंतरालों के दौरान लंबे कदम उठाने की सलाह देते हैं। वह आपकी बांहों को भी सक्रिय रखने, उन्हें कोहनियों से मोड़ने और हर कदम पर उन्हें जोर से हिलाने का सुझाव देते हैं, ताकि लंबे कदमों के दौरान सही मुद्रा बनाए रखने में मदद मिले।

शोध बताता है कि सत्रों को दिन में तीन बार लगभग 10-10 मिनट के खंडों में विभाजित करना भी उतना ही प्रभावी हो सकता है। अगर आप कुछ समय से सक्रिय नहीं रहे हैं, तो धीमी गति से शुरुआत करें और धीरे-धीरे आगे बढ़ें। अगर तीन मिनट बहुत ज्यादा लग रहे हों, तो एक मिनट से शुरुआत करें और धीरे-धीरे आगे बढ़ें। समय के साथ, जैसे-जैसे आपकी फिटनेस में सुधार होगा, आप संभवतः तेज मुकाबलों के दौरान खुद को अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकेंगे।

©The New York Times 2025

जानना जरूरी है
संस्कृति के पन्नों से

आशुतोष गर्ग
लेखक एवं अनुवादक

शिव की क्रोधाग्नि ने कामदेव के शरीर को तो भस्म कर दिया, परंतु उसकी आत्मा को प्रेम की अदृश्य शक्ति के रूप में अमरता भी प्रदान कर दी। यही अनंग प्रेम, सृष्टि का मूल और जीवन का स्पंदन कहलाता है।

कामदेव को 'अनंग' क्यों कहते हैं

देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शंकर के अपमान से क्षुब्ध होकर यज्ञकुंड में आत्मदाह कर लिया था। उनके वियोग में भगवान शिव संसार से विरक्त होकर हिमालय की गुफाओं में तपस्या में लीन हो गए। उनके भीतर की समस्त चेतना स्थिर हो चुकी थी। उन्होंने संसार, सृजन, प्रेम समेत सब कुछ त्याग दिया था।

धूप आने दो

इस बीच देवताओं के सामने भयानक संकट मंडरा रहा था। नमुचि असुर के पुत्र तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र से संभव है। परंतु शिव सृष्टि से विमुख होकर तपस्या में लीन थे। ऐसे में शिव के पुत्र की उत्पत्ति असंभव ही थी। तब देवताओं ने एक योजना बनाई।

वे हिमवान की पुत्री पार्वती के पास पहुंचे। पार्वती ही पूर्वजन्म में सती थीं। पार्वती ने संकल्प लिया कि वह शिव को फिर पति रूप में प्राप्त करेंगी। उन्होंने इसके लिए कठोर तपस्या की। किंतु शिव ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं था। तब देवताओं ने कामदेव का आह्वान किया और उनसे आग्रह किया कि वह शिव की तपस्या को भंग करके उन्हें पार्वती की ओर आकर्षित करें।

कामदेव जानते थे कि यह अत्यंत जोखिम भरा है। फिर भी उन्होंने देवताओं और सृष्टि के कल्याण के लिए इस कार्य को करना स्वीकार किया। उनकी पत्नी रति ने रोकने की कोशिश की। उसने कहा, 'स्वामी, क्या आपने सुना नहीं कि शिव जब क्रोधित होते हैं, तो संहार कर डालते हैं?' लेकिन कामदेव मुस्कराए और बोले, 'यदि प्रेम के लिए प्राण देना पड़े, तो वह मृत्यु नहीं, परम सौभाग्य होगा।'

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

बसंत ऋतु के साथ कामदेव कैलाश पहुंचे। उन्होंने चारों ओर फूलों की वर्षा की, सुगंध फैलाई, कोयलों की मधुर कूक से वातावरण आलोकित किया। पूरी सृष्टि प्रेम से गूंज उठी। कामदेव ने पुष्प-बाण धनुष पर चढ़ाया और निशाना साधा। जैसे ही प्रेम-बाण शिव के हृदय में लगा, शिव का ध्यान भंग हो गया।

एक क्षण के लिए शिव की दृष्टि पार्वती पर ठहर गई। उनके हृदय में हलचल हुई, किंतु उसी क्षण उन्हें बोध हो गया कि किसी ने उनकी तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया है।

शिव के भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उस नेत्र से निकली अग्नि की ज्वाला सीधे कामदेव पर पड़ी और क्षणभर में कामदेव का शरीर जलकर भस्म हो गया। प्रेम, जो कुछ क्षण पहले तक हवा में सुगंध बनकर बिखर रहा था, सहसा भस्म में परिवर्तित होकर उड़ गया।

सारी सृष्टि स्तब्ध रह गई। रति विलाप करने लगीं। वह शिव के चरणों में गिर पड़ीं और रोते हुए बोलीं, 'हे महादेव, मेरे स्वामी ने यह कार्य सृष्टि के कल्याण के लिए किया था। आपने उन्हें भस्म कर दिया। मैं अब किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी?'

कुछ देर बाद शिव का क्रोध शांत हुआ, तो वह करुणा से भरकर रति से बोले, 'रति, कामदेव का शरीर भस्म हो चुका और वह तो वापस नहीं आ सकता, किंतु मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कामदेव, प्रत्येक जीव के हृदय में भाव बनकर अदृश्य रहेगा तथा प्रेम एवं करुणा के रूप में अभिव्यक्त होता रहेगा। अपने समस्त अंग खो देने के कारण अब से कामदेव का एक नाम 'अनंग' होगा!'

समय बीता। पार्वती ने शिव को भक्ति और प्रेम से प्राप्त किया। फिर दोनों का विवाह हुआ और आखिर शिव एवं पार्वती ने एक अत्यंत तेजस्वी, बलवान और विज्ञ पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम था-कार्तिकेय। अपने जन्म के कुछ ही समय बाद कार्तिकेय ने भीषण युद्ध करके तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर के अंत के साथ ही सृष्टि में सदाचार और संतुलन की फिर से स्थापना हो गई।

इस प्रकार, शिव की क्रोधाग्नि ने कामदेव के शरीर को तो भस्म कर दिया, परंतु उसकी आत्मा को प्रेम की अदृश्य शक्ति के रूप में अमरता भी प्रदान कर दी। यही अनंग प्रेम, सृष्टि का मूल और जीवन का स्पंदन कहलाता है।

अध्ययन कक्ष

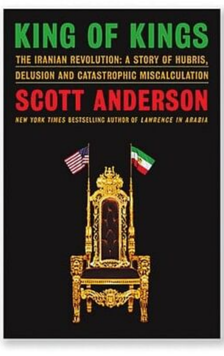

किंग ऑफ किंग्स
(द ईरानियन रेवोल्यूशन: ए स्टोरी ऑफ हुब्रीज, डेल्यूजन एंड कैटास्ट्रोफिक मिसकैलकुलेशन)

लेखक : स्कॉट एंडरसन

प्रकाशक : पेंगुइन रेंडम हाउस
मूल्य : 3,065 रुपये (हार्डकवर)

अमेरिकी विदेश नीति की वह ऐतिहासिक भूल

कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुई पत्रकार स्कॉट एंडरसन की यह किताब बताती है कि 1979 की इस्लामी क्रांति के खतरे को न समझ पाने की वजह से अमेरिकी विदेश नीति इस तरह पटरी से उतरी कि अब तक जूझ ही रही है।

वर्ष 1977 में ईरान की राजकीय यात्रा पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी को 'बादशाहों का बादशाह' कहते हुए बधाई दी, और ईरान की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह 'स्थिरता का एक द्वीप' है। विडंबना देखिए कि आज उसी अमेरिका का एक राष्ट्रपति ईरान को बर्बाद करना चाहता है। बेस्टसेलर पुस्तकों के लेखक स्कॉट एंडरसन की पुस्तक *किंग ऑफ किंग्स* ईरानी क्रांति का एक अद्भुत इतिहास प्रस्तुत करती है, जो आधुनिक समय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह शानदार कृति अमेरिकी सरकार की भारी गलतियों को उजागर करती है और धार्मिक राष्ट्रवाद के उदय का पता लगाती है, तथा आज की वैश्विक अशांति के बारे में आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ईरान के पास दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी सेना थी और वह अरबों डॉलर के तेल की कमाई में मस्त था। शासन के खतरनाक गुप्त पुलिस बल एसएवीएके ने कम्युनिस्ट विरोध को कुचल दिया था, और शाह ने देश के भीतर रूढ़िवादी मुस्लिम मौलवियों को खरीद लिया था। शीत युद्ध में एक सहयोगी के रूप में वह अजेय और अमेरिका के लिए अमूल्य प्रतीत होता था। चौदह महीने बाद, अयातुल्ला खुमैनी नामक एक उग्र धर्मगुरु के नेतृत्व में धार्मिक क्रांति के कारण शाह को सिंहासन से बेदखल कर दिया गया और वह ईरान से भाग गया। इसके बाद हुए बंधक संकट ने दुनिया में अमेरिका की प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए धूमिल कर दिया। ईरान का आखिरी शाह शेक्सपियर की त्रासदी का एक पात्र था : बाहर से घमंडी और वैभवशाली, अंदर से असुरक्षित और अनिर्णायक, एक फारसी रिचर्ड द्वितीय, जो अपने पतन के बाद भी आत्म-सम्मान से भरा हुआ था। जनवरी, 1979 में जब वह आखिरी बार ईरान से रवाना होने के लिए विमान की सीढ़ियों के नीचे खड़ा था, उसके गालों पर आंसू बह रहे थे और वह जानलेवा कैंसर से जूझ रहा था। यह देख कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी इस तानाशाह पर दया आई होगी। स्कॉट एंडरसन ने जो कहानी बुनी है, वह एक ऐसे तानाशाह की है, जो अपनी प्रजा के तिरस्कार को नहीं समझता और एक ऐसी महाशक्ति की है, जो विनाश की ओर अग्रसर है। एंडरसन ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया है कि ईरानी क्रांति, फ्रांसीसी और रूसी क्रांतियों की तरह ही दुनिया को हिला देने वाली घटना थी। पश्चिम एशिया, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अब अमेरिका में आर्थिक रूप से हाशिये पर पड़े धार्मिक लोगों की धर्मनिरपेक्ष कुलीन वर्ग के प्रति घृणा ने हिंसा और उथल-पुथल को जन्म दिया है-और ईरान इसका उदाहरण था। *किंग ऑफ किंग्स* इतिहास की एक साहसिक कृति और चेतावनी है। पश्चिम एशिया से लेकर यूक्रेन युद्ध तक, दुनिया अब भी शाह के पतन के झटकों से जूझ रही है, और यह अभी खत्म नहीं हुआ है।

अभियान

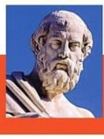

भूमि कितनी ही उपजाऊ क्यों न हो, बिना बीज बोए, बिना मेहनत किए अच्छी फसल नहीं हो सकती है।
- प्लेटो, महान दार्शनिक

amarujala.com
अमर उजाला

Hindi@mithelesh
■ मिथिलेश बारिया

गोल चबूतरा

पन्नों के बीच यूं दबा पड़ा था,
वो फूल, जैसे उस किताब का
किरदार हो कोई...

अपनी मंजिल होने का अहसास
उनको कराते रहना,
वरना लोग तुम्हें रास्ता समझ
कर गुजर जाएंगे...

स्पाइडरमैन आया लोगों के सामने

झरोखा
10 अगस्त

आभासी चरित्र स्पाइडरमैन आज के ही दिन 1962 में पहली बार मार्वल कॉमिक्स की 'अमेजिंग फैंटसी-15' नामक कॉमिक बुक में नजर आया था। इसे बच्चों ने इतना पसंद किया कि बाद में यह कार्टून फिल्मों के परदे पर भी नजर आया। गरीबों के मसीहा स्पाइडरमैन ने लंबे समय तक दुनियाभर में करोड़ों दिलों पर राज किया। स्पाइडरमैन का असली नाम पीटर पार्कर था। वह एक साधारण किशोर था, जो अपने चाचा-चाची के साथ रहता था। एक दिन उसे एक रेडियोधर्मी मकड़ी काट लेती है और वह चमत्कारी शक्तियां प्राप्त कर लेता है, जैसे- दीवारों पर चढ़ना, मकड़ी का जाल फेंकना और असाधारण फुर्ती। लेकिन इन शक्तियों के साथ आती है एक गहरी जिम्मेदारी। यह संवाद न केवल स्पाइडरमैन की कहानी की आत्मा है, बल्कि दुनियाभर के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया। आज स्पाइडरमैन सिर्फ एक कॉमिक कैरेक्टर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक बन चुका है। 63 साल बाद भी उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि असली हीरो वही होता है, जो अपने डर, दुख और कठिनाइयों से लड़कर दूसरों के लिए खड़ा होता है।

■ पिंकी खंडेलवाल, पानीपत

उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में आई आपदा प्रशासन और लोगों की लापरवाही का नतीजा है। जब तक विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ बंद नहीं होगी, ऐसी मुसीबतें आती रहेंगी।

प्राकृतिक आपदा के जिम्मेदार हम ही हैं

मानव निर्मित मुसीबत

चिट्ठी 1

उत्तराखंड के धराली में आई आपदा हो या हिमालयी क्षेत्र, जहां संकट के बादल मंडरा रहे हैं या यूं कहें कि मनुष्य अपनी बढ़ती मनोकामनाओं और इच्छाओं के वशीभूत होकर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा है। इसरो वैज्ञानिकों द्वारा पहले भी आपदा की जानकारी दी गई थी, मगर सरकारी तंत्र का उदासीन रवैया उत्तराखंड को खत्म कर रहा है, साथ ही तबाही के लिए निश्चय ही विकास के नाम पर पहाड़ों और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, सड़कों, सुरंगों, बांधों और भवनों के निर्माण के रूप में प्रकृति-पर्यावरण से मानव छेड़छाड़ ही जिम्मेदार है। हाइड्रो पावर बनाने के लालच में बड़े-बड़े बांध बनाने की रफ्तार भविष्य के लिए बहुत बड़े खतरे का आगाज है। पहाड़ी क्षेत्र में मानवों की बढ़ती जनसंख्या और ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसके परिणाम उत्तरकाशी का धराली हो या पूर्व में केदारनाथ और चमोली जैसी घटनाओं के रूप में दिखाई देते रहेंगे। यह भविष्य के लिए मानव को प्रकृति की चेतावनी है। सुखी, सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल जीवन प्रकृति के साथ संतुलन, संरक्षण और सामंजस्य से ही संभव है। सरकार को इस चेतावनी को गंभीरता से लेना होगा, ताकि हम आपदा से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें। पहाड़ी प्रदेशों में विकास कार्य करना आवश्यक है, केंद्र एवं प्रदेश सरकारें ऐसी विकासपूरक योजनाओं के धरातल पर ईमानदारी से कार्य करें कि जो जनता को सुख-सुविधा प्रदान करे। दरकती जमीन और सिसकते पहाड़ हमारी जीवन शैली को फिर से चेतावनी दे रहे हैं कि संभल जाओ मानव, अभी भी वक्त है, प्रकृति के दोहन को रोक लो।

■ लक्ष्मण पुंडीर, श्रीनगर गढ़वाल

नीति नहीं नीयत है जिम्मेदार

चिट्ठी 2

हमारे देश की सरकारी शिक्षा की बदहाली के लिए सरकार की नीतियां नहीं, वरन उन नीतियों को अमल करवाने वाले अमले की नीयत सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। केंद्र या राज्य सरकार की प्रत्येक योजना का मकसद देश और राज्य के लोगों के विकास से जुड़ा होता है। धरातल पर सरकार की योजनाओं की सफलता या असफलता का सारा दारोमदार उससे जुड़े संबंधित विभाग के अधिकारियों की नीयत पर निर्भर करता है। देश में कई शासकीय योजनाएं ऐसी हैं, जो तंत्र के लोगों की साफ नीयत की वजह से देश के विकास में बेहतर साबित हो रही हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जितनी प्रगति देश और राज्यों में आजादी के बाद होनी चाहिए थी, उसके न होने की वजह जिम्मेदार लोगों की नीयत का ही परिणाम कहा जाएगा। देश में एक आम मानसिकता बन गई है कि जब सरकारी योजना के अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं तो हम सरकार को कोसते हैं, जबकि इसके लिए उन योजनाओं के जिम्मेदार तंत्र को कोसना चाहिए, जिसकी उदासीनता की वजह से सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ जनता को उतना नहीं मिल पाता है, जितने के वे हकदार हैं। यही हालत और यही सच्चाई आज देश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की है, लेकिन इसके लिए अकेले शिक्षक को दोषी ठहराना भी तो न्यायसंगत नहीं है।

■ अरविन्द रावल, झाबुआ

त्योहारों पर ट्रैफिक जाम प्रशासनिक उदासीनता

चिट्ठी 3

भारत विविधताओं और उत्सवों का देश है। यहां सालभर अलग-अलग सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक आयोजन होते रहते हैं। इनका उद्देश्य समुदायों को जोड़ना, परंपराओं को जीवित रखना और खुशियां बांटना होता है। लेकिन जब इन आयोजनों के दौरान और लोगों की आवाजाही के कारण सड़कों पर घंटों तक ट्रैफिक जाम लग जाता है, आपातकालीन सेवाएं रुक जाती हैं और आम आदमी का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हमने उत्सव और सुविधा के बीच संतुलन बनाने की आदत खो दी है?

त्योहारों पर ट्रैफिक समस्या केवल आमजन की गलती नहीं है। यह एक व्यापक सामाजिक व्यवहार का हिस्सा है, जहां हम सार्वजनिक संसाधनों को अपनी निजी सुविधा की तरह इस्तेमाल करते हैं और दूसरों की असुविधा के प्रति असंवेदनशील रहते हैं। लोग अपने वाहनों को सड़क पर कहीं भी पार्क कर देते हैं, यातायात नियमों को 'त्योहार का अपवाद' मानकर तोड़ते हैं।

नागरिकों को भी यह समझना होगा कि सड़कें, पुल और सार्वजनिक स्थान सबके हैं। त्योहार मनाने का असली आनंद तभी है, जब इसमें किसी और की तकलीफ शामिल न हो।

■ मुनीष भाटिया, कुरुक्षेत्र

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

इनकी **चिट्ठियां** भी सराहनीय रहीं

फिरोजाबाद से शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, मोहाली से अभिलाषा गुप्ता, जालंधर से राजेश कुमार चौहान, बरेली से सीमा गुप्ता, अमरोहा से डॉ. महताब अमरोहवी, लखीमपुर खीरी से सुरेश सौरभ, मेरठ से डॉ. नरेन्द्र टोंक, सूरत से कांतिलाल मंडोत, उज्जैन से हेमा हरि उपाध्याय, देवास से हरिप्रसाद चौरसिया, इंदौर से अमृतलाल मारू 'रवि', रायपुर से संजीव ठाकुर।

हमें लिखें
abhiyan@amarujala.com

कुछ अलग

यादों में रह जाएगी रजिस्टर्ड पोस्ट

आगामी 1 सितंबर 2025 से भारतीय डाक विभाग की रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा बंद हो जाएगी।

अगर आपका जन्म 70 से 90 के दशक के बीच हुआ है तो आपने डाकघरों में रजिस्टर्ड चिट्ठी या पार्सल भेजते हुए लोगों को जरूर देखा होगा। भारतीय डाक विभाग के अनुसार, आगामी 1 सितंबर, 2025 से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा बंद हो जाएगी। हालांकि 31 अगस्त तक दोनों सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी, लेकिन 1 सितंबर से लोगों को अपनी चीजें स्पीड पोस्ट से ही भेजनी होंगी।

रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को स्पीड पोस्ट के साथ जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। सरकार का दावा है कि ऐसा करने से काम करने का तरीका अत्याधुनिक होगा। रजिस्टर्ड पोस्ट की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि कोई महत्वपूर्ण कागज या दस्तावेज अथवा बाहर पढ़ने वाले बच्चों को बैंक ड्राफ्ट बनाकर भेजना हो, सबके लिए इसी का उपयोग किया जाता था। आजादी के बाद से ही रजिस्टर्ड पोस्ट को बेहद भरोसेमंद माना जाता था। सरकार भी अटमेंट लेटर भेजने में इसका इस्तेमाल करती रही है। अदालत भी कानूनी नोटिस इसके जरिए ही भेजा करती थी।

भारतीय डाक सेवा की स्थापना 1 अप्रैल, 1854 को हुई थी, लेकिन सही मायनों में इसकी स्थापना 1 अक्तूबर, 1854 को मानी जाती है। तत्कालीन भारतीय वायसराय डलहौजी ने इस सेवा का केंद्रीकरण किया था। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले 701 डाकघरों को मिलाकर भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई थी। डाक विभाग की ही एक अन्य सेवा स्पीड पोस्ट है। इसे 1986 में शुरू किया गया था। रजिस्टर्ड चिट्ठी की तरह ही इसमें भी बुकिंग के वक्त रसीद दी जाती है। इसे आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि स्पीड पोस्ट सेवा रजिस्टर्ड पोस्ट से 20-25 प्रतिशत महंगी हो सकती है। फिलहाल, रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा का बंद होना एक युग का अंत होगा।

■ सीमा सिन्हा, जम्मू

जिंदगी का मकाम ढूंढते संगीत के दो दिग्गज

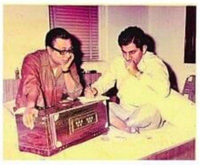

1974 में बनी फिल्म 'आपकी कसम' के गाने 'जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम' की धुन बनाने में तल्लीन आर.डी. बर्मन और आनंद बख्शी।

■ अपर्णा, गाजियाबाद

छायानट

बेटे के लिए पिता ने गिरवी रखा बंगला

कुमार गौरव हीरो बनना चाहते थे, जबकि उनके पिता राजेंद्र कुमार चाहते थे कि वह निर्देशन में हाथ आजमाएं। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर कुमार ने राज कपूर के साथ करीब दो साल काम भी किया। जब कुछ बारीकियां सीख लीं तो एक बार फिर कुमार के दिल-दिमाग में हीरो बनने का जुनून जागा। राजेंद्र ने शर्त रखी कि स्क्रीन टेस्ट दो। कुमार का स्क्रीन टेस्ट आरके स्टूडियो में रखा गया। राज कपूर सामने बैठे थे, कुमार काफी घबरा गए। वह कुछ बोल ही नहीं पाए। यह देखकर राजेंद्र कुमार को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, "तुम अपने काम में फिसड्डी रह गए, फेल हो गए। तुम एक्टर बनने लायक नहीं हो।" राज कपूर की सलाह पर राजेंद्र ने उन्हें एक्टिंग स्कूल भेजा। लौटने के बाद राजेंद्र ने 'लव स्टोरी' नाम से फिल्म बनाई। 1981 में रिलीज हुई इस फिल्म ने कुमार गौरव को रातोरात स्टार बना दिया। उसके बाद लगातार कुमार की फिल्में फ्लॉप होती रहीं। राजेंद्र ने बेटे के लिए फिल्म 'लवर्स' बनाई। इस फिल्म को बनाने में इतना खर्चा हुआ कि राजेंद्र कुमार को अपना बंगला तक गिरवी रखना पड़ गया था।

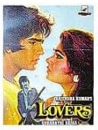

■ अनुज सिंह, दिल्ली

एक प्रभावशाली और गंभीर व्यक्तित्व

पहली मुलाकात में ही यह स्पष्ट हो गया था कि राजमोहन एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इसके कुछ समय बाद मैंने उनके द्वारा लिखी राजाजी और वल्लभ भाई पटेल की जीवनियां पढ़ीं और उनसे बहुत प्रभावित हुआ।

महात्मा गांधी के चार बेटे थे। वे अपने दो बड़े पुत्रों- हरिलाल और मणिलाल से अधिक प्यार रामदास से करते थे, जबकि सबसे छोटे बच्चे देवदास को उनकी माता कस्तूरबा भी बेहद लाडली थीं। देवदास बहुत सौम्य स्वभाव के थे और जल्द ही आश्रम के जीवन में पूरी तरह रम गए। जैसे-जैसे उनका परिचय आश्रम-जीवन से गहरा हुआ, उन्होंने पिता की बातों का पालन मेहनत से किया, चाहे चरखे से सूत कातना हो या दक्षिण भारतीयों को हिंदी पढ़ाना। गांधी जी के जीवन में एक मौका ऐसा भी आया, जब देवदास ने उनकी बात नहीं मानी। ऐसा तब हुआ, जब उन्हें सी राजगोपालाचारी यानी 'राजाजी' की बेटी लक्ष्मी से प्रेम हो गया। यह एक ऐसा रिश्ता था, जिसका गांधी और राजाजी दोनों ने विरोध किया था। देवदास और लक्ष्मी के माता-पिता ने उनसे कहा कि वे अपने प्यार की परीक्षा लेने के लिए पांच साल तक एक-दूसरे से न बोलें और न ही पत्र लिखें। उन्होंने ऐसा ही किया और इसके बाद शादी कर ली। देवदास को हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में नौकरी का प्रस्ताव मिला और वे लक्ष्मी के साथ दिल्ली आ गए। इसी शहर में उनके चार बच्चे तारा (1934), राजमोहन (1935), रामचंद्र (1937) और गोपालकृष्ण (1945) जन्मे।

गांधी जी के बेटे और राजाजी की बेटी के विवाह की कहानी बचपन से ही मेरे मन में बसी हुई थी। देवदास और लक्ष्मी के प्रेम कहानी को भारत के मध्यम वर्ग में काफी पसंद किया जाता था। इसने मेरे माता-पिता को भी प्रेम विवाह में इंतजार करने के लिए प्रेरित किया था। उन्हें भी प्रेम विवाह करने के लिए पांच सालों का इंतजार करना पड़ा था। मेरे लिए यह बड़े ही सौभाग्य की बात थी कि मुझे देवदास और लक्ष्मी गांधी के चारों बच्चों को जानने-समझने का मौका मिला।

उन भाई-बहनों में जिनसे मैं सबसे पहले मिला, वे रामचंद्र (रामू) थे, जबकि देवदास के सबसे छोटे बेटे लोक सेवक और लेखक गोपालकृष्ण मेरे सबसे ज्यादा करीबी हैं। हमारी दोस्ती 1980 के दशक के अंत में हुई, जब हम दोनों दिल्ली में काम करते थे। गोपाल गांधी के घर पर ही मेरी पहली मुलाकात उनकी बहन तारा से हुई, जो खादी की विशेषज्ञ हैं और हिंदी, बंगाली, इतालवी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में बेहद निपुण हैं। गोपाल ने ही मुझे अपने दूसरे भाई राजमोहन से भी मिलवाया, जिनका नब्बेवां जन्मदिन 7 अगस्त को मनाया गया।

जब मैं पहली बार 1990 में राजमोहन गांधी से मिला, तो वे एक संसदीय चुनाव लड़कर हार चुके थे। इससे एक साल पहले उन्हें अमेठी में लोकसभा चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। इसे असली गांधी बनाम नकली गांधी की लड़ाई के रूप में प्रचारित किया गया था, जिसमें महात्मा के एक प्रामाणिक वंशज और एक ऐसे व्यक्ति के बीच मुकाबला था, जो संयोगवश उनका उपनाम रखता था। राजमोहन के पास नैतिकता तो थी, लेकिन पैसा नहीं था। उस समय नेहरू परिवार का गढ़ माने जाने वाले अमेठी में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि राजीव गांधी की पार्टी ने अपना बहुमत खो दिया और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। राजीव गांधी को कड़ी टक्कर देने के पुरस्कार स्वरूप वीपी सिंह ने राजमोहन को राज्यसभा का सदस्य बना दिया।

रामचंद्र गुहा
जाने-माने इतिहासकार

लंबे कद और मोटे चश्मे वाले राजमोहन गांधी में विशिष्टता और गंभीरता झलकती है। वे बहुत ही सावधानी से धीरे-धीरे बोलते हैं। उनमें रामू जैसी वाकपटुता और शरारती हास्य-बोध का अभाव है। उनसे पहली मुलाकात में ही यह स्पष्ट हो गया था कि राजमोहन एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इसके कुछ समय बाद मैंने उनके द्वारा लिखी राजाजी और वल्लभ भाई पटेल की जीवनियां पढ़ीं और उनसे बहुत प्रभावित हुआ। राजमोहन गांधी ने उदारवादी मूल्यों को बढ़ावा देने वाली साप्ताहिक पत्रिका 'हिम्मत' की स्थापना और संपादन भी किया था। आपातकाल के दौरान इसने सेंसर बोर्ड का डटकर सामना किया, लेकिन बाद में पैसों के अभाव में बंद हो गई।

गोपाल के जरिए राजमोहन से मुलाकात होने के बाद मैंने शीघ्र ही उनसे अलग से भी मिलना शुरू कर दिया। हर मुलाकात में मुझे देश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती थी। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली, बंगलूरू, पंचगनी और ईस्ट लांसिंग, मिशिगन में मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई है। मैं उनकी किताबें और निबंध पढ़कर प्रेरणा लेता रहा हूं। राजमोहन और मेरे बीच छपे हुए विषय को लेकर सिर्फ एक बार असहमति हुई है, जिसे अब याद करना बहुत मामूली लगता है।

मैं एक ऐसे परिवार में पला-बढ़ा हूं, जो महात्मा गांधी से अधिक नेहरू की प्रशंसा करता था। एक युवा स्कॉलर के रूप में जब मैं भारतीय पर्यावरणवाद पर शोध कर रहा था तो मैंने नेहरू के प्रति अधिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित किया, क्योंकि उनकी सरकार ने आर्थिक विकास के मॉडल को 'आक्रामक' रूप से अपनाया था, भले ही पर्यावरणीय स्थिरता पर इसके परिणाम नकारात्मक हों। यह राजमोहन गांधी ही थे, जिन्होंने मुझे नेहरू को बुराई का प्रतीक बताने से बचाया, जैसा कि मेरे पर्यावरणवादी मित्र उस समय कर रहे थे। अपनी किताब 'द गुड बोटमैन' में उन्होंने बताया है कि आर्थिक नीति पर मतभेद के बावजूद नेहरू ही गांधी के उत्तराधिकारी थे। महात्मा गांधी के तमाम अनुयायियों के बीच नेहरू ही महात्मा के समावेशी दृष्टिकोण को समझने और उसे व्यवहार में लाने के सबसे उपयुक्त थे। अपने गुरु की तरह भारत के पहले प्रधानमंत्री एक हिंदू थे, जिन पर मुसलमानों ने भरोसा जताया था। वे एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने महिलाओं के समान अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। गांधी जी के निकटतम सहयोगियों सी राजगोपालाचारी, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और वल्लभभाई पटेल किसी में भी नैतिक और राजनीतिक गुणों का यह दुर्लभ संयोजन नहीं था। राजमोहन ने मुझे यह भी बताया कि गांधी जी की हत्या के बाद किस प्रकार नेहरू और पटेल ने अपने व्यक्तिगत मतभेदों को अलग रखते हुए भारत को एकजुट करने का प्रयास किया था। राजमोहन और रामचंद्र गांधी में से रामू को अकेले में या एक बड़े श्रोता समूह के साथ सुनना एक रोमांचक अनुभव होता था। उन्होंने मौखिक परंपरा में ही सबसे अच्छा काम किया। दूसरी ओर, राजमोहन के लेखन में कोई व्यंग्य नहीं है। हालांकि उनके पास अभिलेखों से प्राप्त जानकारी बहुत है।

राजमोहन से देश के बारे में इतना कुछ सीखने के बाद मैं इस लेख को अभिलेखों से प्राप्त एक ऐसी जानकारी के साथ समाप्त करना चाहता हूं, जो शायद ही उनको पता हो। मुझे यह बात वेरियर एल्विन के शोध पत्रों में मिली, जो अंग्रेज से भारतीय बने थे और भारत के जनजातीय लोगों के बड़े विद्वान थे। वह गांधी और नेहरू, दोनों को अच्छी तरह जानते थे। जैसा कि मैंने बताया, राजमोहन के माता-पिता को उनकी शादी की अनुमति देने के लिए उन्हें मनाने में बहुत लंबा समय लगा। आखिरकार जून 1933 में देवदास और लक्ष्मी को पुणे में शादी करने की इजाजत मिल गई। इसके तुरंत बाद गांधी और कांग्रेस द्वारा एक और देशव्यापी सत्याग्रह अभियान शुरू करने की बात होने लगी, जो 1920-22 के असहयोग और 1930-32 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की राह पर चलने वाला था। पुणे में महात्मा के अनुयायियों के एक समूह से मिलने पर वेरियर एल्विन ने उन्हें उदास पाया। एल्विन ने एक दोस्त को लिखा, "खुश केवल देवदास तथा उनकी दुल्हन लक्ष्मी थे और पूरी तरह से जेल न जाने के लिए दृढ़ थे।" आखिरकार, सत्याग्रह नहीं हुआ। देवदास को उनके पिता ने जेल जाने का आदेश नहीं दिया। वे और उनकी पत्नी लक्ष्मी दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद सबसे अलग तरीके से चार प्रतिभाशाली भाई-बहनों को पाला।

आत्मनिर्भरता और अहम के बीच टकराव

एक उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या पिछले महीने उसके पिता द्वारा ही गुड़गांव में कर दी गई। इसने भारत के खेल समुदाय को एक गहरा सदमा पहुंचाया। यह त्रासदी सिर्फ एक परिवार की समस्या नहीं है, बल्कि समाज की उस खतरनाक स्थिति को उजागर करती है, जहां पारंपरिक पितृसत्तात्मक ढांचे और महिलाओं की आधुनिक आकांक्षाएं भयंकर टकराव में हैं।

आईटीएफ डबल्स में 113वें स्थान की खिलाड़ी राधिका यादव खुद की टेनिस अकादमी चलाती थीं। वह नई पीढ़ी की भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती थीं- जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र, पेशेवर रूप से सफल और डिजिटल रूप से जुड़ी हुई हैं। पुलिस जांच के अनुसार, उनके पिता दीपक यादव ने रिश्तेदारों द्वारा उनकी कमाई पर निर्भरता का मजाक उड़ाने और उनके सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को लेकर हुई कहासुनी के बाद उन पर गोली चलाई। यह एक अचानक हुई हिंसा नहीं थी, बल्कि लंबे समय से चल रही उन तनावों का परिणाम था, जो जेंडर, शक्ति और नियंत्रण की व्यापक सामाजिक समस्याओं को दर्शाता है। सामाजिक विज्ञान में इसे 'पितृसत्तात्मक चिंता' कहा जाता है- जब पारंपरिक लिंग पदानुक्रम को भीतर से चुनौती दी जाती है तो मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न होता है। सेंटर फॉर सोशल रिसर्च के शोध के अनुसार, 68 प्रतिशत भारतीय परिवार महिलाओं के कॅरिअर को समर्थन देने और पारंपरिक पारिवारिक संरचना बनाए रखने के बीच तनाव महसूस करते हैं। राधिका का मामला इस विरोधाभास का ही उदाहरण है। उन्हें एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में सराहा गया, लेकिन उनके पिता उनकी आर्थिक स्वतंत्रता से अपमानित महसूस करते थे। यह मनोवैज्ञानिक दबाव अंततः विस्फोटक होता है, जब अपेक्षाएं वास्तविकता से टकराती हैं। राधिका की टेनिस अकादमी की स्थापना केवल पेशेवर उपलब्धि नहीं थी, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक भी थी। भारतीय समाज में महिलाओं की आर्थिक निर्भरता नियंत्रण का साधन रही है और उनकी यह स्वतंत्रता परिवार के मौलिक शक्ति संतुलन को चुनौती देती है। 2024 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 37 प्रतिशत तक बढ़ी है, लेकिन परिवारों में महिलाओं को प्राथमिक कमाने वाला मानने की स्वीकृति कम ही है। दीपक यादव की अपनी बेटी पर आर्थिक निर्भरता को लेकर जो शर्म महसूस हुई, वह व्यापक सामाजिक असमंजस को दर्शाती है।

रुचि खन्ना

खुला आकाश

राधिका का मामला विरोधाभास का सटीक उदाहरण है। उन्हें एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में सराहा गया, लेकिन उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया गया। उन्हें सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन सार्वजनिक छवि के लिए उनकी आलोचना भी हुई।

भारत निर्वाचन आयोग लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा इंगित की गई मतदाता सूची की गंभीर त्रुटियों को लेकर संजीदगी नहीं दिखा रहा। मतलब कि यह संस्थान जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ध्यान दे भारत निर्वाचन आयोग।
अंजलि भारद्वाज, आरटीआई एक्टिविस्ट@AnjaliB_

मुद्दा

भारत डोगरा

सही भावना से अपनाएं स्वदेशी

अमेरिका की टैरिफ संबंधी दादागीरी के दौर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अगस्त को स्वदेशी का आह्वान किया। किसानों और छोटे उद्यमियों के हितों की प्राथमिकता देने की बात की। इस समय वैसे भी बीज और खेती किसानों के मुद्दों पर स्वदेशी और स्वराज की भावना के अनुकूल कदम उठाने की जरूरत बढ़ गई है। अनेक अन्य मुद्दों पर साम्राज्यवादी ताकतों की मनमानी का सामना दृढ़ता से करना भी जरूरी हो गया है।

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अनेक उपनिवेशों के आजाद होने का सिलसिला तेजी से बढ़ा और अगले दो दशकों में छोटे-बड़े कई देशों ने आजाद हवा में सांस ली। इनमें से कुछ देश आजादी के बाद भी औपनिवेशिक इतिहास के बोझ से इतने दबे हुए थे कि विकसित देशों के आश्रित बने रह गए। कुछ हद तक अपनी गलतियों, कुछ हद तक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों, व्यापारगत विषमता और अन्याय के कारण अनेक विकासशील देश विदेशी कर्ज के दलदल में फंसते चले गए। इन देशों को विकसित देशों और उनके द्वारा नियंत्रित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की ऐसी अनेक शर्तें माननी पड़ीं जिनसे वहां के गरीब लोगों को कष्ट सहने पड़े और उनकी आर्थिक संप्रभुता पर चोट पहुंची। विकासशील देशों की सिमटती आजादी को गैट (जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड) वार्ता के उरुग्वे दौर में एक और धक्का लगा। इस बेहद विस्तृत वार्ता का अंत गैट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से हुआ। गैट की अपेक्षा विश्व व्यापार संगठन का कार्य और नियंत्रण क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक है, और इसमें कृषि, निवेश, पेटेंट, बैंक, बीमा, प्रसार माध्यम आदि सम्मिलित हैं।

लगता है जैसे साम्राज्यवाद न केवल जीवित है अपितु उसने अधिक आक्रामक तेवर भी अपना लिया है। उसमें विषमता और शोषण की व्यवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति प्रबल हो चली गई। इस परिस्थिति से जूझने के लिए स्वदेशी की भावना और स्वदेशी आंदोलन के संदेश का विशेष महत्त्व है। वर्तमान संदर्भ में स्वदेशी की भावना का सबसे अनुकूल अर्थ यह है कि जीवन की बुनियादी जरूरतों को लेकर हम यथासंभव स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। यह सिद्धांत राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है, और छोटे ग्रामीण समुदायों पर भी। राष्ट्रीय स्तर पर हमें खाद्यान्न, खाद्य पदार्थों, दवाओं, जरूरी पूंजी वस्तुओं और मशीनों, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए जरूरी शस्त्रों आदि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिए। खनिजों में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हो सकती किंतु इतना तो कर ही सकते हैं कि जिन खनिजों की हमारे यहां कमी है, उनके उपयोग को यथासंभव सीमित रखें। दूसरे शब्दों में विदेशी व्यापार में हम हिस्सा जरूर लेते रहें पर बुनियादी जरूरतों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राथमिकता दें। ऐसा करके ही हम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने न्यायोचित हकों के लिए असरदार संघर्ष कर सकते हैं। स्वदेशी का दूसरा रूप गांव, समुदाय या मुहल्ले के स्तर का है। वास्तव में जब हर गांव और मोहल्ले में स्वदेशी का जोर हो तभी राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी की नीति सफल हो सकती है। गांव-समुदाय, कस्बों और छोटे शहरों में ऐसे प्रयास होने चाहिए कि बुनियादी जरूरतों की यथासंभव पूर्ति स्थानीय उत्पादों से ही हो। इससे अनेक ऐसी दस्तकारियों और अन्य परंपरागत रोजगारों को नया जीवन मिल सकेगा जो उजड़ते जा रहे हैं। शिक्षा और नई तकनीकों का प्रयोग करते हुए भी अनेक रोजगार स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे। यदि इस तरह के प्रयासों का कुछ ही समय में असर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी दिखाई देने लगेगा। आयातित वस्तुओं की मांग कम होगी तो स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ने से बेरोजगारी कम होगी। महानगरों की ओर असहाय पलायन कुछ हद तक रुकेगा। युवा वर्ग को अपनी शिक्षा, कौशल और रुचि के अनुकूल स्वरोजगार मिलने से तकनीकी और उद्यमी क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को आगे आने का मौका पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मिलेगा। हमारे उद्योग और प्रबंधन में जड़ता दूर होगी तथा नई प्रतिभाओं को पर्याप्त अवसर मिलते रहने से इनका स्तर ऊपर उठेगा।

स्वदेशी के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य की बहुत संभावनाएं हैं। किसी भी मुहल्ले या बस्ती से यह कार्य आरंभ हो सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों या विदेशी कर्ज के विरुद्ध नारेबाजी से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। जैसे-जैसे आर्थिक संकट विकट हो रहा है, वैसे-वैसे जनसाधारण को स्वयं भी राहतकारी विकल्पों की तलाश है।

इस स्थिति में यदि उत्साही युवा और अनुभवी बुजुर्ग स्वतंत्रता के संघर्ष के समय के आदर्शों से प्रेरित होकर स्वदेशी के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करें तो निश्चय ही सफलता मिल सकती है। यह पुनीत कार्य ऐसा है जिसमें पूरे समाज को जोड़ कर चलना चाहिए। ऐसे कार्य से सांप्रदायिक सोच को पूरी तरह दूर रखना चाहिए। सांप्रदायिक सोच हमारे समाज को बांटती है। साम्राज्यवाद का सामना करने के लिए पूरे समाज में एकता होनी चाहिए। आपसी भाईचारे और सब धर्मों की एकता के आधार पर ही स्वदेशी जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य का प्रसार निरंतरता से हो सकता है। आज जब खादी और स्वदेशी आंदोलन द्वारा सार्थक भूमिका तलाशने का प्रयास हो रहा है, तो यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि खादी और चरखे का आरंभ महात्मा गांधी ने किस संदर्भ में और किस उद्देश्य से किया था। गांवों के गरीब लोगों की सहायता के लिए वे काफी हद तक आत्मनिर्भर रहने वाली ऐसी व्यवस्था तलाश रहे थे जिसमें साम्राज्यवाद के हमलों और पूंजीवाद में समय-समय पर आने वाले संकटों से अपने को बचा कर हमारे ग्रामवासी बुनियादी जरूरतों के बारे में आश्वस्त हो सकें। लेकिन खादी के बारे में उनकी इस गहरी और व्यापक सोच को स्वतंत्र भारत में मान्यता नहीं मिली। उदाहरण के लिए कागजी तौर पर हथकरघा बुनकरों या हैंडलूम क्षेत्रा के लिए सरकार ने अनेक सुविधाओं की घोषणा की हुई है पर सूत के मामले में उन्हें मिलों पर निर्भर बना कर रखा गया और मिलों द्वारा कभी हथकरघा बुनकरों को संतोषजनक ढंग से सूत उपलब्ध नहीं कराया गया है। बुनकरों के आर्थिक संकट का यह स्थायी कारण बन गया है। खेतों में कपास की उन नई किस्मों विशेषकर जीएम किस्मों को सरकार ने प्रोत्साहित किया है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों के अनुकूल हैं।

इस कारण आत्मनिर्भरता का कार्य अब महात्मा गांधी के समय से भी कठिन हो गया है। खेती, कताई, बुनाई, चरखे और हथकरघे के बीच जो सिलसिला बना हुआ था उसे तोड़ दिया गया है। उसे जोड़ने का कोई प्रयास किए बिना ही सस्ते राजनीतिक लाभ के लिए हथकरघा बुनकरों के लिए छोटी-मोटी सुविधाओं के वादे किए जाते हैं। इन्हें भी प्रायः गलत प्रवृत्ति के लोग लूट ले जाते हैं। इतना ही नहीं, विकेंद्रीकरण के नाम पर बहुत से लाभ तो पावरलूम क्षेत्र ने हथिया लिए हैं जबकि पावरलूम क्षेत्र का अत्यधिक उपयोग मिल मालिक अपने माल के उत्पादन के लिए कर रहे हैं। बस, अपनी मिल का ठप्पा लगा कर इस माल को बाजार में बेच देते हैं। सबक सीखते हुए स्वदेशी को सही भावना से अपनाना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में भी जनसाधरण की आजीविका से जुड़े अनेक सवाल उठते रहते हैं जिनमें महात्मा गांधी के विचार बेहद प्रासंगिक हैं, और जहां इन विचारों के आधार पर आजीविका को बचाने के प्रयास किए जा सकते हैं।

लगता है जैसे साम्राज्यवाद न केवल जीवित है अपितु उसने अधिक आक्रामक तेवर भी अपना लिया है। इस परिस्थिति से जूझने के लिए स्वदेशी की भावना और स्वदेशी आंदोलन के संदेश का विशेष महत्त्व है। वर्तमान संदर्भ में स्वदेशी की भावना का सबसे अनुकूल अर्थ यह है कि जीवन की बुनियादी जरूरतों को लेकर हम यथासंभव स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। यह सिद्धांत राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है, और छोटे ग्रामीण समुदायों पर भी। राष्ट्रीय स्तर पर हमें खाद्यान्न, खाद्य पदार्थों, दवाओं, जरूरी पूंजी वस्तुओं और मशीनों, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए जरूरी शस्त्रों आदि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिए। खनिजों में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हो सकती किंतु इतना तो कर ही सकते हैं कि जिन खनिजों की हमारे यहां कमी है, उनके उपयोग को यथासंभव सीमित रखें

फास्ट समाज फास्ट खबरें

मीडिया

सुधीश पचौरी

'सुपर फास्ट खबरें', 'फटाफट खबरें', 'दस मिनट सौ खबरें', 'सौ शहर सौ खबरें', 'नौ सेकिंड में खबर', 'पांच मिनट में पचास खबरें' आदि इत्यादि। इनमें 'आपराधिक खबरें' सबसे आगे होती हैं, फिर गली-मुहल्ले और एक्सीडेंट संबंधी खबरें होती हैं, फिर सामाजिक संबंध टूटने-बनने की खबरें होती हैं। कुछ खबरें सेलीब्रिटीज और खेल-खिलाड़ियों से संबंधित होती हैं। हर खबर तेजी से आती, चली जाती है। जब तक आप उसे तसल्ली से देखें, वह निकल जाती है, और उसकी जगह दूसरी, तीसरी आने लगती है।

एंकर भी 'टेली प्रोंप्टर' पर तेजी से रेंगती खबरों को उसी 'स्पीड' से जल्दी-जल्दी बोलते नजर आते/आती हैं जिसके कारण उनके बोले शब्द एक दूसरे में ऐसे घुस जाते हैं कि हम समझ में नहीं पाते कि वे क्या तो बोल रहे हैं...कई 'न्यूज एंकरों' के सही उच्चारण और सही पेशबंदी की बात तो छोड़ ही दें। ये खबरें दो-तीन तरह की होती हैं जो हमारे अखिल भारतीय समाज में रह रहे लोगों के आपसी संबंधों, तनावों व तज्जन्य हिंसा के बारे में बताती हैं। किसी की गाड़ी के जरा से छू जाने पर होते 'रोड रेज', किसी के दरवाजे पर कूड़ा फेंक दिए जाने, 'ईगो' की खातिर किसी भी बात पर लड़ जाना, दुश्मनियां निकालने को लेकर की जाती हिंसा या फिर पार्किंग को लेकर होते झगड़े आदि ऐसी खबरों में प्राथमिकता पाते हैं।

कुछ सीसीटीवी के सीन व कुछ लोगों द्वारा ऐसी घटनाओं के बनाए वीडियो सोशल मीडिया पर छा जाते हैं। बहुत से चैनल उनको वहीं से उठा लेते हैं, और वे 'दिन की जरूरी खबर' बन जाती हैं जबकि कोई नहीं जानता होता कि ऐसी घटनाओं के मूल कारण क्या हैं? बहुत सी खबरें 'फ्री सोर्स' से ली जाती हैं। यह शुक्रवार की ही खबर है कि एक हीरोइन के चचेरे भाई को उसके पड़ोसियों ने छाती में 'सुआ' घोंप कर मार डाला। कारण इतना था कि किसी ने अपनी 'स्कूटी' उसके दरवाजे के आगे खड़ी कर दी थी...सीसीटीवी का फुटेज बताता रहा कि कैसे दो चार लोगों ने उसे गिराया फिर बर्फ तोड़ने वाला सुआ छाती में घुसा कर मारा। मृतक की पत्नी, बहिन, भाई रोते-बिलखते रहे कि हमें न्याय चाहिए...उसे फांसी दो...ऐसी खबरों में सबसे अधिक खबरें उन छोटे शहरों, गांवों की होती हैं, जहां जमीन-जायदाद के विवाद पर, पैसे के लेन-देन पर या किसी की धोखाधड़ी को लेकर अचानक हाय-हत्या हो जाती हैं। कहीं औरतें एक दूसरे को मारती-पीटती नजर आती हैं, कहीं किशोर एक दूसरे को मारते-पीटते नजर आते है...ऐसी खबरें आज के गावों-कस्बों-महानगरों की बदलती तस्वीर दिखाती हैं। थोड़ा-थोड़ा पैसा सब तक पहुंच गया है, 'कमजोर वर्ग' भी कुछ ताकतवर हो गया है। कोई किसी से कम नहीं समझता। जरा-जरा सी बात पर हैसियत की बात हो जाती है और फिर हिंसा से सब कुछ तय होता है। रेप, चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्याएं, जातिगत-धर्मगत हिंसा नये बनते-बिगड़ते समाज की रोज 'खबर' देते हैं।

बढ़ती दिखावटी दुस्साहसिकता, युवाओं में रिस्क लेने की बढ़ती प्रवृत्ति, कुछ अलग दिखने की चाहतें बढ़ी हैं। इसलिए कुछ नये 'एडवेंचर' भी खबर बनाते हैं: कोई रील बनाने वाला किसी बहती नदी के बीच खड़े होकर तेज बहाव की रील बना रहा होता है कि अचानक उसके पैर उखड़ जाते हैं, वह लहरों में समा जाता है, परिवारी रोते रह जाते हैं। कभी कोई तेजी से दौड़ाई जाती कार के बोनट पर खड़े होकर रील बनाते/बनाती हैं, और जरा सी असावधानी में लुढ़क जाते/जाती हैं और हादसे के शिकार हो जाते/जाती हैं...इन दिनों 'रील बनाना' उसी तरह का 'शगल' हो चला है जैसा कुछ बरसों पहले था। युवा अपने कान में 'ईअर फोन' लगाकर गाने सुनते किसी गाड़ी की चपेट में आकर दुघर्टनाग्रस्त हो जाते थे। पुलिस चेतावनी देती रहती कि चलते वक्त कान में 'ईअर फोन' या 'ईअर पॉड' लगाने से बाज आएं लेकिन लोग न मानते। आज उसकी जगह रीलों ने ले ली है। रील बनाना सोशल मीडिया पर तुरंत अमरता पाने का नया खेल है। जरा सी देर में आप 'इंस्टा', 'यूट्यूब' पर छा जाते हैं, लाखों 'व्यू' व 'लाइक्स' मिलते हैं। आप फिल्म निर्माता बन कर कमाई करने लगते हैं...इसके लिए आपको ऐसी रील बनानी होती है जो लोगों के मूड को तुरंत पकड़ ले। इसके लिए कुछ 'मजेदार असामान्य' सीन, हैरतअंगेज' सीन, 'चटपटे सीन', 'पैरोडी' और 'मजेदार मीम' जरूरी हैं। आप जो रील बनाएं वह कुछ 'हट के' और मनोरंजक' हो कि देखते-देखते लोग उस पर 'लट्टू' हो जाएं। ऐसी खबरें समाज के 'स्वास्थ्य' के बारे में भी बहुत कुछ कहती हैं, जिसका अलग से अध्ययन होना चाहिए।

ऐसी खबरें आज के गावों-कस्बों-महानगरों की बदलती तस्वीर दिखाती हैं। थोड़ा-थोड़ा पैसा सब तक पहुंच गया है, 'कमजोर वर्ग' भी कुछ ताकतवर हो गया है। कोई किसी से कम नहीं समझता। जरा-जरा सी बात पर हैसियत की बात हो जाती है और फिर हिंसा से सब कुछ तय होता है

ब्रिक्स की एकजुटता ट्रंप का जवाब

विश्व पटल

गिरीश पांडे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक बार फिर 25 प्रतिशत और टैरिफ लगाकर यानी कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाकर साबित कर दिया है कि वे वाकई भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति से खौफ खाए हैं। यही नहीं, 25 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद जो उन्होंने 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, उसके पीछे का कारण भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना बताया है। हालांकि टैरिफ की नई दरें 27 अगस्त से लागू होंगी लेकिन भारत ने उनकी टैरिफ चुनौती को दबाव की नीति कह कर उनकी ही भाषा में जवाब दे दिया है और अतिरिक्त शुल्क लगाने की अमेरिका की कार्रवाई को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण बताया और कहा कि यह देश अपने हितों की रक्षा के लिए झुकने वाला नहीं है।

असल में अमेरिका को भारत-रूस मैत्री कभी रास नहीं आई। अतीत में भी वह रूस से ऊर्जा और हथियार खरीदने के मसले पर टकराव लेता रहा है। मौजूदा रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत द्वारा अपनाए गए रुख से भी वह नाराज है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट-जीटीआरआई-ने अमेरिका के फैसले को पाखंडपूर्ण बताया है और मॉस्को के साथ व्यापार के संबंध में अपने सहयोगियों और चीन के प्रति वाशिंगटन के चयनात्मक रवैये को उजागर किया है। वास्तव में ट्रंप के इस कदम का कोई तार्किक आधार नहीं है। अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार घाटा चीन से है (.295 अरब, 2024), जिस पर ट्रंप ने एक समय 145% शुल्क लगाया था। लेकिन चीन ने दुर्लभ खनिज की आपूर्ति रोक दी तो ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। अब चीन पर मात्र 30% टैरिफ है, जबकि वह और तुर्की भी रूस से तेल आयात करते हैं। फिर भारत को दंड क्यों? इससे स्पष्ट होता है कि इस बार भारत के साथ ही अन्य ब्रिक्स देशों पर मनमाने टैरिफ लगाने के पीछे ट्रंप की मंशा कुछ और नजर आती है और वह ब्रिक्स+ की बढ़ती ताकत से चिंतित हैं। ट्रंप अपने दूसरे शासनकाल से ही ब्रिक्स+ को धमकी देते आए हैं। ब्रिक्स+जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका संस्थापक सदस्यों के अलावा उसमें जुड़े नये सदस्यों जैसे मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया शामिल हैं। यह संगठन जहां दुनिया की लगभग आधी आबादी के साथ 30% से अधिक वैश्विक जीडीपी को समेटे है और जिसमें भारत और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, वहीं यह वैश्विक दक्षिण का सशक्त मंच भी है, जो ऊर्जा, व्यापार, निवेश, तकनीक और वैकल्पिक वित्तीय ढांचे को भी बढ़ावा देता है। प्राकृतिक संसाधन, विशाल बाजार, भू-राजनीतिक संतुलन और सामूहिक आवाज इसकी प्रमुख ताकत हैं।

ब्रिक्स+ से ट्रंप की चिंता मुख्यतः दो कारणों से है। उनकी पहली चिंता ब्रिक्स+ द्वारा कॉमन करेंसी अपनाने की संभावना को लेकर है जिस बारे में वह ब्रिक्स को धमकी भी दे चुके हैं। दूसरी चिंता ब्रिक्स+ द्वारा अंतरराष्ट्रीय सहयोग, बहुध्रुवीय और समावेशी विश्व व्यवस्था के निर्माण पर बल देने को लेकर है जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन और बहुपक्षीय विकास बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं में व्यापक सुधार के साथ करने के लिए ब्रिक्स के सभी देशों ने आह्वान किया है और यहां ट्रंप को अमेरिकी चौधराहट को बरकरार रखने की चुनौती है।

लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ कदम से ब्रिक्स में जो एकजुटता दिखाई दे रही है, उसे हम भविष्य के लिए शुभ संकेत कह सकते हैं। ब्राजील के साथ ही रूस, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका जिस प्रकार से भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, वह भारत के लिए भी अच्छी खबर कही जा सकती है। चीन ने भारत पर ट्रंप के टैरिफ को 'दबावपूर्ण' और अस्वीकार्य कहा, रूस ने इसे वैश्विक सहयोग रोकने में नाकाम संरक्षणवाद बताया और दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स के भीतर मिल कर इसका जवाब देने पर जोर दिया।

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मास्को यात्रा और उसके बाद पुतिन की निकट भविष्य में भारत यात्रा तथा प्रधानमंत्री मोदी की 31 अगस्त से 1 सितम्बर, 2025 को चीन के टियांजिन में शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं बैठक में भाग लेने से भी भारत-चीन-रूस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता की फिर से शुरुआत हो सकती है। इस प्रकार ब्रिक्स की एकजुटता को शायद ही ट्रंप प्रभावित कर सकें। ऐसा होता है तो यह न केवल ब्रिक्स के लिए, बल्कि संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए हितकर होगा।

ट्रंप के इस टैरिफ कदम से ब्रिक्स में जो एकजुटता दिखाई दे रही है, उसे हम भविष्य के लिए शुभ संकेत कह सकते हैं। ब्राजील के साथ ही रूस, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका जिस प्रकार से भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, वह भारत के लिए भी अच्छी खबर कही जा सकती है। चीन ने भारत पर ट्रंप के टैरिफ को 'दबावपूर्ण' और अस्वीकार्य कहा है

भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्ट तत्वों की घुसपैठ

एसएससी

आदित्य वर्मा

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

2025 में एसएससी के अंतर्गत आयोजित भर्ती परीक्षाओं में व्यापक तकनीकी त्रुटियों, अनुचित प्रबंधन और परीक्षा आयोजन एजेंसी के परिवर्तन जैसे कारणों से देश भर में छात्रों, अभ्यर्थियों व शिक्षकों का आंदोलन तेज हो गया है। छात्र क्रोधित और चिंतित हैं क्योंकि जब वे अपने घर से कई सौ किमी. दूर यात्रा करके परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे तो वहां अचानक नोटिस के बिना परीक्षा बंद कर दी गई। तकनीकी गड़बड़ियों, सिस्टम क्रैश, गलत सेंटर आवंटन और अभद्रता के आरोप भी लगे हैं। आंदोलन का मूल कारण 2025 में एसएससी की परीक्षाओं की तकनीकी और व्यवस्थागत विफलता है, जिसके पीछे सरकार द्वारा परीक्षा आयोजन टीसीएस के वर्षों पुरानी कॉन्ट्रैक्ट को बदल कर नई एजेंसी को सौंपना शामिल है, जो चार राज्यों में पहले से ब्लैकलिस्टेड थी और पहले भी परीक्षा लीक और कोलैप्स की समस्याओं में घिरी रही है।

एसएससी ने जून, 2025 में एआई चालित परीक्षा निर्माण तंत्र के सहयोग से अपनाया जहां पेपर सिर्फ 15 मिनट पहले जारी होंगे, डिजिटल हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन आधारित सुरक्षा है, पर यह तकनीकी सुधार छात्रों के विश्वास को बहाल नहीं कर सका क्योंकि परीक्षा संचालन में सुधार नहीं, बल्कि पूरी संरचना में बदलाव की आवश्यकता है। लेकिन सरकार तमाम बयानों और सुधारों को लेकर भाषणबाजी में उलझी रहती है, लेकिन जमीन पर कोई ठोस बदलाव नहीं कर रही है, जिससे विद्यार्थी आंदोलन की अग्नि में झुलसते चले जा रहे हैं।

छात्रों में मानसिक तनाव, आत्महत्या के मामले और सामाजिक आक्रोश बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी, सरकार की नीतियां बेरोजगारी से निपटने की बजाय निजीकरण को बढ़ावा देती हैं, जिससे यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे और राज्य सेवाओं जैसी परीक्षाएं 'स्थायी सरकारी नौकरी' की एकमात्र उम्मीद बन जाती हैं, और जब वही परीक्षाएं अपारदर्शी और अव्यवस्थित हो जाएं तो युवाओं में क्रोध उग्र हो उठना स्वाभाविक है। हाल में विद्यार्थियों ओर शिक्षकों ने दिल्ली में मार्च निकाला जहां दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक रोका, लाठीचार्ज हुआ-यह लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार पर आघात है।

आंदोलन शैक्षिक संस्थाओं की असफलता का समेकित विरोध है-यह उस जलते हुए विश्वास का धुआं है जो दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश में फैल रहा है। सरकार को समझना होगा कि परीक्षा में धांधली तकनीकी समस्या भर नहीं है, बल्कि संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति है-'समान अवसर का अधिकार' जब बार-बार पेपर लीक, भ्रष्टाचार, और प्रणालीगत लापरवाही के कारण छिनता है, तो यह लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है; यदि इस आंदोलन की अनदेखी की गई तो परिणाम सड़कों पर धरने या सोशल मीडिया ट्रेंड तक सीमित नहीं रहेंगे-यह व्यवस्था के प्रति अविश्वास की ऐसी पीढ़ी को जन्म देगा जो या तो व्यवस्था को तोड़ेगी या उससे विमुख हो जाएगी। वक्त है जब सरकार आश्वासन या समिति गठन से आगे बढ़ कर कठोर निर्णय ले-भर्ती बोर्डों को जवाबदेह बनाना, परीक्षा संचालन को स्वायत्त और पारदर्शी करना, एजेंसी चयन प्रक्रिया में सार्वजनिक भागीदारी और निगरानी लाना, और सबसे महत्वपूर्ण-शिक्षा को प्राथमिकता देना। याद रहे कि एसएससी आंदोलन भारतीय लोकतंत्र की युवा आत्मा की लड़ाई है।

सुनहरे भविष्य की निधि जैव ईंधन

जैव ईंधन दिवस

योगेश कुमार गोयल

पिछले कुछ वर्षों से पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव झेल रही है और जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की संख्या एवं तीव्रता निरंतर बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण हमारा पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ गया है, जिसका असर जीवन के लगभग हर क्षेत्र में स्पष्ट देखने को मिल रहा है।

जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा कारण मनुष्यों द्वारा पारंपरिक जीवाश्म ईंधन का बड़े स्तर पर दोहन किया जाना भी है, जिसका पर्यावरण पर बेहद खतरनाक प्रभाव देखा जा रहा है। यही कारण है कि पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की बजाय अपरंपरागत जीवाश्म ईंधन को इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस की जा रही है, और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्पों के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही प्रति वर्ष 10 अगस्त को 'विश्व जैव ईंधन दिवस' मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का उद्देश्य वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण विकास का समर्थन करने में जैव ईंधन के महत्त्व को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के स्थायी विकल्प के रूप में उजागर करना है। जलवायु परिवर्तन में होती वृद्धि के साथ वैश्विक ऊर्जा खपत पैटर्न में बदलाव अब समय की बड़ी मांग है, इसीलिए जैव ईंधन दिवस के माध्यम से दुनिया भर में लोगों को अक्षय ऊर्जा स्रोतों को गैर-नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन से बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत में विश्व जैव ईंधन दिवस पहली बार अगस्त, 2015 में पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय द्वारा मनाया गया था। दुनिया भर में अब जैव ईंधन को हमारा भविष्य बचाने के लिए उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। दुबई में हुए 'कॉप-28' में 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने और जीवाश्म ईंधन से दूर रहने का आह्वान किया गया था और संयुक्त राष्ट्र जलवायु कॉन्फ्रेंस के इतिहास में ऐसा सुझाव पहली बार दिया गया था। हालांकि यह अलग बात है कि जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से चलन से बाहर करने का इसमें कोई उल्लेख नहीं था। इससे पहले नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर 9 सितम्बर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस' (वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन) की शुरुआत भी की गई थी।

पारंपरिक ईंधन का वैकल्पिक संस्करण जैव ईंधन पर्यावरण को बेहतर बनाता है। जैव ईंधन ऊर्जा का नवीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय स्रोत होता है, जो नवीकरणीय संसाधनों से बनता है, और जीवाश्म डीजल की तुलना में अपेक्षाकृत कम ज्वलनशील है। यह कृषि अपशिष्ट अथवा पेड़-पौधों और फसलों, वनस्पति, पशु अपशिष्ट, शैवाल, औद्योगिक अपशिष्ट इत्यादि किसी भी प्रकार की जैविक सामग्री से उत्पन्न हो सकता है, जिसमें काफी बेहतर चिकनाई वाले गुण होते हैं। जहां कोयले अथवा तेल के जलने से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है और ये ईंधन ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा कारण बनते हैं, वहीं जैव ईंधन मानक डीजल की तुलना में कम हानिकारक कार्बन उत्सर्जन का कारण बनता है, और ग्रीनहाउस गैसों के प्रभाव को कम करता है। भारत उन्नत जैव ईंधन क्षेत्र के उत्पादन के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है। अधिकांश पर्यावरणविद् का मानना है कि जहां जीवाश्म ईंधन बहुत कीमती है, वहीं जैव ईंधन सबसे बुद्धिमान ऊर्जा विकल्प है, और जो चीज लागत-प्रभावी, कुशल, टिकाऊ एवं नवीकरणीय हो, वह सदैव बेहतर होती है। भारत में विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन के उपयोग की ओर कदम बढ़ाए जा चुके हैं, जिनमें बायोइथेनॉल, बायोडीजल, ड्रॉप-इन ईंधन, बायो-सीएनजी, उन्नत जैव ईंधन इत्यादि प्रमुख हैं। केंद्र सरकार द्वारा जून, 2018 में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसका लक्ष्य 2030 तक 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण और 5 प्रतिशत बायोडीजल मिश्रण के लक्ष्य तक पहुंचना है। यह योजना उन्नत जैव ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। बहरहाल, दुनियाभर में जैव ईंधन का उपयोग बढ़ाए जाने के कई प्रमुख लाभ हो सकते हैं, जैसे इससे कच्चे तेल पर निर्भरता कम होने से जहां पर्यावरण में अपेक्षित सुधार होने की प्रबल संभावनाएं हैं, वहीं इससे खासकर ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऊर्जा पहुंचाई जा सकेगी। परिवहन ईंधन की बढ़ती मांग को भी आसानी से पूरा किया जा सकेगा। इस समय वाहनों के लिए उपयोग होने वाले पारंपरिक ईंधन और प्राकृतिक गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, और आने वाले समय में इनके दाम और बढ़ेंगे।

ऐसे में जैव ईंधन को बढ़ावा देना समय की मांग है क्योंकि ये ईंधन अन्य ईंधन की तुलना में न केवल सस्ते हैं, बल्कि ऊर्जा के अच्छे स्रोत भी हैं, जो प्रदूषण भी नहीं फैलाते। चूंकि जैव ईंधन नवीकरणीय बायोमास संसाधनों के माध्यम से बनाए जाते हैं, इसलिए इनके उपयोग को बढ़ावा देने से पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है। जैव ईंधन समाज के बड़े हिस्से के लिए आय और रोजगार पैदा करने में भी मदद कर सकता है। माना जा रहा है कि जैव ईंधन पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर इस सदी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद करेगा।

अधिकांश पर्यावरणविद् का मानना है कि जहां जीवाश्म ईंधन बहुत कीमती है, वहीं जैव ईंधन सबसे बुद्धिमान ऊर्जा विकल्प है, और जो चीज लागत-प्रभावी, कुशल, टिकाऊ एवं नवीकरणीय हो, वह सदैव बेहतर होती है। भारत में विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन के उपयोग की ओर कदम बढ़ाए जा चुके हैं, जिनमें बायोइथेनॉल, बायोडीजल, ड्रॉप-इन ईंधन, बायो-सीएनजी, उन्नत जैव ईंधन इत्यादि प्रमुख हैं। केंद्र सरकार द्वारा जून, 2018 में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसका लक्ष्य 2030 तक 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण और 5 प्रतिशत बायोडीजल मिश्रण के लक्ष्य तक पहुंचना है। यह योजना उन्नत जैव ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 353
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

तंत्र कहता है कि भुक्ति बिना मुक्ति नहीं है। तांत्रिक साधक अपना सर्वस्व 'दिव्य मां' के चरणों में अर्पित कर देता है। वह 'जनशक्ति' है। उन्हीं के प्रताप से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और अग्नि अपने धर्म पर अनवरत हैं।
भावेश भीमानथानी, धर्म मर्मज्ञ@bhavesh_yuj

आस्था

प्रेम प्रकाश

कहीं धाम, कहीं स्तूप

मिथिला की धरती पर माता सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम को नये धज के साथ खड़ा करने का निर्णय राजनीतिक से ज्यादा सांस्कृतिक है। खतरा इस बात का ज्यादा है कि इसे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद संयोजित घटनाक्रम के रूप में लिया जाएगा। पर ऐसा है नहीं, और इसके लिए जरूरी सांस्कृतिक समझ के साथ ही इस पर बात हो अच्छा रहेगा। दरअसल, हिन्दी साहित्य की परंपरा और इतिहास में मागधी के विस्तार और विन्यास के सूत्र खोजते हुए जिस भाषा-बोली के साथ खासा अन्याय हुआ, वह है मैथिली। बंगाल के बाद मिथिला दूसरा ऐसा सांस्कृतिक क्षेत्र है, जिनके बीच सांस्कृतिक रिश्ते तो हैं ही, पर उनका अपना स्वायत्त लोक विस्तार भी है।

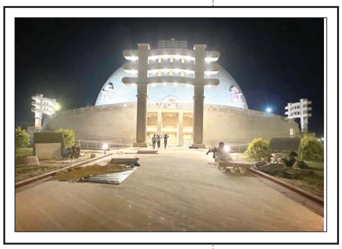

पुनौराधाम और मिथिला

सीता इसी मिथिला की बेटी है, लोक माता है। अवध ही नहीं, बल्कि उसके प्रभाव का पूरा क्षेत्र भी एक हो जाए तो भी सीता और राम के विवाह की झांकी और इसके बीच स्त्री संवेदना का जो गेय-विस्तार मिथिला की लोक भाषा और परंपरा में है, वह असाधारण है। लिहाजा, पुनौराधाम के साथ मिथिला में पल रही आस्था और परंपरा को मिला राजकीय समर्थन अहम है। सत्ता और राजनीति अगर सांस्कृतिक विवेक से लैस हो तो यह स्वागतयोग्य है। कल को इतिहास कह सकता है कि पुरुष सत्ता के सामाजिक-सांस्कृतिक ढांचे के बीच स्त्री संवेदना से जुड़ी आस्था की टेर कमजोर नहीं पड़ी।

भक्ति और आस्था का नया देशकाल

पुनौराधाम की चर्चा के साथ आकार लेते नये देशकाल की करें तो कहना होगा कि यह कलाई पर आस्था और भक्ति का कलेवा बांधे भारतवर्ष का नया देशकाल है। यह विरासत के साथ विकास का साझा विकसित करने वाला भारत है। आजादी के बाद के दशकों में इस देशकाल का वैचारिक अक्षांश और देशांतर किस तरह तय हुआ, वह देखना खासा दिलचस्प है। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि आजादी के बाद खास तौर पर देश में नब्बे के दशक में जब अस्मितावादी राजनीति का जोर बढ़ा तो उसके दूरगामी फलित को समझने में बड़ी चूक हुई। यह राजनीति सामाजिक अन्याय के खिलाफ महज एक प्रतिक्रिया से ज्यादा आज अपने अतीत से बड़ी मुठभेड़ साबित हो रही है। यह मुठभेड़ भारत जैसे देश में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका अतीत सभ्यता के विकास के उत्स तक की यात्रा कराता है।

आज अगर अपनी पहचान और गौरव की ललक देश-समाज में बढ़ी है, तो इसका प्रतिबिंबन सरकारों के विवेक में भी दिखता है। पूरे प्रदेश को छोड़ अकेले पटना की बात करें तो विरासत से विकास का साझा हर जगह बदलाव के नये स्थापत्य के रूप में खड़ा दिखता है। सभ्यता द्वार, ज्ञान भवन, बापू टावर से लेकर नवनिर्मित बिहार संग्रहालय तक हर जगह बिहार अपने स्व की पहचान के साथ अपने सांस्कृतिक वैभव को नये सिरे से लोगों के सामने रख रहा है।

बौद्ध कालीन विरासत और स्मृति

स्वाधीन भारत को अशोक स्तंभ के रूप में उसका गौरव प्रतीक देने वाले बिहार के वैशाली जनपद में बौद्धकालीन विरासत और ऐतिहासिक स्मृतियों को नये सिरे से संजोया जा रहा है। वहां भव्यता के साथ बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप का निर्माण हुआ है, जहां भगवान बुद्ध का पावन अस्थि कलश स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे उन्होंने बेहद दिली लगाव के साथ पूरा कराया है। इसी तरह वे नये बने बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले निर्माणाधीन हेरिटेज टनल को लेकर भी खासे उत्साहित हैं। डेढ़ किलोमीटर का यह अंडरग्राउंड टनल अपने आर्टिफैक्ट को लेकर लगातार चर्चा में बना हुआ है। दरअसल, यह देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में पहली बार होगा जब कोई क्षेत्र अपने अतीत के वैभव को लेकर इस तरह की जागृति का परिचय दे रहा हो। खास तौर पर ऐसी जागृति अगर बिहार जैसे सूबे में दिख रही है, तो यह देश में विकास और नवनिर्माण को नये सिरे से परिभाषित कर रही है। निश्चित तौर पर यह परिभाषा रातोंरात नहीं गढ़ी गई है। बीते दो दशक की राजनीतिक स्थिरता ने इसमें विशेष रूप से बड़ी और निर्णायक भूमिका निभाई है।

विरासत और आस्था के दीये

बिहार में विकास और विरासत से जुड़े इन उदाहरणों का फलक बड़ा है, और इससे इतिहास बोध को लेकर विमर्श के कई मुहाने एक साथ खुलते हैं। इसमें जो बात गौर करने की है कि बिहार में यह सब बगैर किसी धार्मिक क्लेश और तनाव के संपन्न हो रहा है। यहां तक कि पुनौराधाम में मां जानकी के मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण भी सद्भाव और शांति के माहौल के बीच हो रहा है। काशी और अयोध्या के बीते कुछ वर्षों के घटनाक्रम के बीच विरासत और आस्था के दीये हाथ में लेकर चलता बिहार आज अपनी धज और विवेक को नये सिरे से संयोजित और संगठित कर रहा है।

गौरतलब है कि मौजूदा सदी के दो-ढाई दशक में देश में जिस तरह की राजनीतिक-सामाजिक स्थिति बनी है, उससे अतीत और इतिहास की मिट्टी पलटते हुए अपनी पहचान को सुदृढ़ देखने की मनोदशा स्वाभाविकता में तब्दील हुई है। ऐसे में इतिहास लेखन और इतिहास दृष्टि को लेकर बात भी नये सिरे से करने की जरूरत है। सवाल है कि इतिहास के पुर्नेखन और साक्ष्यों के पुनर्परीक्षण के जरिए हम अपने अतीत बोध को किसी नये वैकल्पिक सांचे में गढ़ रहे हैं, या औपनिवेशिक मानसिकता से लैस लीक पर ही आगे बढ़ रहे हैं। यह भी कि इतिहास लेखन में व्यक्तिपरक दृष्टिकोण की आशंका बनी रहती है।

राम, कृष्ण और शिव

इतिहास लेखन और उसके बोध को लेकर कई तरह की स्फीति और भ्रम की स्थितियों के बीच बात वर्तमान चिंताओं की करें तो आज हम पूर्व के अन्याय और ज्यादतियों से निकलने की बजाय उसकी छाया में खड़े होकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। यह निहायत बचकानी स्थिति है। दरअसल, अपने इतिहास में अपने 'स्व' की खोज के लिए हमें ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। डॉ. राम मनोहर लोहिया का प्रसिद्ध निबंध है-राम, कृष्ण और शिव। इस समाजवादी पुरोधा ने बहुत पहले देख और समझ लिया था कि भारत की अस्मिता, उसका तेज, उसका पुरुषार्थ आस्था की सघन परंपराओं के बीच जीवित रहा है। लिहाजा, नये दौर के संकटों के बीच भी अगर भारत के इसी सांस्कृतिक स्थापत्य और निर्मिति को महत्त्व देना होगा। ■

रिश्तों को दागदार करते लोग

जब तक देश में संयुक्त परिवारों का चलन रहा तब तक भारतीय संस्कृति और संस्कारों पर चोट नहीं थी। कभी-कभार अनैतिक रिश्तों की खबर सुनने को मिलती थी। भारतीय संस्कारों का तब से ह्रास होने लगा जब से एकल परिवारों का चलन शुरू हुआ। इसके साथ ही मनमानी का दौर भी शुरू हुआ। मर्यादाएं टूटने लगीं, रिश्ते तार-तार होने लगे और संस्कार मृत अवस्था को प्राप्त होने लगे। रिश्तों को लोग दागदार करने लगे।
पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी से संभोग कर लिया था तो इस बात की सजा उन्हें आज तक दी जा रही है। पूरे देश में ब्रह्मा का मंदिर शायद ही कहीं हो। पूरी दुनिया में ओडिपस नामक व्यक्ति ने अनजाने में अपनी मां जोकास्टा को अपनी रानी बना लिया था। जिस दिन ओडिपस को पता चला कि जो कास्टा उसकी मां है, उसी दिन उसने आत्महत्या कर ली थी। यह बात यूनान की कथाओं में मिलती है। ओडिपस यूनान का था। आज अनैतिक कार्य के लिए दुनियाभर में ओडिपस का नाम किया जाता है। हमारे देश में भी अनैतिकता और दागदार रिश्तों का चलन खूब बढ़ रहा है।

फेसबुक पर ऐसे मर्यादाहीन रिश्तों की बाढ़ सी आई हुई है। उसकी कुछ बानगी देखिए। फेसबुक के अनुसार बिहार में गोपालगंज के पुलकित मिश्रा ने अपनी बहन रागिनी मिश्रा से शादी कर ली। उप्र में अलीगढ़ के एक गांव में होने जा रही सास अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई। महिला का आरोप है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता था, इसलिए दामाद के साथ भाग आई हूं। बिहार में सीतामढ़ी जिले के सैदपुर गांव में छोटू नामक युवक ने अपने चाचा की जान ले ली उसके बाद चाची से शादी कर ली। चाचा की तीन महीने पहले ही शादी हुई थी। बताया जाता है कि उप्र के देवरिया में दो सगे भाइयों ने बहन से शादी कर ली। युवती सोना देवी का कहना है कि उसे दोनों भाई बहुत प्यार करते हैं। इस खबर में जगह का नाम नहीं दिया गया कि एक युवती ने अपने जेठ से शादी कर ली। युवती का कहना है कि जेठ उसे बहुत प्यार करता है, और मैं भी उसे बहुत चाहती हूं। बिहार के हाजीपुर में 20 वर्षीय नन्दू ने अपनी 44 साल की चाची से शादी कर ली। बचपन से वह चाची के पास ही रहता था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे चाची अच्छी लगने लगी। फेसबुक के अनुसार ही बिहार के कटिहार में सूरज अक्सर नानी के घर जाया करता था। इसी बीच उसके अपनी छोटी मौसी से संबंध बन गए। आखिर में दोनों ने भाग कर मंदिर में शादी कर ली। घटना बिहार के सिवान की बताई जाती है, जहां एक बुजुर्ग बबलू यादव ने पुत्र की चाह में दूर के रिश्ते में भांजी लगने वाली 33 वर्षीय युवती से शादी कर ली।
उप्र के मऊ जिले में सोनू की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि तीन बच्चों की मां सीमा ने अपने 55 वर्षीय ससुर से शादी कर ली। दूसरी घटना वैशाली जिले की बताई जा रही है। बेटे ने खुदकुशी कर ली तो सोनिया नामक महिला ने अपने ससुर से शादी कर ली। बिहार के अररिया में चार बच्चों की मां ने भाग कर अपने युवा भांजे से शादी कर ली। उप्र के बलिया जिले में एक सरपंच की बेटी अनीता अपने चाचा अनिल के साथ साइकिल सीखने जाती थी। वहीं दोनों में प्यार पनपा और दोनों चाचा-भतीजी ने शादी कर ली। यह मामला उप्र के अमरोहा का बताया जाता है। 57 साल के सुशील पंडित के संबंध अपनी बहू से बन गए। जब यह बात बेटे को पता चली तो उसने इसका विरोध किया तो ससुर और बहू ने मिल कर बेटे की जान ले ली। यह खबर बिहार के बेगूसराय की बताई जाती है। जहां 70 साल के जीवन प्रसाद ने 23 वर्षीय युवती कांता से शादी कर ली। सुहागरात के बाद ही कांता जीवन प्रसाद के बेटे के साथ भाग गई। बिहार के औरंगाबाद में शादी के 45 दिन बाद गुंजा सिंह ने अपने फूफा जीवन सिंह के साथ मिल कर अपने पति की हत्या कर दी। जीवन सिंह और गुंजा सिंह के बीच संबंध बन गए थे। बिहार के लखीसराय में 67 वर्षीय रामप्रकाश ने 29 साल की पोती से शादी कर ली। सलोनी राय प्रकाश के यहां ही पली-बढ़ी थी। 45 वर्षीय महिला अपने 20-22 साल के बेटे के साथ खड़ी है, और कह रही है कि आज से यही मेरा पति है। यूट्यूबर ने जब संस्कारों की बात कही तो वह उखड़ गई। बोली मुझे पति का सुख चाहिए, जो मेरा बेटा देगा। आज से मैं इसकी पत्नी हूं। फेसबुक पर घटना का स्थान नहीं बताया। बिहार के ही दरभंगा में श्याम नामक युवक ने अपनी सगी बहन से शादी कर ली। एक घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर की बताई जा रही है, जहां दोनों सगे भाई-बहन ने भाग कर शादी कर ली। एक 70 वर्षीय प्रोफेसर ने 19 वर्षीय छात्रा से शादी कर ली। इन्होंने बिहार के मटुकनाथ की याद ताजा कर दी, जिन्होंने 21 वर्षीय छात्रा जूली के साथ शादी कर ली थी। पश्चिमी बंगाल के कॉलेज की प्रोफेसर ने अपने छात्र के साथ शादी कर ली। प्रोफेसर का कहना है कि वह इस छात्र के बिना नहीं रह सकती।

फेसबुक पर ऐसे मर्यादाहीन और समाज को अस्वीकार रिश्तों की बाढ़ सी आई हुई है। सवाल यह है कि ऐसे रिश्तों पर हायतौबा क्यों नहीं मचती। ऐसे रिश्ते बनाने वालों का बायकाट क्यों नहीं किया जाता? हम मूकदर्शक क्यों बने रहते हैं? हमने अपने बचाव के लिए एक शब्द ढूंढ रखा है 'हमें क्या लेना जो करेगा सो भरेगा'। सवाल है कि उसने समाज के नियमों को तोड़ा और आप उम्मीद करते हैं कि उसे सजा भगवान दे। क्या हमारा यह कर्त्तव्य नहीं है कि हम उसका तिरस्कार करें। कुछ लोग इन घटनाओं को अफवाह मान सकते हैं। लेकिन अफवाह भी तो समाज के लिए घातक होती है। हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी ही होगी।

प्रस्तुति : चांद खां रहमानी ■

व्यंग्य | विनोद कुमार विक्की

यारी ऐसी कीजै, ज्यों नर मोबाइल साथ

वैवाहिक कार्यक्रम में जीजा या फूफा, सरकारी योजनाओं में गबन एवं सब्जी में नमक की तरह मानव जीवन में मित्र की उपस्थिति अपरिहार्य है। त्रेता युग के राम-सुग्रीव, द्वापर युग के सुदामा-कृष्ण, कर्ण- दुर्योधन, मुगलकालीन अकबर-बीरबल से लेकर बॉलीवुड के जय-वीरू तक की मित्रता के कई किस्से हमें देखने और सुनने को मिल जाती है, किंतु किसी भी युग में हमें जल और मछली वाली मैत्री संबंध का एक भी उदाहरण देखने को नहीं मिला।

कहा गया है कि 'यारी ऐसी कीजै, ज्यों मछली जल साथ। जल बिन मछली तड़प के, मर जावे दिन रात।' यद्यपि कलयुग के पूर्वार्द्ध में इस दोहे में आंशिक परिवर्तन हुआ है, जिससे मित्रता के मायने बदल गए हैं। 'यारी ऐसी कीजै, ज्यों नर मोबाइल साथ। मानव बिन मोबाइल तड़प के, मर जावे दिन रात।' कलयुगी मित्र के रूप में मोबाइल ने मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क में वह स्थान प्राप्त कर लिया है, जो देवलोक में इंद्रदेव और ससुराल में दामाद अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। इंसान भले ही स्मार्ट नहीं हो लेकिन उसका तकनीकी मित्र अर्थात मोबाइल फोन अवश्य ही स्मार्ट होता है। प्रत्येक क्षण देवालय से शौचालय, कार्यालय से औषधालय, ट्रेन से प्लेन, श्मशान से मकान तक हर शुद्ध-अशुद्ध, सुगम-दुर्गम स्थल पर मनुष्यों का साथ निभाने वाला पवित्र मित्र के रूप में मोबाइल फोन ने खास जगह बना ली है। सुबह आंख खुलने से देर रात आंख लगने तक अथवा फुल बैट्री से बैट्री डिस्चार्ज होने तक सच्चे दोस्त की तरह मोबाइल सदैव मनुष्य के साथ रहता है। देर रात घुप्प अंधेरे में बिछावन पर जब परछाई भी मनुष्य के साथ नहीं होती, तो उसका यशस्वी मित्र मोबाइल फेस टू फेस रहता है। मित्रता निभाने में मोबाइल न तो उम्र की सीमा देखता है और न ही पेशा अथवा जाति। कार्टून वीडियो देख कर दुग्धपान करने वाले नौनिहालों, ऑनलाइन कक्षा करने वाले छात्रों, सरकारी-गैर सरकारी कर्मचारियों अथवा मनोरंजन प्राप्त करने वाले निठल्ले-बेरोजगारों के साथ एक जैसा आचरण करता है। इंसानी फितरत से दूर मोबाइल नर-मादा के बीच लिंगभेद भी नहीं करता। रील्स बनाने से लेकर रसोई में यूट्यूब प्रेरित रैसिपी बनाने में यह महिलाओं का सच्चा साथी है।

मोबाइल नहीं रूठने वाला ब्रह्मांड का सबसे भरोसेमंद मित्र है। थोड़ी सी अन-बन होने पर मानव मित्र कहीं भी चुगली या राजफाश कर सकता है, लेकिन क्रोधवश जमीन पर पटके जाने के बाद भी पासवर्ड लगा मोबाइल मनुष्यों की निजता को अपने अंदर ही समाहित रखता है।

गीता का ज्ञान देने के लिए श्रीकृष्ण को महाभारत युद्ध का इंतजार करना पड़ा था लेकिन डाटा पैक की उपलब्धता मात्र से ही व्हाट्सएप और यूट्यूब के द्वारा मोबाइल में हर समय दुर्लभ ज्ञान प्रसारित होता रहता है। यह और बात है कि अधिकांश दिव्य ज्ञान वेद शास्त्र और पुस्तकों में भी वर्णित नहीं होता। बहरहाल, भविष्य में टैरिफ बिन ट्रंप, कुर्सी बिन नेता, भ्रष्टाचार बिन कर्मचारी, श्रृंगार बिन स्त्री की कल्पना तो की जा सकती है, लेकिन मोबाइल बिन मानव जाति का अस्तित्व आलू से सोना बनाने जितना मुश्किल है। ■

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

राग रंग | आलोक पराड़कर

नाटक की आदत बनाता विंडरमेयर

मुंबई और दिल्ली जैसे नगरों को छोड़ दें तो ज्यादातर नगरों में हिन्दी रंगमंच आज भी शौकिया ही है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारतेंदु नाट्य अकादमी, मप्र नाट्य विद्यालय सहित देश में रंगमंच सिखाने के कई संस्थान हैं, विश्वविद्यालयों में भी विभाग हैं, लेकिन पेशेवर रूप में रंगमंच कर पाना और नाटक करके खर्च निकाल पाना छोटे-छोटे शहरों में आज भी मुश्किल काम है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और बिहार की राजधानी पटना जैसे नगरों में भी कुछेक आयोजनों को छोड़ दें तो नाटकों के लिए टिकट बेच पाना नाट्य संस्थाओं के लिए टेढ़ी खीर है। लोग मल्टीप्लेक्सों में जाकर हजार-दो हजार खर्च कर लेते हैं, तीन -चार सौ रुपये के पॉपकार्न खरीद लेते हैं, लेकिन नाटकों के लिए सौ-दो सौ रुपये का टिकट खरीदना उनके लिए भारी हो जाता है। वास्तव में हम लोगों को टिकट खरीद कर नाटक देखने की आदत ही नहीं डाल सके हैं। इसके लिए कई बार फिल्म कलाकारों को शामिल करने की जुगत लगानी पड़ती है लेकिन फिर नाटकों का खर्च भी बढ़ जाता है। सभागारों और पूर्वाभ्यास कक्षों का किराया पहले से ही काफी अधिक है।

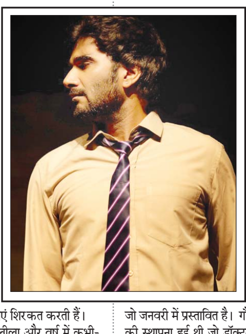

प्रसन्नता की बात है कि कुछ नगरों में रंगकर्म को पेशेवर बनाने की गंभीर पहल दिख रही है। बरेली ऐसे ही चंद नगरों में है। यह पहल यहां इसलिए भी अधिक महत्त्वपूर्ण है कि यह निजी प्रयासों से हो रही है, और इसमें किसी अनुदान या प्रायोजक की सहायता शामिल नहीं है। बरेली के आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह और उनके विंडरमेयर ने अपनी गतिविधियों से पहले ही रंगकर्मियों और रंगप्रेमियों का ध्यान आकृष्ट किया है। उसके नाट्य समारोह, जो इस वर्ष से प्रतियोगितात्मक हो चुका है, में देश भर से नाट्य संस्थाएं शिरकत करती हैं।

विंडरमेयर में नाट्य समारोह के अतिरिक्त रामलीला और वर्ष में कभी-कभार नाट्य प्रस्तुतियां होती रही हैं, लेकिन अब यह ऐसे स्थल के रूप में बदल चुका है, जहां नाट्य मंचन की निरंतरता कायम हुई है, और इसके कारण शहर के रंगप्रेमियों में नाटक देखने की आदत विकसित हुई है। देश भर की नाट्य संस्थाएं यहां आने को उत्सुक हैं, लगातार नाट्य प्रस्तुतियां हो रही हैं, और दर्शक टिकट लेकर नाटक का अवलोकन कर रहे हैं। विंडरमेयर थिएटर में हालिया प्रस्तुतियों पर नजर डालें तो पता चलता है कि किस प्रकार बरेली के रंगप्रेमियों ने चर्चित नाट्य प्रस्तुतियों का आस्वाद किया है। 3 अगस्त को मुंबई की डी फॉर ड्रामा नाट्य संस्था ने निहाल पराशर के निर्देशन में 'पटना का सुपर हीरो' का मंचन किया। विंडरमेयर की अपनी नाट्य संस्था 'रंग विनायक' ने 26 एवं 27 जुलाई को लेखक-निर्देशक राकेश श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 'खामोश अदालत जारी है' प्रस्तुत किया। उजागर ड्रामेटिक असोसिएशन द्वारा 22 जून को मोहित टाकलकर के निर्देशन में 'हुंकारो' किया गया। 14 एवं 15 जून को 'डोंट फियर भरत मुनि इज हियर' की प्रस्तुति हुई जिसे रंगकर्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए विंडरमेयर अनुदान के तहत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जुड़े कलाकारों ने किया था। अब 10 अगस्त को दानिश इकबाल 'बुनकर' करने आ रहे हैं। किसी शहर में रंगकर्म की आदत बनाने के लिए नाटकों की निरंतरता जरूरी होती है। विंडरमेयर इसे कायम करने में सफल हो सका है। डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह कहते हैं, 'हम सौ से डेढ़ सौ टिकट बेचते हैं। टिकट दर तीन सौ से पांच सौ रुपये तक होती है। हमने करीब पांच सौ ऐसे रंगप्रेमियों की पहचान की है, जो विंडरमेयर की प्रस्तुतियों के लिए उत्सुक होते हैं। इस प्रकार अब नगर में टिकट लेकर नाटक देखने की आदत बन चली है। देश भर से नाट्य संस्थाएं विंडरमेयर में प्रस्तुति के लिए हमसे संपर्क करती हैं।' सितम्बर में रामलीला के साथ ही कई दूसरे नाटकों की प्रस्तुतियां होनी हैं, अक्टूबर में संहिता मंच का नाट्य समारोह है। विंडरमेयर चर्चित नाट्य संस्था आदिशक्ति के साथ रंगमंच की कार्यशाला और तीन नाटकों के समारोह की योजना पर भी कार्य कर रहा है, जो जनवरी में प्रस्तावित है। गौरतलब है कि 2013 में इस अत्याधुनिक सभागार की स्थापना हुई थी जो डॉक्टर सिंह के घर की दूसरी और तीसरी मंजिल पर अवस्थित है। इस ब्लैक बॉक्स थिएटर में करीब दो सौ लोगों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन कई बार यह संख्या काफी बढ़ जाती है। डॉक्टर सिंह अपने अस्पताल की ओपीडी और सर्जरी की व्यस्तताओं के बीच रंगकर्म के लिए तन-मन-धन की कोई कमी नहीं होने देते। विंडरमेयर में प्रस्तुति के साथ ही रंगकर्मियों को उनका स्नेह और आतिथ्य भी हमेशा याद रहता है। ■

कैनवस | जय त्रिपाठी

'कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेमोक्रेसी' विशेष दृष्टि

जातिवादी सोच हमारे बोध को संकटग्रस्त बनाती है खासकर वर्तमान में उपस्थित अतीत का विश्लेषण करते समय। कारण यह है कि हम अपने हितों और परिस्थितियों के अनुसार ही दुनिया को देखते हैं। इस वैचारिकी सोच-समझ से जब हम अनीता दुबे द्वारा क्यूरेट इस प्रदर्शनी देखते हैं तो समभाव का एक स्पष्ट स्वरूप दिखाई देता है। और हो भी क्यों न? पूर्व से वर्तमान की प्रगतिशील सोच से भी देखें तो आज भी हम उस सामाजिक व्यवस्था को साकार किए हुए हैं, जो सदियों से चली आ रही है। नई दिल्ली स्थित आर्ट हेरिटेज गैलरी में देश की सुप्रसिद्ध वैचारिक कलाकार एवं क्युरेटर अनीता द्वारा क्यूरेट 'कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेमोक्रेसी-2' शीर्षक से प्रदर्शित प्रदर्शनी सामाजिक विकास की भ्रांतिपूर्ण अवधारणा को प्रस्तुत करती है।

सत्य को उसके वस्तुगत स्वरूप में देखने वाले कबीर भी इस सामाजिक ढांचे को जातिगत भावना से ऊपर की बात कर इस जड़ता को समाप्त करने का संदेश देते हुए कह गए कि 'जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान।' आज इक्कीसवीं सदी में भी हम यह समझ न पाए या हो सकता है कि समझ कर भी नासमझ बने हुए हैं, लेकिन अफसोस है कि देश के एक वर्ग (राजनीतिक दलों) ने विपरीत अर्थों में इसे बहुत अच्छे से समझा है, और इसकी जड़ों को जमाने के लिए भरपूर खाद-पानी दिया है। कलाकार इनसे ऊपर उठे होते हैं, जो पीड़ा के मर्म को संवेदनशील भावों से रच-गढ़ पाते हैं। संभवतः अपने इसी उद्देश्य से दिल्ली एनसीआर स्थित कलाधाम के कलाकारों की सामूहिक प्रदर्शनी में विविध पृष्ठभूमि के कलाकारों की कलाकृतियों को क्यूरेटर द्वारा संचालित किया गया है।

यह प्रदर्शनी समकालीन समय में कलाकार की सामाजिक-राजनीतिक पहचान के मूल विचार से भी संबंधित है। दीर्घा में कलाधाम के लगभग 30 कलाकारों की कलाकृतियों को देख कर महसूस होता है कि कलाकार अपनी कला से पहचाना जाता है एवं उसकी मूल्यात्मक रचनात्मकता से उसकी उत्तम पहचान बनती है। रचनाकारों की यह बुनियादी शक्ति ही दर्शकों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। एक अंतराल के बाद कला-विमर्श में चेतना की इस नई रोशनी से एक नई आशा की किरण सी जगी है, जो इस आयोजन के साथ कला की दुनिया के सामने आई है।

भारतीय संस्कृति और दुनिया भर में विचलित कर देते भावों को आकार देने वाले विचारों को दर्शाती भारतीय कलाकारों की कृतियों की यह प्रदर्शनी निःसंदेह नया रास्ता तय करती है। यह नई राह दिखाने वाली कला की दुनिया की प्रख्यात चित्रकार, कला समीक्षक अनीता दुबे हैं। जहां तक भारतीय कला का संदर्भ है तो कला की समृद्ध परंपरा रही है। चयनित कलाकृतियों को देख कर यह बात मन में आती है कि ये गंभीर और मूल्यवान कृतियां रचना संसार की किसी भी कलाकृति के साथ तुलनीय हैं। प्रदर्शित पेंटिंग, शिल्प, छापा चित्र (ग्राफिक प्रिंट), छाया चित्र (फोटोग्राफ), विडियो आर्ट तथा इंस्टॉलेशन आदि देख कर समझ आता है कि कृतियों में विविध विधाओं में कई तरह के नये प्रयोग हो रहे हैं।

तेरह सितम्बर तक प्रदर्शित कला प्रदर्शनी समकालीन भारतीय कला में विचार और धारणाएं भी हमारे सामने प्रदर्शित करती है। आज कला अत्यंत सक्षम, उपयोगी एवं विशेष दृष्टि की प्रयोगवादी कला है, और पूरी दुनिया में इसको करने वाले असंख्य कलाकार हैं। समकालीन कलाकार नये-नये प्रयोगों, तरीकों और नई रचनात्मक दृष्टि के साथ द्रुत गति से आगे बढ़ कर रहे हैं, ऐसे में क्यूरेटर द्वारा कई कलाकारों के समूह को एकजुट करके वैचारिक सोच के साथ एक साथ लाना केवल वर्तमान का चिंतन नहीं, बल्कि हमारे हित-अहित से जुड़ कर वह हमारी मनोभावना और दृष्टिकोण का निर्धारण भी करता है। यह संघर्ष परिवर्तन के युग में आशावादी और मानववादी चिंतन को दर्शाता है। अनीता दुबे की कलाधाम के कलात्मक कामों से ली गई प्रेरणा, कलाकारों की जाति, वर्ग, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि को रेखांकित करने का समभाव बहुध्वनि का प्रतिबिंब है। ■